हरियाणा विधान सभा

की कार्यवाही

8 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 8 मार्च, 1994

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)37
सचिव द्वारा घोषणा–	
संविधान (77वां संशोधन) बिधेयक, 1992 से अनुसमर्थन संबंधी	(7)39
विभिन्न विषयों का उठाया जाना.	(7)40
तारांकित प्रश्न संख्या 726 पर अतिरिक्त सूचना देना	(7)44
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
(1) श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री द्वारा	(7)45
(2) राजस्व मन्त्री द्वारा	(7)46
(3) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(7)46
विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(7)47

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का अभिवादन	(7)48
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	(7)48
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	
राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं तथा मनुष्यों के लिए क्रासिंग का उपलब्ध करने तथा राजमार्गो के पास की भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी	(7)51
वक्तव्य–	
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) कच्ची द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी?	(7)52
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(7)53
वर्ष 1994– 95 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)54

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 8 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9– 30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) मै अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Electricity Tubewells in Agricultural Sector

***707. Shri Satbir Singh Radian :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the total number of Tubewells in Agricultural Sector in the State at present;

(b) the total number of Tubewells running having a capacity of 3, 5, 7½ and **10** HP separately; and

(c) the total number of Tubewells out of those as referred to in part (b) above running on fiat rates ?

Power Minister (Shri A. C. Chaudhary)

(a) Ending 12/93, 3,80,388 power run tubewells were functioning in the State.

(b & c) The details are as follows :—

	Total Tubewells	Flat rate Tubewells
3 BHP	64,413	42,300
5 BHP	1,63,820	1,03,318
7.5 BHP	97,297	62,156
10 BHP	34,432	23,538

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय कुल कितने मैगावाट बिजली बनती है और यह जो 3 लाख 80 हजार 388 पावर से ट्यूबवैल्ज चलसे हैं, उनमें कितनी बिजली कृषि क्षेत्र में खर्च हो रही है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, जितनी मोटरें चलेगी, बिजली उतनी कंज्यूम होगी। अब इस बारे में एस्टीमेट करना कि मोटरे कितनी चलती हैं, बड़ा मुश्किल है। आन एन एवरेज 55 परसैन्ट बिजली एग्रीकल्चर सैक्टर को मिनिमम जा रही है। आज के दिन भी ऐसी हालत है। जब पीक लोड था, उस वक्त 65 परसैन्ट को भी क्रौस' कर लिया था। (व्यवधान व शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियानः कुल कितनी बिजली पैदा हो रहे है?

श्री अध्यक्षः इसकी कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल जनरेशन कितनी है?

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब, 55– 55 मैगावाट के तीन यूनिट फरीदाबाद में हैं। इसके अलावा 110– 110 मैगावाट के चार यूनिट और 210 मैगावाट का एक यूनिट पानीपत में है। बाकी जो शेयर है, वह हमें भाखड़ा और यमुना हाईडल प्रोजैक्टस से मिलता है। कुल मिलाकर हमारी अपनी जनरेशन कैपेसिटी तकरीबन 665 मैगावाट की है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं इस बारे में थोड़ा–सा क्लीयर कर दूं। हमारी अपनी स्टेट के अन्दर बिजली आन एन एवरेज एक करोड़ यूनिट एक दिन में बनती है। कभी 90 लाख यूनिट, कभी एक करोड़ 5 लाख यूनिट, कभी एक करोड़ 10 लाख यूनिट बनती है। एक बार एक करोड़ 12 लाख यूनिट भी एक दिन में बनायी गया है। इसके मुकाबले में हमारी जो बिजली की टोटल जरुरत है, वह सारी स्टेट के अन्दर 3 करोड़ यूनिट के लगभग डेली की आवश्यक्ता है। इसमें से हमारे पास कभी 2.90 करोड कभी 2.80, कभी 2.70 करोड़ यूनिट अवेलेबल होती है। आपको पता है कि कई दफा भारत सरकार का भी कोई प्लांट खराब हो जाता है तो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे मन्त्री जी ने बताया है कि हम कृषि क्षेत्र को 55 परसैन्ट से 60 परसैन्ट तक बिजली सप्लाई करते हैं। इस वक्त स्टेट में बिजली के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। किसी जगह पर कोई कट नहीं है। सब जगह पर पूरी बिजली किसानों को मिल रही है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ये स्पष्ट नही कर पा ये हैं कि बिजली की कृषि क्षेत्र को कितनी जरुरत है और कितनी दे पाये हैं जबकि आपके सामने आकड़े हैं। कृषि क्षेत्र में 21 लाल हौर्स पावर के ट्यूबवैल्ज पर डे चलते हैं। इससे मल्टीप्लाई करके आप देख लें कि आप कृषि क्षेत्र को कितनी बिजली दे रहे हैं। यह इन्फर्मेशन आप बतायें, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान व शोर) आप रोज ब्यान देते हो कि कृषि क्षेत्र को 60 परसैंन्ट बिजली दे रहे हो जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक कृषि क्षेत्र पर 20 परसैन्ट से ज्यादा बिजली खर्च नही हौ ग्ही है, आप इस बारे में स्पष्ट करे।

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इनका कहना टोटली निराधार है। इस बारे मैं। मैं, इतना जरुर कहना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० से हम अपने शेयर के अलावा जो सैक्शन्ड है, हमने 60– 60 लाख यूनिट बिजली एक्सट्रा ड्रा की है, ग्रोवर ड्रा की है। ओवर ड्रा हम उसी स्टेट पर करना चाहेंगे जब हमें बिजली की बहुत ज्यादा जरुरत होगी। क्योंकि ओवर ड्रा में आपको पता है कि अगर नार्मल रेट डेढ़ रुपया है तो ओवर ड्रायल के लिये दो रुपया और अढ़ाई पया और तीन रुपया प्रति, यूनिट तक होती है। ऐसी हालत में स्टेट को बहुत बड़ा बोला भुगतना पड़ता है इसलिये हमें रिसोसिज का भी ख्याल रखना पड़ता है। एग्रीकल्चर की जहां पर बात हो, वहां हम इस बात की भी परवाह नही करते, जहां जरूरी होता है, वहां ओवर–ड्रायल भी करते हैं।

कल के रिकार्ड के मुताबिक हमने तकरीबन 40 लाख यूनिट ओवर ड्रा की हैं।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इनके पास ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज लेने के लिये लगभग तीन लाख टैस्ट रिपोर्टस थी, जो अब और ज्यादा हो गयी होंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कुल कितनी टैस्ट रिपोर्टस इनके पास टयूबवैल के कनैक्शन्ज की पैडिंग है और ननको कब तक कनैक्शन दे देंगे?

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है कि तीन, पांच, साढ़े सात और. दस एच ० पो ० के अनह। अलग कितने कनैक्शन्ज ट्यूबवैल्ज के हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अकेले हिसार में ग्यारह हजार के करीब कनैक्शन ऐसे हैं जो दस एच ० पो ० से ज्यादा के हैं। सारे प्रदेश में 3 लाख 8० हजार 3 छ 8 ऐग्रीकल्चर सैक्टर में हैं और इनमें से 3 लाख 59 हजार 982 दस एच० पी ० के हैं, साढ़े सात के, पांच के और तीन एच० पी ० के हैं।

श्री कृष्ण लालः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सैल्फ फाइनैस की जो स्कीम गवर्नमैंट ने चलाई उसके अन्डर कितनी ऐप्लीकेशन्ज आई, उनमें से कितनों को कनैक्शन्ज दे दिए और कितनी ऐप्लीकेशन्ज पैडिंग हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी स्टेट से अलावा हम बाहर से जैसे इन्द्रप्रस्थ, हिमाचल प्रदेश

और एन ० टी० पों ० सी ० से कितनी कितनी बिजली लेते हैं। यानि अलग–लग सोर्स से या प्रदेश से कितनो–कितनी बिजली हम लेते हैं। तीसर मेरा सवाल यह है कि एक मेंगावाट में कितने यूनिट बिजली होती है?

श्री ए ० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, अगर मेरे भाई कीं नीयत सवाल पूछने की होती तो मैं उनके सवाल का जवाब देता लेकिन नीयत सवाल पूछने

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

50.	Hindustan Copper Ltd.	SSP	3
51.	Bharat Chemicals & Fertilizers	"	7
52.	Sweeping material (Unknown)	"	4
53.	Punjab Agro Chemical	"	1
54.	Munak Chemical	"	4
55.	NITIN	"	4
56.	Agro Chemical	"	3
57.	Varindra Agro Chemical	"	1
58.	IFFCO	NPK	87
59.	Hind Fertilizer lad Chemical Ltd.	"	56
60.	Gujarat Narmada Fertilizer Co.	"	38
61.	R.C.F.L.	"	11
62.	Gujarat State Fertilizer Co.	"	12

63.	Sweeping Material (Unknown)	"	17
64.	Haryana Agro Fertilizer & Chemical	"	5
65.	HAFED	"	3
66.	National Fertilizer Ltd.	CAN	49
67.	Gujarat State Fertilizer Co.	ASP	5
68.	Gujarat State Fertilizer Co.	Ammonia Sulphate	1
	Sweeping Material (Unknown)	Do	3
69.	I.P.L.	MOP	41
70.	Gujarat Narmada Valley Fertilizer Co.	Ammonia Chloride	1
	Sweeping Material (Unknown)	Do	1
71	Haryana Agro Chemical, Panchkula	Zinc	19
72.	Sonia Overseas Pvt. Ltd., Panchkula	"	28
73.	Suraj Zinc Pvt. Ltd.	"	5
74.	S.S.R.P.	"	4
75.	Radh a Chemicals, Ambala	"	1
76.	Prabhat Fertilizer	"	85

77.	Jai Shree Agro	"	22
78.	Fattar Micro Nutrient	"	10
79.	Amar Products, Yamunanagar	"	1
80.	Shivalik Chemical	"	2
81.	Kailash Paints & Chemicals	"	9
82.	Shahbad Chemical Work, Chapra	"	5
83.	Parkash Agro Chemical, Rawa	"	6
84.	New Bharat & Chemical	"	2
85.	JyotiChemical & Fertilizer, Samana	"	7
86.	Gee Emm Enterprises	"	15
87.	Mahesh Chemical	"	26
88.	Indoplast Pvt. Ltd., Parwanoo	PP	5
89.	A.C. Pvt. Ltd.	"	1
90.	Pooja Chemical & Fertilizer	"	5
91.	Chandigarh Chemical, Tohana	"	20
92.	Pantnagar Fertilizer	"	3

93.	Shit Chemical	Zinc	1
94.	Jindat Industries	"	5
95.	Reliance Chemical, Shahbad	"	1
96.	Kay Chemical India	"	12
97.	Babbar	"	1
98.	Bhoomi Sudhar Agro industries	"	8
99.	Defence Agro Chemical & Fertilizer	"	2
100.	India Phosphate & Carbonate	"	31
101.	Partap Chemicals	"	5
102.	Luchhma Chemical & Fertilizer	"	1
103.	Randeep Paper Board Mill, Amritsar	"	1
104.	Haryana Agro industries	"	5
105.	Sena Fine Chemical Pvt. Ltd.	"	3
106.	Gandhi Chemical & Fertilizer	"	10
107.	Sweeping Material (Unknown)	"	3
108.	Puneet Chemicals	"	1

109.	Him Chemical & Fertilizer Nalagarh	"	8
110.	Shambhu Nath Chemical Works, Amritsar	"	3
111.	Uttar Bharat Metal Product	"	7
112.	Namdev Chemical & Fertilizer	"	6
113.	Haryana Zinc Pvt. Ltd.	"	I
114.	Pal Chemical & Fertilizer Industries	"	2
115.	Chemicals & Fertilizer Dalyor	"	3
116.	Priya Chemical & Fertilizer Ltd.	"	1
117.	Bharat Chemicals & Allied Industries.	"	1
118.	Rattan Micro Nutrient Pvt. Ltd.	"	I
119.	Suraj Zinc Pvt. Ltd.	"	1
120.	Northern Minerals, Gurgaon	Chelated micronutrient	2
121.	Sweeping Material (Unknown)	TSP	1
		Total	4928

ANNEXURE—II

List of the firms whose samples found non standard and action taken thereon

Sr. No.	Dealer	Manufacturer	Fertilizer	Non-Standard		Action taken
				Request	Other	
1	2	3	4	5	6	7
1.	The Ambala Coop. Marketing Society Ltd., Am bala	KRIBHCO	Urea	1	—	(The fertilizer stocks of sam- pies, which are drawn on request and fo- and non- stan- dard are not sold to the farm ers, but are as Perdispo clseankoff 23 of Fertilizer
2.	State Warehousing Corporation, Barara	Do	"	1	—	
3.	Mohit Agency, Mullana	Shivalik Fertilizer	SSP	I	—	
4.	Kribhco, Yamuna Nagar	KRBIHCO	Urea	1	—	
5.	P.P.C.L. Jagadhri	PPCL	DAP	1	—	
6.	Do	Do	"	1	—	

7.	Agro Chem. Traders	Do	"	1	—	Control Order 1985 i.e. such fertilizers are sold to the manufacturers of mixtures of fertilizers or Research Farms of Govt. or Universities or such bodies after fixing the price on the basis of the nutrient value found as per repport. ort sis The
8.	Lalit Kumar Naresh Kumar, Yamuna Nagar	Khaitan	SSP	1	—	
9.	IFFCO, Yamuna Nagar	IFFCO	Urea	3	—	
10.	Cheema Fertilizer Rasulpur	India Cerials	SSP	1	—	
11.	State Warehouse, Kurukshetra	KRIBHCO	Urea	2	—	
12.	Coop. Mktg. Society, Shahbad	Do	"	1	—	

						price of such fertilizer is reduced pro-portionately)
13.	Central Coop. Bank Kurukshetra	Sweeping Material	MOP	1	—	
14.	Do	Do	Urea	1	—	
15.	Do	Do	CAN	1	—	
16.	Do	Do	SSP	1	—	
17.	Do	Do	NPK	1	—	
18.	Do	Do	"	1	—	
19.	Do	Do	TSP	1	—	
20.	Do	Do	Urea	1	—	
21.	Central Cb-operative Bank, Kurukshetra	Sweeping Material	Urea	1	—	
22.	Do	Do	Ammonia Sulphate	1	—	
23.	Do	Do	NPK	1	—	

24.	State Ware house, Unit-II	KRIBHCO	Urea	1	—	
25.	State Warehouse Unit-II	KRIBHCO	Urea	1	—	
26.	State Warehouse Unit-I	Do	"	1	—	
27.	Cooperative Marketing Society, Thanesar	Do	"	1	—	
28.	The Morthort Credit Service Society, Morthly	IFFCO	DAP	1	—	
29.	State Warehouse No. 3, Kaithal	KRIBHCO	Urea	1	—	
30.	Do	Do	"	1	—	
31.	The Baupaur Coop. Credit Service Society Ltd. Baupaur	G.S.F.C.	DAP	1	—	
32.	Do	P.P.L.	DAP	1	—	

33.	Do	KRIBHCO	Urea	1	—	
34.	Jai Durga Fertilizer Kaithal	Hind Fertilizer	NPK	1	—	
35.	Krishak Bharati Sewa Kendra, Indri	KRIBHCO	DAP	1	—	
36.	KRIBHO, Karnal	Do	Urea	6	—	
37.	Central Coop. Bank Karnal	HAFED	NPK	1	—	
38.	Do	Sweeping Material	Urea	3	—	
39.	Do	G.S.F.C.	Ammonia Sulphate	1	—	
40.	Do	Sweeping material	"	1	—	
41.	Do	IFFCO	NPK	1	—	
42.	Shri Fertilizer & Chemical	Shri Ram	Urea	1	—	

43.	HLRDC, Madlauda	Jai Shree	Zinc	1	—	
44.	HLRDC, Panipat	Shivalik Chemica l	Zinc	1	—	
45.	Do	Jai Shree	"	1	—	
46.	KRIBHCO, Sonipat	KRIBHC O	DAP	1	—	
47.	Do	Do	Urea	2	—	
48.	The Garhi Kesari Coop. Service Society, Garhi Kesari	IFFCO	"	1	—	
49.	Do	NFL	CAN	1	—	
50.	Do	IFFCO	NPK	1	—	
51.	KRIBHCO, Palwal	KRIBHC O	Urea	1	—	
52.	KRIBHCO, Bal abgarh	Do	"	1	—	
53.	KRIBHCO Hodal	Do	"	I	—	
54.	KRIBHCO,	Do	DAP	1	—	

	Faridabad					
55.	KRIBHCO, Faridabad	Do	Urea	1	—	
56.	Coop. Mini Bank, Bancheri	NFL	CAN	1	—	
57.	Do	IFFCO	NPK	1	—	
58.	Central Coop. Bank, Faridabad	"	DAP	1	—	
59.	Do	NFL	Urea	1	—	
60.	Coop. Mini Bank, Bancheri	IFFCO	DAP	1	—	
61.	Central Coop. Bank F arid abad	HAFED	NPK	1	—	
62.	Do	NFL	CAN	1	—	
63.	Coop. Mini Bank Bancheri	IFFCO	Urea	1	—	
64.	Coop. Bank, Palwal	"	NPK	1	—	
65.	Do	MI	DAP	1	—	
66.	Do	NFL	Urea	1	—	

67.	Do	OP	CAN	1	—	
68.	KRIBHCO, Farldabad	KRIBHCO	DAP	2	—	
69.	KRIBHCO Faridabad	KRIBHCO	Urea	1	—	
70.	KRIBHCO, Gurgaon	"	DAP	1	—	
71.	DO	"	Urea	1	—	
72.	KRIBHCO, Rewari	"	"	9	—	
73.	Mini Bank, Bhakali	IFFCO	NPK	3	—	
74.	Do	"l	Urea	1	—	
75.	Do	If	DAP	1	—	
76.	Do	NFL	CAN	1	—	
77.	Do	Sweeping Material	Zinc	1	—	
78.	Mini Bank, Rewari	Do	NPK	3	—	
79.	Do	Do	DAP	1	—	
80.	Do	Do	Zinc	1	—	

81.	Do	Do	CAN	1	—	
82.	Do	Do	Urea	2	—	
83.	State Warehousing Corporation, Bhiwani	IPL	"	1	—	
84.	HAFED, Bhiwani	PPL	DAP	1	—	
85.	HAIC, Bhiwani	"	"	1	—	
86.	HAIC, Ch. Dadri	"	"	I	—	
87.	KRIBHCO, Rohtak	KRIBHCO	Urea	2	—	
88.	Mini Bank, Sundarpur	NFL	CAN	1	—	
89.	Do	Sweeping material	Urea	1	—	
90.	Do	Do	NPK	1	—	
91.	Mini Bank, Sampla	Do	Urea	1	—	
92.	Do	NFL	CAN	1	—	

93.	Mini Bank, Sundarpur	Sweeping material	DAP	1	—	
94.	Do	Do	NPK	2	—	
95.	Mini Bank, Khamba	IFFCO	DAP	1	—	
96.	Do	Sweeping material	Urea	1	—	
97.	Mini Bank Khamaa	NFL	CAN	1	—	
98.	Do	Sweeping material	NPK	3	—	
99.	Mini Bank, Sampla	Do	DAP	1	—	
100.	Do	Do	NPK	1	—	
101.	Farm Supdt. Samargopalpur	Do	DAP	1	—	
102.	Do	Do	Ammonia Sulphate	1	—	
103.	KRIBHCO, Safidon	KRIBHCO	Urea	2	—	

104.	Do Jind	Do	"	2	—	
105.	Alewa Coop. Society, Alewa	PPL	DAP	2	—	
106.	Mini Bank, Khokhri	Sweeping material	"	1	—	
107.	Do	Do	Urea	2	—	
108.	Do	Do	CAN	1	—	
109.	Do	Do	NPK	2	—	
110.	Mini Bank, Bishanpura	Do	"	1	—	
111.	Do	Do	DAP	1	—	
112.	Do	Do	Urea	1	—	
113.	Do	Do	CAN	1	—	
114.	Coop. Marketing-cum-Processing Society	POOL	DAP	1	—	
115.	HAFED, Ratia	IPL	Urea	5	—	
116.	HAFED, Fatehabad	"	"	4	—	
117.	Do	NFL	"	2	—	

118.	HAFED, Bhuna	"	"	1	—	
119.	Shri Ram Fertilizer Hisar	Shri Ram	"	2	—	
120.	KRIBHCO, Tohana	KRIBHCO	"	1	—	
121.	Mandi Adampur Coop. Mktg. Society Adampur	IPL	"	1	—	
122.	C.W.C. Hisar	KRIBHCO	Urea	1	—	
123.	Do	Do	DAP	1	—	
124.	Do	IFFCO	Urea	1	—	
125.	C.W.C., Adampur	KRIBHCO	"	1	—	
126.	KRIBHCO, Sirsa	KRIBHCO	Urea	1	—	
127.	HAFED, Ellenabad	INDO-PLAST	Zinc	1	—	
128.	M/s. Banwari Lal Loti Ram, Mullana	Agro Chem. Punjab	SSP	—	1	Prosecution launched
129.	M/s. Goyal Ferti- lizer,	Hind	NPK	—	1	Prosecution launched

	Saha	Fertilizer				FRC cancelled
130.	M/s. Dashmesh Fertilizer Ambala Cantt.	"	"	—	1	FRC cancelled
131.	M/s. Hind Ferti- lizer & Chemical, Rukri	"	"	—	1	Warning issued
132.	Do	"	"	—	1	Do
133.	M/s. Ved Parkash Arun Kumar, Ambala	India Ceriol	SSP	—	1	Do
134.	M/s. Mittal Sales Corporation Mullana	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Do
135.	Banwari Lal Loti Ram, Mullana	Agro Chemica l	SSP	—	1	Prosecution launched
136.	M/s. Jain Fertilizer Barara	Shival&	"	—	1	FRC cancelled
137.	M/s. Hind	Hind	NPK	—	1	Warning

	Fertilizer & Chemical, Rukri	Fertilizer				issued
138.	Mis. Vikas Traders, Ambala City	Oriental Carbon	SSP	—	1	FRC cancelled
139.	M/s. Mittal Sales Corporation, Mullana	NITIN	"	—	I	FRC cancelled prosecution, launched
140.	M/s. Arvind Kumar Jain & Co., Ambala City	"	"	—	1	Do
141.	Dashmesh Fertilizer, Ambala Cantt.	"	"	—	1	Prosecution launched
142.	Radha Chemicals, Radhapur	Radha Chemica l	Zinc	—	1	FRC cancelled
143.	Hind Fertilizer & Chemical, R ukri	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Warning issued
144.	HaryanaAgro, Chemical,	Haryana Agro	Zinc	—	1	Do

	Panchkula	Chemical				
145.	Do	"	"	—	I	Do
146.	H.L.R.D.C., Naraingarh	Gee Emm		—	1	Prosecution launched
147.	Partap Haryana Chemical & Ferti- lizer, Charnia	Partap	"	—	1	Warning issued
148.	Hind Fertilizer, Rukri	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Prosecution launched
149.	Nagpal Trading Co., Ambala City	"	"	—	1	Under process
150.	Krishna Traders Ambala Cantt.	Rampur Distillery	SSP	—	1	Prosecution launched
151.	Nagpal Trading Co. Ambala City	Hind Fertilizer	NPK	—	1	FIR lodged on 24-11-93
152.	Do	Indogulf	DAP	—	1	Do
153.	M/s. Hind Fertilizer & Chemical, Rikri	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Warning issued

154.	Do	Do	"	—	1	Do
155.	Prem Sagar & Co., Chhachhrauli	Agro Chemical	SSP	—	1	FRC cancelled
156.	Ram Lal Tilak Raj Chhachhrauli	Uttar Bharat	Zinc	—	1	FRC cancelled
157.	Kapoor Khad Bhandar, Ledi	Hind Fertilizer	NPK	—	1	FRC cancelled prosecution launched
158.	Do	ICL	SSP	—	1	Do
159.	K.C. Fertilizer, Bilaspur	Oriental Carbon	"	—	1	Prosecution launched
160.	Amar Product, Yamuna Nagar	Amar Products	Zinc	—	1	Warning issued
161.	Bawa Traders, Yamuna Nagar	Jay Shree	SSP	—	1	Prosecution launched
162.	Agro Chem. Traders	PPCL	DAP	—	1	Under Process
163.	Gambhir Products, Jagadhri	Rampur Distillery	SSP	—	1	Prosecution launched
164.	Garg Traders,	Shri	"	—	1	Do

	Jathlana	Acid				
165.	Bansal Trading Co. Jathalana	Oriental Carbon	"	—	1	Do
166.	Jai Laxmi Khad Bhandar, Gumthala	Rampur Distillery	"	—	1	Do
167	Om Parkash Aggarwal, Mustafabad	Jai Shree	"	—	1	Under Process
168.	Prem Fertilizer, Kurukshetra	Shivalik	"	—	1	Undes Process
169.	Amar Nath R oshanLal, Kurukshetra	"	"	—	1	Do
170.	IFFCO Sales Centre, Pipli	IFFCO	DAP	—	I	Warning issued
171.	Zamidara Khad & Pesticides, Pipli	Oriental Carbon	SSP	—	1	Prosecution launched
172.	Luxmi Fertilizer, Kurukshetra	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Warning issued
173.	Chawla Traders,	Munak	SSP	—	1	Prosecution launched

	Kurukshetra					
174.	Arya Fertilizer, pipli	Hind Fertilizer	NPK	—	1	Warning issued
175.	Jhandu Mal Des Raj, Shahbad	Shri Acid	SSP	—	1	Prosection launched
176	Arya Fertilizer, Pipli	Oriental Carbon	"	—	1	Do
177.	Sanjay Traders, Shahabad	Hind Fertilizer	"	—	1	warning issued
178.	Durga Fertilizer, Ladwa	Munak	"	—	1	Prosecution launched
179.	Shankar Trading Co., Jhansa	Oriental Carbon	"	—	1	Do
180.	Arora Trading Co., Pipli	"	"	—	1	Do
181.	Nanak Chand Bal Kishan, Shahbad	"	"	—	1	Do
182.	Nanwan Khad Bhandar Ladwa	Bharat	Chem. Fert.	—	1	Do
183.	Kishan Fert.	Jyoti	Zinc	—	1	Under

	Ladwa					Process
184.	Sarswati Fert.Pehowa	"	"	—	1	Do
185.	Shiv Fert. Agency Ladwa	Shree Acid	SSP	—	1	Prosecution launched
186.	Ram Sons Fert. & Chem., Ladwa	Parphat Zinc	Zinc	—	1	Under Process
187.	Prem Fertilizer Kurukshetra	Bharat Chem. & Fert.	SSP	—	1	Do
188.	Kurukshetra	Gee EMM	Zinc	—		Do
189.	Gugrat Fert., Kaithal	Shivalik	SSP	—	1	Do

.....

.....

.....

.....

.....

.....

245.	Gopal Support Co. Rohtak	Parkash Agro	Zinc	—	1	FIR lodged.
246.	Rathi Khad Bhandar, Kalanaur	Oriental Carbon	SSP	—	1	Prosecution launched.
247.	Punjab Trading Co., Rohtak	Do	SSP	—	1	Under Process.
248.	Babu Ram Goyal, Berl	Do	SSP	—	1	Prosecution launched.
249.	Rattan Lal Bansal	DJ	SSP	—	1	Prosecution launched.
250.	B.K. Trading Co. Kalanaur	Chambal	DAP	—	1	Warning issued.
251.	Tek Chand Bishambar Dayal, Sampla	Hind Fert.	DAP	—	1	Under Process.
252.	Dalam Walla Traders, Jind	India Cereiols	SSP	—	1	Warning issued
253.	KRIBHCO Safidon	Uttar Bharat	Zinc	—	1	Sale stopped. under process, Centre closed.

254.	Jai Ambe Beej Bhandar, Jind	Jai Shree	Zinc	—	1	Prosecution launched.
255.	Mangla Trading Co., Alewa	Oriental Carbon	SSP	—	1	Do
256.	Mukandl Lal & Sons, Narwana	Indian Phospha te & Carbo- nate Mfg. Co.	Zinc	—	1	Warning issued.
257.	Gopi Ram Rameshar Dass, Jind	Shree Acid	SSP	—	1	Prosecution launched.
258.	Mini Bank, Budhakhera	Chambal	Urea	—	1	Warning issued.
259.	Seized Material, Nagura (Naresh S/o Chander Bhan, Dehola)	DAP	IPL	—	1	FIR Lodged.
260.	Haryana Fert., Jind	Oriental Carbon	SSP	—	1	Prosecution launched.
261.	Dalam Wala Traders, Jind	Do	SSP	—	1	Do
262.	Ravi Beej	Do	SSP	—	1	FRC

	Bhandar, Barwala					Cancelled.
263.	Kamboj Agri Store, Fatehabad	Gandhi Chem.	Zinc	—	1	Warning issued.
264.	Ratia Agri. Chem. Store, Ratia	Oriental Carbon	SSP	—	1	Do
265.	Mehar Chand Krishan Kumar, Ratia	Do	SSP	—	1	Do
266.	Fateh Singh Niyamat Singh	NYL	SSP	—	1	Warning issued.
267.	Jyoti Krishi Bhandar, Narnaund	Oriental Carbon	SSP	—	1	Do
268.	KRIBHCO, Dabwali	Uttar Bhart	Zinc	—	1	Do
269.	IFFCO, Ellanabad	Sonia Overseas	Zinc	—	1	Do
270.	Do	Haryana Agro. Chem.	Zinc	—	1	Do
271.	Vinod Fert.,	Shree	SSP	—	1	Do

	Rania	Acid				
272.	Tulsi Ram Raj Kumar, Sirsa	Parkash Agro.	Zinc	—	1	FRC Cancelled.
273.	Lamboria Inter-prices, Sirsa	Jindal	Zinc	—	1	Warning issued
274.	Suraj Fert., Rania	Jai Shree	SSP	—	1	Do
275.	Chawala Fert., Sirsa	GNVFC	ASP	—	1	Do
276.	Harish Fert., Dabwali	Shree Acid	SSP	—	1	Do
277.	Sunil Kumar Sandip Kumar, Sirsa	Oriental Carbon	SSP	—	1	Do
278.	Jagdamba Trading Co., Sirsa	Do	SSP	—	1	Do
279.	Sita Ram Pesticides, Sirsa	Jai Shree	SSP	—	1	Do
280.	Ram Chander Inder Kumar, Sirsa	Oriental Carbon	SSP	—	1	Do

281.	HLRDC, Ding	Chandigarh Chem.	Zinc	—	1	Do
282.	HLRDC, Sirsa	Mahesh	Zinc	—	1	Do
283.	Shubh Ram Behari Lal, Dabwali	Jai Shree	SSP	—	1	Do

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, लगभग एक साल और दस महीने की अवधि से दौरान में जो खाद के नमूने लिए गए, उनमें से 328 नमूने निम्न स्तर के पाए गए और जवाब में बताया गया है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, निम्न स्तर के खाद से किसान का बहुत बड़ा नुक्सान होता है और देश का भी नुक्सान होता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि खाद का सैम्पल टैस्ट होने के बाद खाद किसान के खेत में जाए जिससे पैदावार का नुक्सान न हो? जब किसान के खेत मैं खराब खाद चला जाता है, तो किसान का बहुत नुक्सान होता है और उसकी पैदावार खराब हो जाती है?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत कोशिश होती है कि किसान को बढ़िया खाद मिले और खराब खाद न मिले। इस तरफ सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और वास्तव में किताब सिंह जी बहुत अच्छे किसान हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान को जिस खाद की ज्यादा जरुरत होती है,

वह है यूरिया और सके बाद है डी० ए० पी ०। ये दो खादें है जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तीसरी खाद जैसे जिंक हैं, बहुत कम इस्तेमाल होती है। यूरिया और डी ० ए ० पी ० ये दो खाद हैं जिनको सरकारी कम्पनियां ज्यादातर बनाती हैं, उनमें मिलावट बहुत कम होतीं है, मिलावट के बहुत कम चान्सिज हैं। जो किसान ज्यादा खाद यूज करते हैं, रसमें ज्यादा खराबी के चान्सिज नही हैं और जो छोटे किसान थोडी थोड़ो खाद यूज करते हैं, उस खाद को छोटे छोटे मैनुफैक्चरर्ज बनाते हैं, उभको भारत सरकार ने अलाउ कर रखा है, नम केसिज में कई जगह कमियां आई हैं। लेकिन सरकार फिर भी इस बारे में पूरी सतर्क है और सरकार को पूरी चिन्ता है कि किसानों को सही खाद मिले, गल्त खाद न मिले।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया हैं कि 328 केसिज निम्न स्तर के पाए गये हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें यूरिया के कितने और डी ० ए०पी० के कितने व बाकी खादों के कितने कितने केसिज है?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट हमने इस बारे में प्रोवाईड कर रखी है, अगर माननीय सदस्य उसको ध्यान से देखेंगे तो उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल जाएगा कि डी ० ए० पी ० खाद के कितने, यूरिया के कितने और दूसरी खादों के कितने कितने केसिज हैं।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन जिन केसिज में निम्न स्तर का दर्जा पाया गया है, क्या ऐसे केसिज में उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि ऐसे केसिज में तनि प्रकार के एक्शंज लिये जाते है। अगर खाद मे सिफ 5 परसैन्ट से कम न्यूटरैटंस हो तो उस कैस में वारनिग दी जाती है। अगर इससे ज्यादा किसी और बात की कमी रह जाए तो उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीक्यूशन केस दायर करते हैं। अगर खाद बिल्कुल ही खराब हो, जैसा जिंक में आम तौर पर हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे केसिज में एफ० आई० आर ० दर्ज करवाई जाती है, केस चलाया जाता है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर इस बात का श्रिका आया कि 328 केसिज न्यूटैरन्टस कम के मिले हैं। क्या मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि यूरिया, जिंक व डी ० ए ० पी ० में मिलावट के यि तने कितने केसिज हैं? क्या कैटेगरीवाइज मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हुमने पहले बताया है कि तकरीबन जिंक के केसिज में एफ० आई० आर ० दर्ज की गये। है। बाकी यूरिया व डी० ए० पी० के खिलाफ अगर कोई शिकायत

आई होगी, ऐक्शन लिया गया होगा तो ये दी गई लिस्ट को देख लें, इनको सब कुछ पता चल जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, जिन्दे केसिज में न्यूट्रैन्स कम थी उसके कारण किसानों की फसलों को व उनको नुक्सान हुआ है। हो सकता है शायद किसान भाईयों ने उस बारे में लिखकर न दिया हो, जबानी ही कहा हो शिकायत को गई हो, तो ऐसे मामले में अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो तो मन्त्री महोदय बताए।

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिज मे जब प्रोसीक्यूशन चालू हो जाती है तो कोर्ट तक केस चला जाता है। फिर उसके बाद यह कोर्ट पर डिपैन्ड करता है कि वह कब फैस ला करती है। लिस्ट मम्बर्ज के पास है, ये वहां से देख सकते हैं कि किन किन केसिज में एक्शन हुआ है। अगर यूही पूछ पूछ कर समय बरबाद करना है तो अलग बात है। मेरे विचार से अगर इनको सही पोजीशन देखनी है तो किसानों के खेतों में जाकर देखें और उन से पूछें कि उनके खेतों का क्या हाल है, तब इनको पता चलेगा। यूं ही हाउस का समय बरबाद नही करना चाहिये।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि नकली खाद इस्तेमाल करने से किसानों को जो नुक्सान होता है, क्या उसका मुआवजा किसानों को

सरकार की ओर से देने का कोई प्रोवीजन है ताकि किसानो का जो नुक्सान हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके? इसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि ऐसी कंपनियों पर, जिन्होंने नक्ली खाद सप्लाई करने का धन्धा पकड़ रखा है, उनके ऊपर सरकार कोई जुर्माना लगाने का विचार रखती है?

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, लगभग एक साल और दस महीने की अवधि के दौरान में जो खाद के नमूने लिए गए, उनमें से 328 नमूने निम्न स्तर के पाए गए और जवाब में बताया गया है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, निम्न स्तर के खाद से किसान का बहुत बड़ा नुक्सान होता है और देश का भी नुक्सान होता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि खाद का सैम्पल टैस्ट होने के बाद खाद किसान के खेत में जाए जिससे पैदावार का नुक्सान न हे।? जब किसाने के खेत में खराब खाद चला जाता है, तो किसान का बहुत नुक्सान होता है और नसकी पैदावार खराब हो जाती है?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत कोशिश होती है कि किसान को बढ़िया खाद मिले और खराब खाद ने मिले। इस तरफ सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और वास्तव में किताब सिंह जी बहुत अच्छे किसान है और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान को जिस खाद की ज्यादा जरुरत होती है, वह है यूरिया और उसके बाद है डी ० ए ० पी ०। ये दो खादें हैं

जो ज्यादा इस्तेमाल होती है। तीसरी खाद जैसे जिंक हैं, बहुत कम इस्तेमाल होती है। यूरिया और डी ० ए ० पी ० ये दो खाद है जिनको सरकारी कम्पनियां ज्यादातर बनाती हैं, रतमें मिलावट बहुत कम होती है, मिलावट के बहुत कम चान्सिज हैं। जो किसान ज्यादा खाद यूज करते हैं, उसमें ज्यादा खराबी के चान्सिज नही हैं और जो छोटे किसान थोड़ी थोड़ी खाद यूज करते हैं, उस खाद को छोटे छोटे मैनुफैक्चरर्ज बनाते हैं, उभको भारत सरकार ने अलाउ कर रखा है, उन केसिज में कई जगह कमियां आई हैं। लेकिन सरकार फिर भी इस बारे में पूरी सतर्क है और सरकार को पूरी चिन्ता है कि किसानों को सही खाद मिले, गल्त खाद न मिले।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया हैं कि 328 केसिज निम्न स्तर के पाए गये हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेगे कि इनमें यूरिया के कितने और डी ० ए ०पी ० के कितने व बाकि खादों के कितने कितने केसिज हैं?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट हमने इस बारे में प्रोवाईड कर रखी है, अगर माननीय सदस्य उसको ध्यान से देखेंगे तो उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल जाएगा कि डी ० ए० पी ० खाद के कितने, यूरिया के कितने और दूसरी खादों के कितने कितने केसिज हैं।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता 'हूं कि जिन जिन केसिज में निम्न

स्तर का दर्जा पाया गया है, क्या ऐसे केसिज में उन लोगों के खिलाफ किसी– प्रकार की कोई कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हू कि ऐसे केरिज में तनि प्रकार के एक्शंज लिये जाते है। अगर खाद में सिफ 5 परसैन्ट से कम न्यूटरैटंस हो तो उस केस में वारनिंग दी जाती है। अगर इससे ज्यादा किसी' और बात की कमी रह जाए तो उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीक्यूशन केस दायर करते है। अगर खाद बिल्कुल ही खराब हो, जैसा जिंक में आम तौर पर हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे केसिज में एफ० आई० आर० दर्ज करवाई जाती है, केस चलाया जाता है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर इस बात का जिकर आया कि 328 केसिज न्यूटैरन्टस कम के मिले हैं। क्या मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि यूरिया, जिंक व डी ० ए ० पी ० में मिलावट कितने कितने केसिज हैं? क्या कैटेगरीवाइज मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने पहले बताया है कि तकरीबन जिंक के केसिज में एफ० आई० आर० दर्ज की गई। है। बाकी यूरिया व डी ० ए. ० पी ० के खिलाफ अगर कोई शिकायत आई होगी, ऐक्शन लिया गया होगा तो ये दी गई लिस्ट को देख लें, इनको सब कुछ पता चल जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, जिन केसिज में न्यूट्रैन्स कम थी उसके कारण किसानों की फसलों को व उनको नुक्सान हुआ है। हो सकता है शायद किसान भाईयों ने उस बारे में लिखकर न दिया हो, जबानी ही कहा हो शिकायत की गई हो, तो ऐसे मामले मे अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो तो मन्त्री महोदय बताए।

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिज में जब प्रोसीक्यूशन चालू हो जाते। है तो कोर्ट तक केस चला जाता है। फिर उसके वाद यह कोर्ट पर डिपैन्ड करता है कि वह कब फैसला करती है। लिस्ट मैम्बर्ज के पास है, ये वहां से देख सकते हैं कि किन किन केसिज में एक्शन हुआ है। अगर यूही पूछ पूछ कर समय बरबाद करना है तो अलग बात है। मेरे विचार से' अगर इनको सही पोजीशन देखनी है तो किसानों के खेतों में जाकर देखें और उन से पूछें कि उनके खेतों का क्या हाल है, तब इनको पता चलेगा। यूं ही हाउस का समय कबाद नही करना चाहिये।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि नकली खाद इस्तेमाल करने से किसानों को जो नुक्सान होता है, क्या उसका मुआवजा किसानों को सरकार की ओर से देने का कोई प्रोवीजन है ताकि किसानों का जो नुक्सान हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके? इसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि ऐसी कंपनियों पर, जिन्होंने नक्ली खाद सप्लाई

करने का धन्धा पकड़ रखा है, उनके ऊपर सरकार कोई जुर्माना लगाने का विचार रखती है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में अभी तक नही यार्ड। अगर किसी किसान का, गलत खाद मिलने की वजह से नुक्सान हुआ है तो हम उसका ईलाज जरुर का लेंगे। अगर नकली खाद होगी तो हम मनुफैक्चरर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे।

श्री हरि सिंह मलबाः अध्यक्ष महोदय, जो खाद का मैनुफैक्चरर है, जैसे नेशनल फर्टिलाईनर्ज पानीपत में है, उन्होंने फर्दर अपने सप्लायर रखे हुए है। से जो माल आता है, वह ओरिजिनल बैग्ज में आता है और उसका भी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के लोग सैम्पल लेते हैं तथा इस बात पर चालान होता है। चालान इसलिये होता है कि बैग के अन्दर जितना मोटा दाना होना चाहिये उतना नही है क्योंकि इसके अन्दर थोड़ी राख सी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसा कोई चालान होता है, वह मैनुफैक्चरर का होता है या डिपो होल्डर का होता है। अगर बैग में टैम्परिंग है, तब तो डिपो होल्डर का होना चाहिए वरना मैनुफैक्चरर का होना चाहिए। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में तो नीति स्पष्ट है कि अन्यार बग में टैम्परिंग है, तो डिपो होल्डर के

खिलाफ चालान करेंगे और अगर नही है तो मैनुफैक्चरर का चालान होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम को इमप्रूव करने के लिए हमने कई डिसीजन लिए हैं। जैसे सैम्पल लेने वाली बात में शिकायत आई थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर आफिशियल हैं, जिनको इन्सपैक्शनं करने की पावर मिली हुई है, वे डीलर्ज को बता कर सैम्पल लेते हैं, ऐसी हमारे पास शिकायत आई थी। हमने उनसे पावर्ज विंद्ड़ा कर ली है और हैड क्वार्टर पर ज्वायंट डायरैक्टर और एडीशनल डायरैक्टर को ये पावर्ज दी हैं। अब वे सरप्राइज चौक कर सकते हैं ताकि किसी डोलर को पता न चले कि कब कैकिंग वाली टीम आनी है। हम चाहते हैं कि किसान को अच्छा खाद मिले, इसी बात को ध्यान में रख कर हमने यह चेंज की है।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मच्छी जी कह रह थे कि खेतों में जाकर देखें। 3 दिसम्बर, 1993 को मैंने साम्पला रोहतक बाई पास पर छापा मरवाया था। वहां पर लोग नकली दवाइयां बना रहे थे लेकिन सरकार ने अपने दबाव से उन लोगों को छुड़वा दिया।

(इस प्रश्न का नहीं दिया गया)

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले सवाल पूछा था, उसका जवाब ठीक नही आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रावधान करेगे कि खाद टैस्ट होने के बाद खेत मैं

जाए। ये जो 328 सैम्पल निम्न स्तर के पाए गए हैं, इसका कारण यह भी है कि बहुत सी फर्म ऐसी हैं जो सब–स्टैंडर्ड माल बनाती है। जैसे हिन्द फर्टिलाइजर है, इनका लाइसैसं कई बार कैंसिल हुआ है क्योंकि वह सब स्टैडर्ड माल बनाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी फर्म्ज को बन्द करवाएंगे और खाद टैस्ट होने के बाद ही किसान के खेत में जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है, सारे देश और प्रदेश का इसमें नुकसान है।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि किसान को ज्यादा खाद की जरूरत है और यूरिया की उससे कम जरूरत है। डी ० ए ० पी ० एक स्टैंडर्ड की कम्पनी है जिसमें खराब होने के चांस नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो छोटे मैनुफैक्चरर है, उनके सैम्पल हम रैगुलर ले रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि सैम्पल लेकर ही खाद खेत में जानी चाहिए, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि सैम्पल की रिपोर्ट आने में लगभग 60 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से खाद को रोक कर बैठ जाएंगे तो ये खुद झगड़ा खड़ा कर लेंगे कि खाद समय पर रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर किसान को खाद मिलने में एक दिन की भी डिले हो जाए तो उसका नुकसान होता है। हम यूरिया और डी० ए ० पी० की कभी भी रुकावट नहीं डाल सकते ताकि किसान का नुक्सान न हो। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार जो कुछ कर रही है, वह किसानों के इंट्रस्ट में कर रही

है। अगर माननीय सदस्य श्री किताब सिंह को कोई बात की पर्सनल शिकायत है तो हम हर वक्त सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्षः उन्होंने तो यह जानना चाहा है कि जो नैटोरियस फर्म्ज हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा रहा है।

Purchase of Buses

***763. Chaudhri Zile Singh Jakhar :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the total number of buses including ordinary/express purchased by the Transport department during the period from 1st January, 1993 to-date togetherwith the number of buses out of them allotted to each depot; and

(b) the per kilometer income accrued by the buses as referred to in part (a) above separately during the above said period ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) 1 जनवरी, 1993 से साथ तक खरीदी गई साधारण, एक्सप्रैस तथा डीलक्स बसों की संस्था 529 है। इन्हें विभिन्न डिपुओ में निम्न प्रकार से आबंटित किया गया है:—

क्र० सं०	डिपो का नाम	अलाट की गई बसों की संख्या	
		एक्सप्रैस / डीलक्स	साधारण
1.	अम्बाला	24	
2.	चण्डीगढ़	42	
3.	करनाल	11	
4.	जीन्द	15	
5.	कैथल	23	
6.	सोनीपत	17	
7.	यमुनानगर	22	
8.	दिल्ली	27	
9.	कुरुक्षेत्र	16	
10.	पानीपत	8	
11.	गुडगावा	25	
12.	रोडतक	5	

13.	हिसार	18	
14.	रिवाडी	23	
15.	भिवानी	10	
16.	सिरसा	17	
17.	फरीदाबाद	14	
18.	फतेहबाद	4	
19.	चरखी दादरी	8	
	कुल जोड़	329	

(ख) चालू वर्ष के दौरान हरियाणा रोडवेज बसों की औसत यातायात आय 5.00 रुपए प्रति किलोमीटर रही है, नई बसें औसत से अधिक यातायात आय दे रही हैं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा रोडवेज की बसिज आया लोगों को सुविधा के लिए है या लाभ कमाने के लिए हैं? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो 329 एक्सप्रैस बसिज खरीदी गई हैं, उनका डिपोवाइज डगबंटन का क्या क्राइटेरिया है? क्या उनका आबंटन का क्राइटेरिया पापुलेशन का है, एरिया का है

या सब डिपोवाइज का है? एक्सप्रैस बसिज का 25 परसैटं किराया ज्यादा है, उसके बावजूद उनकी अरनिंग ओर्डीनरी बसिज के बराबर है। एक्सप्रैस बसिज में सीटें हाफ होती हैं। एक्सप्रैस बस में 15 या 20 सवारिया होती हैं। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या लोकल रुटस के लिए आर्डीनरी बसिज खरीदी गई है?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज की बसिज लोगों की सुविधा के लिए है और लाभ कमाने के लिंए भी हैं। अब हम जो एक्सप्रैस बसिज बनवा रहे हैं, टनमें म्यूजिक और ओल्ड डरिंकस का भे। प्रावधान किया जा रहा है, वह यात्रियों की सुविधा के लिए ही है। एक्सप्रैस बसिज के स्टोपिज भी कम होते हैं। एक्सप्रैस बसिज लौंग रूट्स पर चलती हैं। हरियाणा के सभी जिला हैडक्वार्टर्ज को एक्सप्रैस बसिज से जोड़ा है। लोगों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हुमने ये बसिज रूट्स पर डाली हैं। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने बसिज की आबंटन का क्राइटेरिया पूछा है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह लोगों की मांग पर निर्मर करता है कि किस डिपो में कितनी बसिज दी जाएं। अभी पीछे हमने 329 में से 15 डीलक्स बसिज खरीदी हैं। उनमें से तीन डीलक्स बस हमने सोनीपत डिपो को आफर की थी लेकिन वहां से जी ० एम ० का जवाब आया कि यहां पर डो नक्स बस वायबल नहीं है इसलिए हम इस डिपो से नही चला पाएंगे। वायबिलिटी भी देखो जातो है ताकि दश खाली

न चलाई जाए। एक्सप्रैस बसिज की सीट भी आर्डीनरी बसिज से ज्यादा है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, उनकी रीसीट इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्सप्रैस बसिज का 25 परसैटं किराया भी ज्यादा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 329 एक्सप्रैस बसिज खरीदी गई उनमें से कुछ आर्डीनरी बसिज क्यों नहीं खरीदो गई ताकि लाम लोगों को उसका फायदा होता। जो इस समय लोकल रूट्स पर बसें चल रहे। हैं वे बहुत पुरानी बसिज है। वे सारी टूटी पड़ी हैं। उनका बहुत बुरा हाल है।

श्री बलबीर पाल शाह: स्पीकर साहब, हम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए और लोगों की मांग को देखते हुए बसिज बनवाते हैं। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि आर्डीनरी बसिज क्यों नहों खरीदी गई। इस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी हम बसिज का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। इसलिए जिनको रूट परमिट मिलेंगे उन बसिज को भी रूट्स पर लगाना पड़ेगा। इधर एक्सप्रैस बसिज के लिए लोगों को मांग बढ़ती जा रही है इसलिए हम चाहते है कि आने वाले समय में रूट्स पर माधो आर्डीनरी बसिज हों और आधी एक्सप्रैस बसिज हो। हमने सारी सुविगाए लोगों की भी देखनी हैं और इस बात का भी ध्यान रखना है कि विभाग को नुकसान न हो। जब इनका राज था तो उस समय 1990– 91 में रोडवेज को 10 करोड़ रुपए का घाटा था। जब हम आये, उसके बाद वर्ष 1992– 93 में हमने 7 करोड़

रुप ये का लाभ कमाया और वर्ष 1993–94 में भी हम 7 करोड़ से ज्यादा लाभ कमाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरका को रेवैन्यू देने की बात है, वर्ष 1991–92 में 70 करोड़ रुपये के रिसोर्सिज दिए गए और 1992–93 में 1०7 करोड़ रुपये के रिसोर्सिज दिए गए। 1993–94 का जो वर्ष चल रहा है, इसमें 175 करोड़ रुपये के लगभग रिसोर्सिज हम सरकार को देंगे। हमारी तो कोशिश यही होती है कि लोगों को सुविधाएं भी प्राप्त हो और सरकार को भी फायदा हो। स्पीकर साहब, इन्होंने जो मिनी बसें खरीदी थी, उनका क्या हाल हुआ उस बारे में मैं कुछ कहूंगा तो दूसरी बातें उठेंगी, उस बारे में अब कहना ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना सदन के पटल पर रखी है, उसके मुताबिक हमारे फरीदाबाद डिपो के लिए केवल मात्र 14 बसिज दी गई हैं। भाई जिले सिंह ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि आर्डीनरी बसें तो एक भी नही खरीदी गई। हमारे जले के सभी विधायकों ने और मैंने लिखित रूप से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि फरीदाबाद जिले के गांवों और शहर से सैकंडो/ हजारों की तादाद में नौकरी करने वाले लगो, व्यापारी और पढ्ने वाले बच्चे दिल्ली आते–जाते हैं। प्रायः आमतौर पर यह देखने मे आया है कि जो इन्होंने डीलक्स बसें चला रखी हैं और अब इन्होने उनकी संख्या भी पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ाई है।

श्री अध्यक्षः बिसला जी, आप स्पीच न करें, आप क्या बात पूछना चाहते हैं वह पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में यह बात ताना चाहता हूं कि होडल, पलवल, फरीदाबाद से जितनी भी बसिज गुजरती हैं, यानी ये डीलक्स बसिज चलने के स्थान से ही ओवरलोडिड होकर चलती हैं और ओवरलोडिड होने की वजह से हीं कहां पर रुकती नही हैं, जिसकी वजह से ओरते जो छोटे छोटे बच्चे लिए खड़ी होती हैं, वे बस की इंतजार में कई कई घंटे खड़ी रहती हैं लेकिन बस नहीं मिल पाती बसों की सुविधाएं न होने से दूसरे लोग, अपनी जीपें वगैरह चला रहे हैं जिनमें ये सवारियां बैठकर जाती है, जिसके कारण सरकार को अपने रेवैन्यू का भी नुक्सान होता है।

श्री अध्यक्षः आप सीधा सा सवाल पूछें जो शप पूछना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः मेरा कहना है कि वहां पर बसिज कम है जबकि पेसेंजर की संख्या ज्यादा है। जिले के सभी विधायकों ने भी मांग की है कि वहां पर नम्बर आफ बसिज बढ़ाई जायें। इन्होंने जो 14 बसिज अब दी हैं, वे भी राम हैं। वहां की समस्या की तरफ मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अतः मैं आपके माध्यम से मली महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या

मंत्री महोदय हमारे फरीदाबाद जिने को इसी सप्ताह या इसी महीने, और 50 नई बसें देगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके?

10.00 बजे

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, एक बोत मेरे माननीय दोस्त श्री बिसला जी ने मानी है कि जो एक्सप्रैस सर्विस चल रही है वह घाटे में नही चल रही है इसलिए मेरे माननीय साथी चोधरी जिले सिंह जी ने जो खदशा जाहिर किया है हि एक्सप्रैस बसें घाटे में चल रही है, वह ठीक बात नही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि बसों का प्राईवेटाईजेशन हो जाने के बाद जो सरप्लस बसें होंगी, उनको ऐसे रूटों पर चलाया जाएगा और कोशिश यह करेंगे जहां यातायात ज्यादा है, वहां अधिक से अधिक बसें दी जाएं और लोगो को सुविधा प्रदान की जाए। स्पीकर साहब, एक और तथ्य मैं यहां पर बताना चाहूंगा। हमारे साथी ने दिल्ली सर्विस पर जाने वाले यात्रियों की कठिनाई का जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में सर्विस करते हैं, उनकी फेसिलिटी के लिए दिल्ली सरकार को भी कुछ बसें चलना चाहिएं परन्तु ऐसा न होने के कारण सारा ट्रैफिक हरियाणा रोडवेज को हो सम्भालना पड़ता है। दिल्ली और हरियाणा सरकारों की दोनो तरफ से यह फेसिलिटी हो जाए तो सर्विस करने वाले यात्रियों को काफी राहत हो सकती है।

***812. Shri Dhirpal Singh : Will** the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide some amount at the discretion of the members of Legislative Assembly for the development works in their repective constituency ?

विकास मन्त्री (राव बंसी सिंह): इस सभा में दिनांक 4–3– 94 को मुख्य मन्त्री को घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधान सभा सदस्य को अपने निर्वाचन–क्षेत्र मे 1– 4–94 से प्रतेक वित्त वर्ष में 20 लाख रुग्ये की विकास योजनाएं (सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से) प्रस्तावित करने की अनुमति होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इसके बारे में हाऊस मैं आपके माध्यम, से यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पहला प्रान्त हैं जहां यह योजना लागू की गई है। दिनांक 4–3– 1994 को मुध्य मन्त्री जी ने सदन में घोषणा की है जिसके अनुसार प्रत्येक विधान सभा सदस्य को शपने निर्वाचन क्षेत्र में 1– 4– 1994 से प्रति वर्ष 20 लाख रुपये को राशि विकस कार्यों पर खर्च करने को अनुमति प्रदान की गई है। विकास कार्य पर डी० सी ० का कण्ट्रोल होगा।

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मती जी से यह जानकारी चाहूंगा कि यह 20 लाख रुपये की राशि, विधायक द्वारा किसी भी योजना की घोषणा होने के कितने समय बाद मिल जाएगी और राशि कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि कोई विधायक उस राशि को उस योजना वर्ष में खर्च नहीं कर सकेगा तो क्या बाकी की बची. हुई राशि अगले साल में सामयोजित की जाएगी? अध्यक्ष महोदय मन्त्री जी ने बताया है कि कन्ट्रोल डी० सी ० का होगा। योजना के लिए जो रा–मैटीरियल है, जैसे कि इंटें हैं, सीमेंट या दूसरा सामान है, उस पर विधायक का कितना कण्ट्रोल होगा? अगर वह योजना, विधायक द्वारा शुरु की जाती है तो उस पर उसका कितना कन्ट्रोल होगा और वह उस पर कैसे चौकिंग कर सकेगा?

श्री अध्यक्षः विधायक को तो मुंह से बोल कर कहना ही है कि, यह काम करना है, काम पर सुपरविजन मे लिए उसको कोई रोकता नहीं है वह उसको कैप कर सकता है, उसकी सुपरविजन कर सकता है।

राय बसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी धीरपाल सिंह जी को बताना चाहूंगा कि डिवैल्पमैंट वर्क्स के लिए जो भी योजना बनेगी, उसको टापप्रायोरिटी पर पूग करवाया जाएगा। वह राशि उे वर्क्स पर खर्च की जाएगी और विधायक उस राशि को जहां चाहे, खर्च करवा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विधायक नहीं हागा जो 20 लाख रुपये की राशि को पूरा खर्च न करवा सके और उसको अगले साल पर छोड दे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक बिसला जी के सवाल का सम्बन्ध था, हम उसको तो टोटली रिजेक्ट कर चुके हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही वैल्यूएबल सवाल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, हिमाचल में जब टोटल प्लान तैयार की जाती है तो उस समय वहां के सभी एम ० एल० एज ० के साथ बातचीत करके उसके बारे में उनकी राय ली जाती है, तभी बजट तैयार किया जाता है। मेरे ख्याल से यह प्रथा अभी वहां पर डिसकंटोन्यू नहीं की गई है। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी प्लान बनाते वक्त इम बात का ध्यान रखेगे ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मैंने 20 लाख रुपए के बारे में अनाउंस किया था, उस दिन इनको बहुत तकलीफ हो गई थी। इन्होंने कह दिया था कि हम नहीं लेंगे। अब ये बात को गोल मील करके पैसा लेना चाहते हैं। लेकिन धीर पाल जी ने जो सवाल पूछा है, वह बिल्कुल ठीक है कि अगर 20 लाख रुपए उस साल में खर्च नहीं होंगे तो क्या उस पैसे को अगले साल में भी दिया जाएगा। अब ये हिमाचल के बारे में कहने लग पड़े हैं। विकास योजना जो बनती है, वह पंचवर्षीय योजना से बनती है। जिस तरह केन्द्र सरकार ने प्रत्येक एम० पी० को अपने हल्के के विकास के लिए तक करोंड रुपये दिए हैं, उस तरह हमने भी एम० एल० एज० को 20 लाख रुपये दिए है। एम० एल ० ए० को चाहिए कि, वह अपने हल्के में होने

वाले कर्मो की लिस्ट क्रमवाईज बना का दे दे। हम इस 20 लाख रुपए को क्रमवाइएज लिस्ट के अनुसार. खर्च कर देगे। अगर कुछ काम रह जाते हैं तो उनके लिए हम अगले साल फिर पैसे दे देगे।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं वह यह है कि जो सिस्टम हिमाचल प्रदेश ने कर रखा है वि, टोटल प्नान के लिए सभी एम० एल० एज ० से राय लेते हैं, तो क्या यह सरकार भो ऐस करेगी? इस बारे में जवाब नही आया

श्री अध्यक्षः अब तो आठवी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है।

प्रो० सम्पत सिंहः लेकिन प्रायरिटी नहीं है। प्रायरटी तो स्टेट प्लानिंग कमीशन करता है। अध्यक्ष महोदय, जरार ये राय लेना नहीं चाहते हैं तो मना कर दें। (शोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्पके द्वारा इन्हें कहना चाहता हूं कि पहले तो इन्होंने 20 लाख रुपए लेने से मना कर दिया था क्योंकि ये स्टेट में डिवैल्पमैंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या सारे बजट में इनकी राय लेकर इसका भट्ठा बैठाना है (शोर त्वं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh : Sir, we are custodian. This assembly is custodian of budget and plan. This House is custodian, Sir. (Interruptions)

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सम्पत सिंह ने जिस बात की चर्चा को है, उसमें सभी मैम्बर्ज की सलाह की बात नहीं है। मैंने यह सिस्टम वैस्ट बगांल और गुजरात में स्टडी किया है, वहां पर कमेटी सिस्टम है। वहां हाऊस की कमेटी इस बात को डिस्कस करती है तथा पूरी बरह से डिस्कस कर के सारे प्रान्त की समस्याओं को देखकर बजट का प्रावधान करती है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्वीकर सर, कमेटी ही करती है, सरकार नहीं करती।

चौधरी जिले सिंह जाखडः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 20 लाख रुपया प्रत्येक सदस्य को उनके हल्के के विकास के लिए दिया जाना है, क्या उसका प्रावधान इन्होंने इस बजट में किया हे? पहले से जो प्रोग्राम है, जैसे जे ० आर० वाई० डो ० डी ० पी ० तथा एच० आर० डी० एफ० आदि चल रहे हैं, क्या इस राशि को इन्हीं प्रोग्रामों में खर्च किया जाएगा या इन प्रोग्रामों को छोड्कर अलग से राशि दी जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस राशि का बजट के अन्दर अलग से प्रावधान किया गया है। यह राशि 10 करोड़ के करीब है। अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम पूरी तरह से अन्य स्कीमों से

अलग है। जो स्कीम्ज पहले से ही चल रही हैं, वे भो चलती रहेगी। उन स्कीमों का इस स्कीम से कोई मतलब नहीं है।

Repair of Roads

***768. Shri Ramesh Kumar :** Will the Minister for P.W.D. (B &R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of Baroda constituency-

(i) from Jagsi to Chhataihara;

(ii) from Chidana to Dhurana;

(iii) from Mohmmadpur to Chhataihara; and

(iv) from Kohla to Nizampur; and

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be repaired ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें): मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी)

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) उक्त सड्कों पर पैचिज तथा खड्डों की मुरम्मत कर दी गई है।

श्री रमेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कांग्रेस सरकार दावा करती है कि हरियाणा प्रदेश की एक भी सड़क ऐसी

नहीं है जिसकी मुग्म्मत न की गयी हो लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से मंडी जी के नोटिस में लाना चाहुंगा कि मेरे हल्के बड़ौदा की निम्नलिखित सड़कें ऐसी हैं जिनकी आज तक मुरम्मत नहीं की गयी है–

1. जागसी से छतैहरा

2. चोडाना से धुराना

3. मोहम्मदपुर से छतैहरा

4. कोहला से निजामपुर

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सड्कों की कब तक मुरम्मत कर दी जाएगी?

चौधरी आनन्द सिंह डागीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन चार सबको की रिपेयर के बारे में कहा है कि इन सड्कों की बिल्कुल भी रिपेयर नहीं की गयी मै, इनको यह बात बिल्कुल गलत है। इन सड्कों की लम्बाई 33. 5 कि ० मी ० पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इन सड्कों की एक बार मुरम्मत का दी गयी थी तथा दोबारा से भी इनके पैचिज तथा खड्डों की मुरम्मत कर दे। गयी है। ये सड़कें यातायात के लिए भी चालू है जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने सैशन के दौरान विश्वास दिलाया था कि हम 6 महीने के अन्दर–2 सारी सड्कों की मरम्मत कर देंगे। वह काम सरकार ने पूरा किया है।

श्री रमेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, इनकी मरम्मत केवल कागजो तक ही सीमित है। वास्तविकता यह है कि इन सड्कों की मरम्मत बिल्कुल नहीं की गयी। क्या मंत्री महोदय इन सड्कों की जांच करवाएंगे कि मरम्मत की गयी है या नहीं?

श्री मनीरामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि आपने मुझे एक साल के बाद बोलने का मौका दिया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन्होंने खै हल्के में जो सड़क मंजूर की थी, उस पर मिट्टी भी पड़ गया थो लेकिन वह सड़क आज तक भी पूरी नहीं हो पायी है। यह सडक दडबकलां खुर्द से भोडिया तक 11 या 12 किलोमीटर लम्बी है। उस पर दो बार मिट्टी भी पड़ चुकी है और 1.5 किलोमीटर तक उस पर पत्थर भी पर चुका है लेकिन फिर भी वह आज तक नहीं बन पायी है। मुख्यमंत्री जी ने यह सडक आपने मे पिछले राज के दौरान मंजूर की थी तो अब वे इसको कब तक पूरी करवा देंगे?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होने ठीक ही कहा कि यह सड़क मैंने आपने पिछले राज के दौरान मंजूर की थी लेकिन बाद में इन लोगों का राज आ गया और जो भी मिट्टी बगैरह इस सड़क पर पड़ी थी वह भी वह गयी। हम फिर उस पर मिट्टी डलवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वे दोबारा बन जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जिन सड्कों की मरम्मत नहीं की गयी है, इसके लिए जैसा कि मैंने दो दिन पहले

ही कहा था कि हम पहली अप्रैल से एक साल के अन्दर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवा देगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि क्या विरोधी पक्ष के हल्कों की सड्कों के लिए पी० डब्ल्यू ० डी० वाले राशि अलाट करेंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपये की राशि के लिए विरोधी पक्ष के हल्कों का ही सवाल नहीं है। हमारे लिए सारी स्टेट एक जैसी है। हमें सबको बराबर देखना है। वैसे तो कुछ दिनों बाद कोई बिरोधी हल्का रहेगा ही नहीं, इनके हल्के भी हमारे ही हो जाने हैं।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर सर, जो विरोधी पक्ष के हल्के हैं, वहां सड्कों का बुरा हाल है? उन हल्कों की सड़कों के लिए बजट में पैसा एलौट नहीं होता है। धत्ने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। मती जी मुझे आश्वासन दे कि क्या उन, सड्कों की रिपेयर कराई जाएगी? (विघ्न)

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर सर, इनका चार साल क् राज चला गया लेकिन ये अपने चार साल में वे रोडज सैट नहीं कर सके। अब फिर यहां आकर इन्होंने मांग रखी है सड्कों की रिपेयर के निए। स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि किसी भीं हल्के के साथ किसी भी मामले में

भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है। सारे के सारे हल्कों की सड्कों की मररमत की जाएग।। आज कोई भीं ऐसी सड़क नहीं है जिस पर आवागमन न हो, सब पर यातायात चालू चौधरी बलवंत सिंह मायनाः स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर यातायात चालू नहीं है। मैं मत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैरे क्षेत्र के किंसरैंटी से मोरखेड़ी के बीच रोड बनी हुई है लेकिन उसका थोड़ा सा टुकड़ा नही बना है। पहले सैशन में भी मैंने कहा था, दूसरे में भी कहा था लेकिन वह सड़क ज्यों को त्यों हैं। इसी प्रकार से सिमली और भम्भेवा के बोच लोकल बसें चलनी बंद हो गई हैं क्योंकि वह सड़क टूटी पड़ी हैं। इसी तरह से डीगन से वेरी को सड़क भी टूटी पड़ी है। मंत्री जी स्वयं जाकर देख ले। हसनगढ़ और खुर्रमपुर की सड़क भी अधूरी पड़ी है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ने एक सड़क डीगल से देरी की चर्चा की। उस सड़क का एक–सवा–एक किलोमीटर का जो रास्ता है, वह फलड से टूट गया था, रसको अच्छी तरह से रिपेयर करा दिया है, शायद माननीय सदस्य उसके बाद उस सड़क पर गए नहीं हैं। कुछ सडकें जो गांव की आबादी में टूटो हुई हैं, उनका मुख्य कारण यह है किं गांव का जो पानी आता है, वह सड़क पर, आ जाता है, उस पानी को गांव वालों ने सीधे सड़क से जोड़ रखा है। पानी या जाने की वजह से सड़क टूट जाती है। उसके लिए हमने

प्रोग्राम बनाया है कि आने वाले 2–3 महीनों में हम उस पानी के लिए पक्की ड्रेन न बना सके तो कच्ची ड्रेन जरूर बता देंगे। जहां जरूरत है उन सड्कों की मरम्मत कराएंगे।

श्री सूरज मलः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ और सरहेड़ी का सीधा लिंक दिल्ली से है। वैसे तो हरियाणा में सारी सड़कें बाकायदा तौर पर बनी हुई हैं, मगर कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां एक– एक कि ० मी० के गैप हैं। दिल्ली के एरिया' की रोड पूरी बनी हुई हैं लेकिन हरियाणा के एरिया की तरफ जा जो गैप है, मैं चाहता हूं किं यह मुकम्मल करा दिया जाए, उस से हरियाणा का नाम भी होगा और ट्रैफिंक भी आसानी से आ जा सकेगा?

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सूरज मल जी ने जो सवाल किया है, यह बात आज तक हमारी नौलेज में नहीं आई कि कौन सा गैप कहा बाकी है जो दिल्ली की सड्कों को जोड़े। अगर कोई ऐसा गैप है तो चौधरी साहब लिखकर दे दें, उन पर विचार कम्के धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण करा देंगे।

श्री सूरज मलः स्पीकर साहब, एक गैप के बारे में क्सी बता देता हूं। लडरावण से पंजाब–खोड़ (यह दिल्ली सूबे का गांव है) उनकी रोड बनी है एक कि० मी ० का गैप हमारे हिस्से में आता है, वह नहीं बना है।

Setting up of 220 K.V. Sub-Station at Mohindergarh

***785. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a 220 K.V. Sub Station at Mohindergarh; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

Power Minister (Shri A. C. Chaudhry) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Sub Station is likely to be commissioned by 1996-97.

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद भी महेन्द्रगढ़ में विजिट किया था। सबसे आखिर में टेल पर यह इलाका है। अगर हरियाणा के किसी भी एक मंडल/ डिवीजन में सवसे ज्यादा नम्बर आफ ट्यूबवैल्ज हैं, तो वे महेन्द्रगढ़ में हैं। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी इसके लिये कुछ समय और कम करने की कोशिश करेंगे और टाईम बाउन्ड प्रोग्राम बनायेंगे?

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मेरे भाई राम बिलास जी ने खुद यह माना है कि टेल ऐंड तक के गांवों में, मैं बिजली की खुद समीक्षा करने गया था। यह जो जगह है, महेन्द्रगढ़, कनीना और नारनौल, इन सब की सप्लाई सांझी है और

सबस्टेशन वाकई ओवरलोडिड है। आज के हिसाब से यह जो हम 220 के० वी ० का सबस्टेशन बनाने जा ग्हे हैं, उसकी एस्टिमेटिड कास्ट 10 करोड़ की है। यह राशि समय के साथ जरूर बढ़ेगी क्योंकि प्राईसिज की एस्कालेशन हो रही है। दूसरी बात यह है कि इसके लिये जमीन की एक्वीजीशन भी होनी है, उसमें भी कुछ न कुछ समय लगेगा। इसके लिये हमने सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और सैक्शन 6 के पेपर्ज बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दो–तीन महीने में जमीन मिल जायेर्ग।। फिर हम इस पत्र काम शुरु करेंगे। आपको यह भी पता है कि 10 करोड़ रुपये की लागत से यह काम पूरा होना है। इसके लिये पैसा भी चाहिये और समय भी चाहिये। तो मेरा कहना यह है कि मेन इस के लिये चिन्तन जरूर है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं मैम्बर साहब को यह बताया चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जागरूक है। हमने साधन भी जुटाने हैं और सारी बातों को ध्यान में रखना है। इनके एरिया में कम से कम बिजली की ओवरलोडिंग हो और इनको पूरी बिजली मिलती रहे, इसके लिये हमने कई आल्टरनेटिव साधन भी अपनाये हैं। अटेली के सब–स्टेशन में हमने एडीशन करा है। इसके साथ साथ कनीना सब–स्टेशन को बाई– फरकेट करा रहे हैं। कनीना सब–स्टेशन से लोड हटा कर दूसरी जगह पर लगा रहे हैं। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजैक्ट के पूरा होने में जो समय लगेगा, उससे पहले ही, दूसरे साधनों से हम इनको सुविधा पहुंचा देंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने खुद माना है कि वहां पर लाइनों का बुरा हाल है और बहुत बुरी तरह से ओवरलोडिड हैं। इससे पहले कि वहां पर 220 के० वी ० का पावर हाउस बने और यह सारा सिस्टम शुरू हो, जैसे दिल्ली से बुडौली जोड़ने का प्रावधान इन्होंने किया है, उसी तरह से कनीना मुडीया खेड़ा महेन्द्रगढ़ को अलग–अलग जोड़ का किसान को राहत दी जायेगी। क्या इस प्रोग्राम को जल्दी करेंगे जो दिल्ली से बुडौली और बुडौली से महेन्द्रगढ़ कनैक्शन करना है ?

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मेन प्रोग्राम तो वही है लेकिन मैंने पिछले हफते भी जिक्र किया था कि बादशाहपुर से रिवाड़ी भी जोड़ना है। इससे वहां पर लोड कम होगा। इसके साथ–साथ अभी हमने सतनाली में एक 33 के० वी० का सब–स्टेशन कमीशन किया है। 132 के० वी ० का सब–स्टेशन अटेली में और एक 33 के० दी ० का सब–स्टेशन निजामपुर में, इसी साल में कमीशन करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। काम इमे पर चल रहा है। एक नया सब–स्टेशन गढ़ी माहसर में हम बनाने जा रहे हैं जो महेन्द्रगढ़ में है। ऐसा करने से इतने साधन उपलब्ध हो जायेगे कि वक्ता तौर पर जब तक यह प्रोजैक्ट धू होगा, कमीशन होगा, तब तक पोजीशन काफी ईजो हो जायेगी। मैं अपने माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं और ये मानेंगे भी, कि इस बार जिला महेन्द्रगढ़, जिला रिवाडी और साउथ हरियाणा में जितनी बिजली

को पोजीशन ईजी कर दी गयी है, उससे पहले कभी नहीं थी। यह बात तो अपने मुंह से यह कहेंगे।

प्रो० राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, बिजली की पूर्ति तो इन्होने नहीं की है। हां, समस्या को देखा जरूर है। पूर्ति तो हुई नहीं है, यह तो इन्होंने खुद माना है कि वहां पर लाईन्व ओवरलोडिड हैं। मेरे जिले में पिछले 6 महीने तक बिजली का अकाल रहा है। इन्होंने यह माना भी है कि लाईनें ओवरवोडिड हैं। ये खुद वहां पर गये हैँ औंर देख कर आये हैं कि किसानों ने पावर हाउस के सामने धरना दे रखा था। यह खुद भी वहां पत्र बैठे हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, मेरे भाई गलत भी सफाई से नहीं बोल पाये हैं। सही बात यह है कि रिवाड़ी नारनौल और महेन्द्रगढ़ जिलों में जितन। बिजली दी गयी है, उसके लिये इस बार वहां पर लोगों ने भजन लाल जिन्दाबाद के नारे लगाये हैं। मेरे साथ कैप्टन अजय सिंह और राव बंसी सिंह जी भी बैठे हैं। इनके इलाके के लोगों ने जिन्दाबाद के नारे लगाये हैं। आज भी मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये भाई चाहें तो वहां के लोगों की तरफ से लैटर आफ थैक्सं, जो एक रिटायर्ड कर्नल रैक के आदमी हैं, जिन्होंने सतनाली में और बाकी जगहों में मुजाहरों की अगुवाई की थी, ने लिखा है, वह पेश कर सकता हूं। अगर आप कहें तो मैं कल ही वह लैटर आफ थैक्सं टेबल पर रखवा देता हं ताकि इन को यह पता लग जाये कि पब्लिक हमारी

सरकार की शुक्रगुजार है, भले ही यह सियासी लोग सियासी बात की वजह से कह बात न मानें।

श्री सूरज मलः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे' कि क्या उनके नोटिस– में कोई ऐसी बात है कि जसौर खेड़ा और इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ के लिए तेतीस– तेंतीस के० वी० ए० का ट्रासफार्मर मन्जूर हो चुका है और इनके न होने की वजह से रोजाना इंडस्ट्री वालों की मिट्टी खराब रहती है, अगर इनके नोटिस में यह बात है तो इस समस्या के समाधान के लिए कब तक तेंतीस के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे?

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने इन बुजुर्ग माननीय सदस्य को खुद वाक्या था कि बहादुरगढ़ के लिए मेरे पास प्रस्ताव है और वहां के इंडनियललिस्ट्स का एक डेपुटेशन भी मुझे मिलने आया था। मैंने इनसे कहा था कि तीन–चार दिन की छुट्टी है। मैं इन छुट्टियों में टाईम दे दूंगा और बहादुर गढ़ में बैठकर समस्या का समाधान करके फैसला करवाऊंगा। स्पीकर साहब, पिछले शुक्रवार को आपको थर्मल प्लांट पानीपत के बारे में आश्वासन दिया था और मैं इनके साथ वहां का दौरा करके आया हूं।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि कल इन्होने मेरे एक सवाल के जवाब

में कहा था कि मूनक में 132 के० वी० का पावर स्टेशन लगाएंगे लेकिन आज जनसत्ता में छपा है कि वहां पत्र कोई पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इनमें से कौन सी बात ठीक है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, किसी पत्र में क्या छपा है इसका मुझे पता नहीं है। मैं कल से इस बक्स तक किसी भी पत्रकार से नहीं मिला हूं। स्पीकर साहब, मैंने जो वायदा किया है कि ''सबजैक्ट टू अवेलेबिलिटी आफ फण्डज'' लेकिन न होने वाली कोई बात नहीं है, जो मैंने वायदा किया है वह पूरा किया जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंहः मैं सदन को बताना चाहता हू कि वर्ष 1990–91 में चार सब स्टेशंज एक लोहारू में, एक पहाड़ी नकीपुर में, एक अगरोहा में और एक नहला में मन्जूर किए गए थे और इन पर काम भी शुरु हो गया था। दोनों सब–स्टेशंज लोहारू और पहाड़ी नकीपुर के सब–स्टेशंज का ताल्लुक है उनके बारे में तो बहन चन्द्रावती जो बताएंगी लेकिन अगरोहा और नहला का जहां तक ताल्लुक है वहां पर 33 के० के ० के सबस्टेशंज पर काम शुरु हो गया था और अगरोहा में तो मैडीकल कालिज के अन्दर इस सब–स्टेशन पत् कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो गया है लेकिन आज तक असे बाद पिछले अढ़ाई साल में सरकार ने एक पैसा भी इन दोनों सब– स्टेशंज पर खर्च नहीं किया है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, एक पैसा भी सरकार खर्च नहों कर रही

है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों सब–स्टेशंज को कब तक पूरा करेंगे?

श्री ए० सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ये अपोजीशन के लीडर हैं और इनका स्तर एक मन्त्री के बराबर है। इनको तो पता है कि यह क्वेश्चन महेन्द्रगढ़ के बारे में है और जो कुछ प्रश्न में पूछा गया था उसके बारे में मैंने फिगर्ज दे दी। जैसा कि इन्होंने कहा कि 1991 में वहां पर पैसा लगा और उसके बाद नहीं लग रहा है, इसके बारे में मैं बगैर कागज देखे कैसे बता सकता हूं। 1991 के बाद भीं पैसा लग सकता है, यह तो रिकार्ड देखकर. बताया जा सकता है। यह क्वेश्चन महेन्द्रगढ़ ऐरिया के बारे में था औप जो कुछ रसमें पूछा गया था बगैर कागज देखे मैंने जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप अलग से इस बारे में क्वैश्चन पूछ लें।

प्रो० सम्पत सिंह: ठीक है जी।

Number of J. B. T. Teachers

***737. Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of J.B.T. teachers working in the Govt. Primary Schools in the State at present togetherwith the number of J.B.T. teachers belonging to Scheduled Castes and Backward Classes amongst them ?

Education Minister (Shri. Phool Chand Mulana) : There are 33527 J.B.T, Teachers working in Government

Primary Schools in the State. Of these, 2017 belong to Scheduled Castes and 2666 are from Backward classes.

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट की 6800 पोस्ट्स होनी चाहिए थीं और इसमें दो हजार ही हैं। इस समय 4800 पोस्टस का बैक लौग है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के कोटे में भी एक हंजार टीचर्ज की कमी है क्या मन्त्री महोदय, स्पेशल भर्ती करके इन दोनों केटेगरीज की पोस्टस की कमियों को पूरा करने की कृपा करेगे। क्या मंत्री महोदय, यह भी बताएंगे कि जिन्होंने पूरी भर्ती नही की उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, जितनी चिन्ता रिजर्वेशन पौलिसी की श्री लहरी सिंह को है उससे ज्यादा चिन्ता भजन लाल जी की सरकार को और मुझे है। 1989 से पहले जो वेकेन्सी थी वे तो आज नहीं हैं लेकिन स्पीकर साहब जे ० बी ० टी ० की पोस्ट्स केवल एस ० सी ० और बी ० सी ० की ही खाली नहीं बल्कि जनरल केटेगरी की भी है। पिछले दिनों हमने तीन हजार पोस्ट्स बोर्ड के माध्यम से मांगी हैं। जिसमें 900 भरी हैं और चार हजार के लगभग औी मांग रहे हैं जिसमें एस ० एस ० मास्टर्ज और जे० बी० टीज० भी हैं। मौजूदा 2707 जे ० बी ० टी ० पोस्टें खाली हैं जिसमें एस ० सी ० की 656 और बी ० सी ० की 263 खाली हैं। ज्योंही कैन्डीडेट्स उपलब्ध होंगे, इन पोस्टों को तुरन्त भर दिया जाएगा और हमने इनको पूरा करने के लिये

सारी स्टेट के अन्दर 17 ट्रेनिंग सैन्टर्ज चालू किये हुए हैं और उन सैन्टर्ज में 1810 बच्चे ट्रेनिंग लेकर के आ जाएंगे। फिर कोई बी ० सी ० व एस० सी ० का शार्ट फाल नहीं रहने दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Lining of Saraswati Canal

***777. Sardar Jaswinder Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. for lining of Saraswati Canal in Pehowa; and

(b) if so, the time by which the lining of the said canal is likely to be started/completed ?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा):

(क) जी, हां।

(ख) यह कार्य वर्ष 1995–96 के दौरान सम्भवतः आरम्भ किया जायेगा।

Opening of a Govt. College at Farnkh Nagar

***752. Shri Mohan Lal Pippal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Govt. College at Farukh Nagar; and

(b) if so, the time by which the said college is likely to be opened?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Posts of J. B. T. of Urdu

***772. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of sanctioned posts of J.B.T. of Urdu for the Govt. schools of Hathin, Punhana, Nagina, Nuh and Taoru blocks of Mewat area as at present; and

(b) the number of posts out of those as referred to in para (a) above are likely to be filled up ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) इन ब्लाको में स्वीकृत पदों की संख्या 95 है।

(ख) 16 रिक्तिया हैं जिन्हें भरे जाने की सम्भावना है।

Opening of Ayurvedic Dispensary at Village Khatiwas

***743. Chaudhri Om Parkash Beni : Will** the Minister for **Health** be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Ayurvedic Dispensary in village Khatiwas (Rohtak); and

(b) if so, the time by which the aforesaid dispensary is likely to be opened ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी):

(क) हां।

(ख) इसके लिए इस समय कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती।

Providing of Drinking water

***758. Shri Daryao Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state.—

(a) the names of villages, if any, in Jhajjar Block in which drinking water facilities have not been provided so far and

(b) the steps taken or proposed to be taken to provide drinking water facilities in the villages as referred to in part (a) above ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रामपाल सिंह कंवर):

(क) शून्य।

(ख) उक्त ''क'' अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सचिव द्वारा घोषणा

संविधान के (77 वां संशोधन) विधेयक, 1992 के अनुसमर्थन सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House, a copy each of the following documents, received from the Council of States, regarding the ratification of the Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Bill, 1992 :—

(i) Letter dated the 8th September, 1993, received from the Secretary-General, Rajya Sabha, New Delhi;

(ii) The Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Bill, 1992, (English and Hindi versions), as introduced in the House of People;

(iii) The Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Bill, 1992, (Engilsh and Hindi versions), as passed by the Houses of Parliament;

(iv) Lok Sabha Debates on the Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Bill, 1992; and

(v) Rajya Sabha Debates on the Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Bill, 1992.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, आज के एक अखबार में, हमारे राज्य के गवर्नर महोदय के पोते के बारे में एक खबर छपी है कि उन्होंने फरीदाबाद में किस तरीके से..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप बैठिये। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सारी पोजीशन क्लीयर कर देता हुं। (शोर) जो ये लोग कहना चाहते हैं, (रस बारे में मैं एक मिनट में क्लीयर करके बता देता हूं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिये। (शोर)

श्री अध्यक्षः नहीं नहीं। आप बैठिये। (शोर) The conduct of the Governor cannot be discussed in the House.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में छपा है, वह खबर बिल्कुल बेसलैस और बेबुनियाद है। मैं उस अखबार वालों से भी यह कहूंगा कि जब तक वे किसी बात की पूरी तरह से तह में न जा ले और सारी बातों की जांच पडताल न कर लें, तब तक ऐसी खबर को न छापा जाए। (शोर) मैं हाउस में यह बताना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय का कोई पोता फरीदाबाद में नहीं पढ़ता। मैंने पूरी जांच कर ली है। दो, दिन पहले यही खबर हिन्दुस्तान वाईम्ज में भी आई थी और आज यह ट्रिब्यून में छपी

है। गवर्नर महोदय के दो पोते हैं। एक पोता गई में पढ़ता है और दूसरा यहां चण्डीगढ़ सैडल स्कूल में पड़ता है। उनका कोई पोता फरीदाबाद में नहीं पछता। यह जो खबर छपी है यह बिल्कुल खे–बुनियाद व बेसलैस

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यहां हाउस के अन्दर गवर्नर महोदय के कंडक्ट पर बात नहीं हो रही बल्कि उनके पोते के बारे में जो खबर छपी है, उस पर चर्चा हो रही थी। चलो मुख्यमन्त्री महोदय ने बात को क्लैरीफाई कर दिया है। पीछे जब हमने इस हाउस में एक मन्त्री महोदय के भाई व उप्रके साले के बिहेवीयर के बारे में प्रश्न किया था कि मन्त्री महोदय के लड़के ने रोहतक के अन्दर किस प्रकार से नकल न करवाने के कारण पुलिन कर्मियों के साथ मिल–बिहेव किया था तो उस वक्त सरकार ने यह कह दिया कि यह मामला सब–जुडिस है। हमने कह दिया कि यह मामला सब जुडिस नहीं है। क्योंकि केवल पुलिस ने ही उसका चालान किया था। स्पीकर साहब, उसकी जमानत कोर्ट में नहीं हुई बल्कि पुलिस में जमानत ले ली गई। स्पीकर साहब, उसके बाद आपकी रूलिंग आई और आपने कहा था कि चूंकि मैंटर सब–जुडिस है, इसलिए दि मैटर एंडज। हम आपकी रूलिंग से सैटिसफाई हो गए क्योंकि शापकी रूलिंग आई कि एक्सन हो गया। लेकिन यह आगस्ट हाउस 90 एम०एल०एज० का है और इसमें सभी पार्टीज के एम०एल० एज० हैं। इन्होने अब कांग्रेस पाटों की मीटिंग बुला कर यह फैसला ले लिया कि तीन आदमियों

की यानी एम० एल० एज० को कमेटी बैठाएंगे और वह कमेटी इन्क्वायरी करके इस मामले की तद्' तक जाएगी। स्वीका साहब, उस दिन के मुताबिक जब एक्शन हो गया था तो मामला खत्म हो गया था लेकिन अब ये तीन मैंबर किस बात की इन्क्वायरी करेंगे? इसका मतलब यह है कि उस मैटर को हाउस में डिस्कस करवाने की बजाए ये उसको पार्टी मीटिंग तक सीमित रखना चाहते हैं। यह सवाल एक पार्टी का नहीं है। जो लोग आज सज्जा में है, उनके परिवार के लोगों का सवाल है। जैसे इस लड़के का जिक्र आया। रोहतक में जब ट्रैफिक सप्ताह मनाया जा रहा था, पुलिस के लोगों ने जब उस लड़के की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने उनको धक्का दे दिया। उस वक्त सिचुएशन कन्ट्रोल में नहीं गई और पुलिस के लोग लाठियां फेंक कर चले गए और कहने लगे कि हम अब डियूटी नहीं देंगे। ट्रैफिक सप्ताह का चौथा दिन खत्म हो गया था। अगर उस टाइम कार्यवाही हो जाती तो आगे यह कदम न उठता कि पुलिस के लोगों ने लड़के को नकल करने से इन्कार करवा दिया। जिन तीन पुलिस कर्मियों ने नकल करवाने से इंकार किया था, जब वे अपनी डियूटी के बाद उस लड़के के घर के आगे से गुजर रहे थे तो उस लडके ने अपने दूसरे साथियों को ले कर उन तीनों को बुरी तरह से पिटवाया जिस कारण वे जख्मी हो गए। इससे पहले भी उस लड़के ने वहां की महिला डी ० एस० पी० के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस वजह से पुलिस वालों में बहुत रिजैंटमैंट है। इन्होने सारी पुलिस मशीनरी को क्लैपस करके रख दिया। आज उनके मन में टैरर हुं

कि अगर हम किसी बड़े आदमी को छेड़ेंगे तो तुम्हारे ही खिलाफ कार्यवाही होगी। पिछली बार यहां पर हमने एक एस ० पी ० की बड़ाई कर दी थी जो उस समय सिरसा में कार्यरत था। हमने उस समय कहा था कि चूंकि हमने उसकी बड़ाई की है इसलिए वह वहां पर रह नही पाएगा। अखबार वाले भी फ्लड की रिपोर्ट लेने वहां गए थे। अखबार वालों ने भी उसके बारे में लिख दिया कि वह अफसर बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद वह एस०पी० किसी भी जिले में नहीं रह सका। तो स्पीकर साहब, ऐसा करने से तो यह सारा सिस्टम क्लैपस हो जाएगा। इस मुद्दे पर हाउस में चर्चा होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ज्यादती किस ने की है और किस का कसूर है। केवल तीन एम० एल० एज० की कमेटी बनाना ठीक नहीं ई। फर उन्हीं लोगों से उस लड़के की जमानत करवा ली गई है जिनको उस लड़के ने पिटवाया था। अभी उस लड़के की पीठ दिखाने की बात हो रही थी कि उसको कितना पीटा गया है। मैं कहता हूं कि आप पूलिस वालों की भी पीठ देख ले। मुख्य मन्त्री जी उस लड़के की फोटो की तरफ इशारा कर रहे थे। जहां तक फोटो का सवाल है, जो आदमी रोज कानून को अपने हाथ में लेता हो तो पता नहीं वह कहा से पिट कर आया होगा। न जाने किस मुहल्ले में उसको पीटा गया होगा और उसको पुलिस के जिम्मे लगाया जा रहा है। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पाका साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। स्पीकर साहब, कल या परसों यह मुद्दा उठाया गया था और

उस पर आपने अपनी रूलिंग दे दी थी उससे मेरे विपक्ष के भाई सैटिस्फार्ड हो गए थे इसलिए वह मैटर खत्म हो गया था। आज विपक्ष के नेता ने अपना भाषण शुरु किया और उसमें कई और बातें जोड़ दी। कल या परसों विपक्ष के नेता ने यह मुद्दा इस तरह से उठाया था कि मंदी के बेटे ने नक्त करवाने की कोशिश की इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या एसएम लिया गया, इस बात का यह जवाब दिया गया कि इस बारे में केम रजिस्टर करना दिया गया है, उस पर आपने जो रूलिंग दी उससे विपक्ष के नेता सैटिस्फाई हो गए, इसलिए वहू मैटर समाप्त हो गया। आज जो खबर अखबारों में छपी है, मंत्री जी ने शिकायत की है कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती हुई है। मंत्रों द्वारा यह शिकायत उठाना कोई पाप तो नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि इस मैटर को हाउस में डिस्कस किया जाए। एक आदमी प्राइवेटली शिकायत करता है..। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः मंत्री ने पार्टी मीटिंग में यह शिकायत की है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः चलो, मान लिया इन्होने पार्टी मीटिंग में शिकायत की है। वह पार्टी भी इनकी अपनी पार्टी है। यदि माननीय मंत्री जी अपनी पार्टी के सामने यह शिकायत करते हैं कि उनके बेटे के साथ ज्यादती की गई है, इसकी इन्कवायरी की जाए। मंत्री जी इस बात का मुख्य मंत्री जी के सामने जिकर करते या अपने कूलीग्ज के सामने जिक्र करते, यह कोई जरूरी नहीं है

अगर इन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में जिकर का दिया तो स्ब कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को इस तरह से इतना बड़ा बना देना कि पुलिस बहुत भयंकर डिमोरेलाइज हो गई, पुलिस वह हो गई, पुलिस यह हो गई, ठीक नहीं है। इनको इस तरह से पुलिस के जजबातों को नहीं भड़काना चाहिए। इनको संयम रखना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि विपक्ष को मुद्दे जरूर उठाने चाहिएं लेकिन मुद्दे वह उठाएं जिनमें वजन हो और गवर्नमैंट को उन मुद्दों के बारे में अलरट भी रहना चाडिए लेकिन विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी है कि वह कोई ऐसी बात न करे जिससे स्टेट में बदअमनी फैले, जिससे स्टेट का नुक्सान हो, जिससे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो, जिससे पुलिस फोर्स में बदअमनी या रिजैटमैंट हो, इसलिए विपक्ष के नेता को इस तरह से कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चहिए। स्पीकर साहब, मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि एस ० वाई० एल० का मुद्दा उठाया गया। एस ० वाई० एल० के बारे में कौन चिन्तित नहीं है? यह सभी लोग जानते हैं कि 90 के 90 विधायक उस कैनाल के बारे में चिन्तित है।

श्री अध्यक्षः इसका रैकैंस बाद में दें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः ठीक है जी। स्पीकर साहब, हुडडा साहब ने अपने बेटे से बारे में कहा और मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि इस बारे में तीन विधायकों की एक कमेटी बना कर इन्कवायरो करा देंगे। सम्पत सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि

आपने यह कैसे एन्टेसिपेट कर लिया कि उस कमेटी के तीनो मैम्बर कांग्रेस पार्टी के ही होंगे, हो सकता है शायद उसमें विपक्ष के किसे। विधायक को भी शामिल कर लें या हो सक्ता है यह खबर अखबारों में ही गलत छपी हो। इस तरह से वावेला मचा देना कोई अच्छी बात नहीं है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सम्पत सिंह जी ने यह मामला उठाया है, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि कप हमरी पार्टी माटिंग थो। उस मीटींग में इस बारे में थोड़ी चर्चा चलीं थी कि हुड्डा साहब के लड़के के साथ पुलिस ने ज्यादती की है और मार पिटाई की है जोकि पुलिस ने अच्छा नहीं किया, उनकी काफी पिटाई की गई, उनकी बेइज्जती को गई। यह मामला पार्टी मीटिंग में उठा था। मैंने उस समय कहा कि इस बारे में सीनियर अधिकारी से इन्कवायरी करवा लेते हैं लेकिन उस समय हमारे? पार्टी के कुछ सदस्यों ने यह कहा कि एम ० एल० एज० की एक कमेटी बना दें। मैंने कहा कि ठीक है तीन एम० एल० एज ० की एक कमेटी बना देंगे जो इस बारे में जांच कर लोगे। वह कमेटी बना दी है और उस कमेटी में चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसरा, श्री मनोराम केहरवाला और श्री जाकिर हुसैन एम० एल० एज ० को मैम्बर बनाया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। (शोर)

चौधरी भजन लालः किस बात का प्वायंट औफ आर्डर है? पहले मुझे अपनी बात कह लेने दें, उसके बाद आप कह लेना। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ओफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप इस तरह से बीच में न बोलें। बैठ जाएं,

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कमेटी बना दी है। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगा, उस पर कार्यवाहों करेगे। इनका यह कहना कि पुलिस डिमोरेलाइन हो गई है, पुलिस वह हो गई है पुलिस यह हो गई है, यह इनकी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी कैसा जुर्म करता है, उसके मुताबिक केस दर्ज होता है। यह केस 323 धारा के तहत दर्ज हुआ है। इसमें पुलिस ही जमानत लेगी। (शोर एवं विघ्न) इसमें कोई मरा तो नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस दिन संसदीय मंत्री ने कोर्ट की बात की थी।

चौधरी भजन लालः जब मामला दर्ज हो गया तो वह कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन उस दिन यह तो नहीं पता था कि किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। (शोर एवं विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः चौधरी साहब, आप अपने मंत्री को कहें कि ये सोच समझ का बातें करें। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः मैं हाऊस को बताना चाहता हूं कि जो उन तीन एम ० एल० एज० की रिपोर्ट इस बारे में आएगी, उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहानः कोई विपक्ष का साथी इस बात को उठाता है तो कहते हैं कि यह मामला सब–जुडिस है। सरकार की तरफ से इस बारे में जब बात उठती है तो कहते हैं कि सब–जुडिस नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही केस में यह दोहरा मापदण्ड कैसा है? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः मैंने नहीं कहा। (शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहानः आपके मंत्री ने कहा था। (शोर)

तारांकित प्रश्न संख्या 726 पर अतिरिक्त सूचना देना

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कल चौधरी संपत सिंह जी ने सवाल नं० 726 के बारे में पूछा था कि प्राज्य में बर्ष 1993 और वर्ष 1994 में कितने हत्या के मामले दर्ज हुए। उस बारे में मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में 603 अभियोग दर्ज हुए और 645 लोगों की जानें गई तथा वर्ष 1994 में 34 अभियोग हुए और 35 लोगों की जाने गई।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में बताया है कि वे अपनी पार्टी से विधायकों की एक समिति गठित करेंगे जो इस बात को देखेगी कि किस तरह की इस मामले में ज्यादती हुई है। स्पीकर साहब, यह मामला हुड्डा साहव के बेटे की पिटाई का नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में पुलिस राज कायम हुआ है। जय एक मंत्री, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता तो फिर आम आदमी का क्या हो रहा होगा।

श्री अध्यक्षः दलाल साहव, जब एग्रीवड पार्टी संटीस्फाइड है तो फिर इसमें आपके कहने की कोई बात नहीं रह जाती। अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, जब ये अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

(1) श्रम तया रोजगार राज्य मंत्री द्वारा

श्रम तया रोजगार राज्य मंत्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। श्री सम्पत सिंह जी ने बोलते हुए, रोहतक में जो डी० एस० पी० महिला लगी हुई हैं, उसके बारे में जिक्र किया कि मेरे लड़ते ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं भरे हाउस में कहना चाहता हूं कि यदि

मेरे लड़के ने उस महिला डी ० एस ० पी ० के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो तो मैं आज ही अपना इस्तीफा सी० एम० साहब को दे देता हूं। इतना हे। नहीं इस मामले की जांच मेरी पार्टी का कोई मैम्बर नहीं बल्कि सम्पत सिंह जी, खुद कर लें कि मेरे लड़के का कसूर इसमें कोई है या नहीं। यदिं इनकी रिपोर्ट में मेरा लड़का दोषी पाया जाए तो मैं उसे। दिन इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मेरा लड़का वहां पर नक्ल करवाने के लिए गया ही नहीं, यदि वह गया हो तो मैं आज ही इस्तीफा दे देता हूं। स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है किं आज मेरे से वे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके राज में सुप्रिया जैसा काण्ड हुआ हो, तब इस्तीफा नहीं दिया और जिनके राज में ओम प्रकाश चौटाला के लड़के ने ताज होटल में एक लड़की को अपने हाथों में उठा लिया था, तब इस्तीफा नहीं दिया। यदि वे उस समय इस्तीफा दे देते तो मैं भी आज इस्तीफा देने में एक मिनट नही लगाता। स्पीकर सर, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से खुद यह कहा कि मेरे लड़के के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत न की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैंने अपने लड़के को किसी प्रकार से भी कार्यवाही होने से बचाया नहीं, उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। जिस समय वह बेल हो कर घर पर आये तो मैंने लड़के को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बात तो सुन लो परन्तु मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी और उसको घर से निकाल दिया। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं सुनना है, जो भी कहना हे, प्रैस में जा कर

कहो। वे प्रैस में गए और उन्होंने अपने जिस्म पर जो निशान थे, वह भी प्रैस वालों को दिखाए कि पुलिस ने उसकी कितनी पिटाई की है। चौधरी कर्ण सिंह दलाल ने भी शायद उसके शरीर के जख्मों को देखा होगा। हम कोई गलत काम नहीं करते, मेरे लड़के के साथ जो भी हुआ, उसके लिए बाकायदा कार्य– वाही हुई और हमने किसी भी बात को हश–अप करने की कोशिश नहीं की। सरकार में मिनिस्टर होते हुए भी मैंने अपने लड़के के खिलाफ हुई कार्यवाही को रोकने की कोशिश नहीं की, और न ही उसको प्रोटैक्ट करने की कोशिश की है।

(2) राजस्व मन्त्री द्वारा

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह): स्पीकर साहब, मैं भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। लीडर आफ दि हाउस, हुड्डा साहब और वीरेन्द्र जी ने इस बारे में बताया है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि मेरे साथियों को कुछ भी बात कहने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। इस तरह की बात जो हुडडा साहब के लड़के के साथ हुई है, इसी ढंग से हम में से किसी भी साथी के साथ हो सकता है। मुजरिम के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करती है और मुजरिम के साथ पुलिस द्वारा मारपीट भी की जाती है (विघ्न) जब हमारी सरकार नही थी हमने तो तब भी भुगत रखा है, सम्पत सिंह जी ने खुद भुगता है, उनके खुद के यूथ प्रैजिडैटं को इनकी पुलिस ने पीटा। स्पीकर साहब, सरकार की यह बहुत बड़ी जिम्मे– दारी है, यदि इस तरह का मामला इनमें से किसी के बेटे

के साथ हो जाए, तब भी हम इसी राय के होंगे कि रनके खिलाफ पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है कि मुजरिम का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए और इस मामले में सी ० एम० साहब की तरफ से भी कोई इशारा नहीं किया गया। पुलिस लोगों की प्रोटैक्शन के लिए होती है लेकिन कभी कभी पुलिस द्वारा लोगों के साथ ज्यादती भी हो जाती है। कई बार पुलिस और लोगों के बीच काफी तनाव भी हो जाता है और मार–पीट भी हो जाती है। (शोर) मेरे आनरेबल साथी जी मुझे नॉन–अवेलेबल मिनिस्टर बताते हैं, स्पीकर साहब, इन्होने खुद मेरे खिलाफ दो मुकद्में दर्ज करवाएं हैं, अपने दो साथियों को छुड़ाने और थाने में घुस कर थाने के सिपाहियों और थानेदार को पीटने तथा मुजरिमों को भगाने क्एय बारे में। (विघ्न) यह बात भी अच्छी नहीं थी। स्पीकर साहब उस वक्त इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके इशारे पर थाने में साधारण लोगों को पीटा जा रहा था, इस कारण वहां पर भीड़ इक्ट्ठी हो गई और उन लोगों को थाने से लोग छुड़वा कर लाए थे। (विघन एवं शोर)

(3) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। श्री कृष्ण मूर्ति हुडडा ने अपनी बात कहते हुए मेरे लड़के के किसी होटल में हुई घटना में इनवाल्यमैंट होने की चर्चा की है, यह टोटली निराधार और बेसलैस है। इस बात में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है।

इस प्रकार की किसी भी घटना में अगर मेरे किसी लड़के के शामिल होने की बात साबित हो जाए तो स्पीकर साहब, जो आप बड़ी से बड़ी सजा देंगे, मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। (विघन) स्पीकर साहब जब इनके पास कोई बात कहने को नहीं होती तो ये इस प्रकार की अनर्गल चर्चाएं करते रहते हैं। इनको शायद मालूम भी नहीं है कि इस सम्बन्ध में इनकी सरकार ने सी० बी० आई० से इन्क्वायरी भी करवा ली है और उस इन्कवायरी में कुछ भी नही निकला। ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा चुके हैं लेकिन वहां भी कुछ तथ्य नहीं मिला। फिर भन ये इस प्रकार के अनर्गल बात करते हैं। स्पीकर साहब, थी कृष्ण मूर्ति हुड्डा के लड़के का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का था कि अगा पुलिस प्रशासन को डी–मोरेलाईज किया जाएगा तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति जो प्रदेश में पहले ही खराब है, और भी खराब हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के लोगों को इनकी पुलिस परेशान करे तो इनको अच्छा लगता है, कालका के उपचुनाव में बूथ कैप्चर किये जाएं पुलिस की मौजूदगी में, तो वह इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, आप प्वायन्ट पर ही बोले।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनकी पुलिस राजस्थान में इनके रिश्तेदारो को जिताने के लिए बूथ कैप्चर कन्ने गई। वहां हमारी पुलिस के लोगों की पिटाई की गई। अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत ठीक बात कही है कि हाउस

के सदस्यों के बेटों की पिटाई की जाती है, उनको प्रोटैक्शन दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चन्द्रावती जी को जब गिला था, तब तो कोई कमेटी नहीं बैठाई गई। सुरजीत कुमार एम० एल० ए० के केस में नहीं बैठाई और कृष्ण मूर्ति हुड्डा के बेटे पर बने केस की बात निराधार मान ली जाती है तो सुरजीत कुमार एम० एल० ए ० की ठीक मानी जानी चाहिये और जबरदस्ती उनके लड़के की शादी नहीं करवानी चाहिये थी। वह लड़की जबरदस्ती उसके गले में मंड दी। मैं तो यह चाहता हं कि अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए परन्तु जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तरह कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा। लेकिन अभी इन्होंने दो–तीन बातें ऐसी कह दी हैं जिनका जवाब देना जरूरी हो गया है। एक तो सुप्रिया कौंड वाली बात है। हमने सी० बी ० आई० वालों को लिख कर दिया या। इसके अलावा और भी कई केस थे, परन्तु उन्होंने कह दिया कि अभी हमारे पास टाईम नहीं है इसलिये उन्होंने इन्कवायरी नहीं की। इसलिये अब नसकी जांच हमारी पुलिस ही करेगी। दूसरे इन्होंने कालका में बूथ कैप्चरिंग की बात कह दी। अध्यक्ष महोदय, इन्हें अपना टाईम याद आता है और ये उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने मेहम में किया था। इन्होंने राजस्थान में संगरिया की बात कह दी। हमारा कोई भी आदमी वहां नहीं गया था। न ही यहां पर बूथ कैप्चर किये गए।

अगर कोई पुलिस में है और वह अगर छुट्टी लेकर जाना चाहे तो वह जा भी सकता है। लेकिन हमने बूथ कैप्चर नहीं करवाए, यह तो आपकी आदत है और आप ही ऐसा करवाते रहे हैं। (विघ्न) इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं और प्रैस भी जानती है। अगर मैं ज्यादा इस विषय में कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बी ० एस ० पी ० के सुरजीत कुमार वाली बात कही है कि हमने धक्के से उनके लड़के की शादी करवा दी है। वह लड़की हिमाचल की है और लड़का यहीं का है। हमने तो सुरजीत कुमार को कहा था कि आप इस बात की तह में जाए और देखें कि अगर वास्तव में रुपी बच्चा लडके का है, तो आपको अपने लड़के की शादी उस लड़की से करनी चाहिए। आपको तो इस बात को सराहना चाहिये। हमने तो उनके साथ नरायणगढ की एक लेडी एस० डी० एम० को भेजा था। बाद में सुरजीत कुमार जी हमारे पास आए और कहने लगे कि लड़के और लडकी की शादी होनी चाहिए। इस तरह से उसने उस लड़की से शादी की। अध्यक्ष महोदय, उसने ऐसा करके बहुत ही शानदार काम किया है। इसके लिए इनको नुक्ताचीनी करने की बजाए उसकी तारीफ करनी चाहिए। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, क्या कोई किसी से जबरदस्ती शादी कर सकता है?

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का अभिवादन

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं अपनी एक बात और कहना चाहूंगा कि आज

इंटरनेशनल महिला दिवस है। मैं इस. अवसर पर प्रदेश की और सारे देश की मातृशक्ति को अभिवादन करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से अपनी वचनबद्धता भी दोहराना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार देश की माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, कल्याण और तरक्की के लिए कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ेगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा एक कालिंग अटेंशन मोशन है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा भी एक कालिंग अटेंशन मोशन है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमने भी आपको रूल 66 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपका यह नोटिस आज ही प्रातः 8.50 बजे आया है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमारा यह प्रस्ताव कालिंग अटेंशन मोशन नहीं ई बल्कि यह स्थगन प्रस्ताव है। मैं आपसे सबमिट करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव हमने इसलिये दिया था कि गर्वनमैंट आफ इंडिया ने बिना पार्लियामेंट से पूछें, गैट समझौते को मंजूरी दी है। स्पीक सर, डंकल ने जो अपना प्रस्ताव

रखा था, जो ड्राफ्ट रखा था, उसको भारत सरकार ने मान लिया है। लेकिन स्पीकर सर, इस प्रस्ताव से आर्थिक गुलामी देश में आएगी, हर उपभोक्ता चीजों के दाम बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह, अभी आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जब आपने मुझे समय दिया है तो मुझे अपनी बात पूरी कह लेने दें। स्पीकर सर, इस प्रस्ताव से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगो, आर्थिक गुलामो आएगी और सारी उप– भोक्ता वस्तुओं के दाम कई गुना मंहगे हो जाएंगे और जो कर्मचारी ऑलरेडी एम्मलायड हैं, वे भी बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनकी छंटनी हो जाएगी। इसके अलावा स्पीकर सर, यह प्रस्ताव इसलिये भी गलत है कि इससे हमारी सम्प्रभुता को ही खतरा पैदा हो जाएगा। स्पीकर सर, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। केवल कृ षि ही नही

श्री अध्यक्षः प्रो० सम्मत सिंह जी, यह अभी अन्डर कंसीड्रेशन है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह स्थगन प्रस्ताव है इसलिये हम यह चाहते हैं कि सारी असैम्बलो युनानी मसली एक रैजोल्यूशन पास करें और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को सुझाव दें कि जो वे 14 तारीख को इस डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत करने जा रहे हैं, वह न करे। स्पीकर सर, 14 तारीख को इस पर दस्तखत हो

जाएंगे और अगले साल से यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा। स्पीकर सर, अगर हम सब एक ऐसा रैजोल्यूशन पास कर दें कि वह इस पर दस्तखत न करे तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ मजबूत होंगे। इसलिये आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर ले। आपके ऐसा करने से उस प्रस्ताव पर सबकी राय आ जाएगी, यहां पर काफी ऐक्सपियरंस्ड लीडर बैठे हुए हैं, उन सभी की राय उसके बारे में आ जाएगी। इसलिये इस असैम्बली को युनानीमसली एक रैजोल्यूशन पास करके भारत सरकार के पास भेजना चाहिए ताकि वह उस प्रस्ताव पर दस्तखत न करे। स्पीकर सर, यह एक मृत्यु की घंटी है, इसको बजने से रोका जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, मैंने कह दिया है कि आपका प्रस्ताव अभी अंडर कंसीड्रेशन है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने जो डंकल प्रस्ताव के बारे में अपनी बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के उस डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत करने से पहले ही इस सदन को युनानीमसली एक रैजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिए ताकि वह उस प्रस्ताव पर दस्तखत न करे। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक और आध प्रदेश की विधान सभाओं ने भी ऐसे ही रैजोल्यूशन पास करके भेजे हैं। अगर यह डंकल प्रस्ताव हो गया तो जिस तरह से पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां पर आयी थी, उसी तरह से यहां पर वहां के बिजसनैसमैन आ जाएंगे और ईस्ट

इंडिया कम्पनी की तरह ही ये लोग देश पर कब्जा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने ने अपनी एक प्रैस काफ्रैंस में एक बात मानी थो कि डंकल प्रस्ताव से दवाईयों की कीमत बढ़ जाएगी दवाइयों की ही नहीं, हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत होने के बाद इसके ऊपर अमल करने पर हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत फैक्ट्रियां सिक हो जाएंगी, बन्द हो जाएंगी, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी से बचने के लिए देश की इकोनोमी को बचाने के लिए मैं समझता हूं कि विधान सभा में यूनानी–मसली एक प्रस्ताव पास करना चाहिये कि डंकल प्रस्ताव पर भारत सरकार दस्तखत न करे। (शोर)

Mr. Speaker : I have already told, it is under consideration.

प्रो० राम विलास शर्मा: स्पीकर सर, में आपसे सबमीशन करना चाहता हूं कि विपक्ष के मेरे साथियों ने जो एडजर्नमेंट मोशन दी है, उस पर आज बहस होनी चाहिये। आपका तो काफी अनुभव है..... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने कह दिया है कि अंडर कसींड्रेशन है।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, आप तो जानते ही हैं कि एडजर्नमेंट मोशन को उसी दिन की कार्यवाही में शामिल किया जाता है। इस बारे में कांग्रेस के लोग जो चाहते हैं, वह कहें। डंकल प्रस्ताव के बारे में इनके क्या विचार हैं, ये भी अपनी

बात कहें, हमें भी अपनी बात कहने दें। ये प्रस्ताव भारत को गुलाम बनाने का एक पैगाम है। अमरीका इस प्रैशर टैक्टिक्स के द्वारा पाकिस्तान के चू भारत को तोडना चाहता है। अमी जेनेवा में मानवाधिकार की बात आ चुकी है। अमरीका के प्रतिनिधि ने वाजपेयी जी को धमकी दी है नि इन प्रस्तावों पर तुम, इतना बावेला क्यों मचा रहे हो? उनका कहना है कि सोवियत रूस टूट गया, भारत टूट जाएगा तो कौन सा आसमान गिर जाएगा? स्पीकर सर, ये देश की एकता का सवाल है, देश की अखण्डता का सवाल है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वैस्ट है कि आप इस पर बहस कराइए ताकि हम इस पर अपनी बात कह सकें।

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received an adjournment motion from Shri Sampat Singh and 11 other M.L.As at 8.50 A.M. Under rule 67 of the Rules of Procedure and conduct of Business notice of adjournment motion is required to be given not less than 1½ hours before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made. The matter is under my consideration. This is my ruling and no speech is permitted now.

चौधरी कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में कल एक काल अटैशन मोशन दिय था। मेरा काल अटैशन मोशन यह था कि झासकेतली से होडल के बार्डर पर, फोर लेन का निर्माण हो रहा है। वहां इरकौन कम्पनी काम कर रही है। वहां हरियाणा के अधिकारी भी नि युक्त हैं, नकी लापरवाही की वजह से रोज ऐक्सीडैटं होते हैं। अभी दवा पर होडल के एक परिवार का

ऐक्सीडैटं हो गया जिसमें एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्पीकर सर, इसी तरह से वहां प्रतिदिन ऐक्सीडैटं होते हैं।

श्री अध्यक्षः आपका काल अटैंशन मोशन अंडर कंसीड़ेशन है।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर सर, आलू की फसल एवं परिजर्वेशन के बारे में मेरी एक काल अटैशन मोशन थी।

श्री अध्यक्षः वह अंडर कंसीड्रेशन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राष्ट्रीय राजमार्गो पर और पशुओं तथा मनुष्यों के लिए क्रार्सिग का उपबन्ध करने तथा राजमार्गो के पास की भूमि पर अवैध कच्चे सम्बन्धी।

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have recieved a Calling Attention notice No. 5, given notice of by Smt. Chandrawati, M.L.A., regarding provision of crossings for cattle and human being on the National Highways and illegal possession of land adjacent to the Highways. I admit it. Smt. Chandrawati may read her notice and the concerned Minister may make the statement thereafter.

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 हरियाणा के बीचों बीच गुजरता है तथा

अब इसे चार मार्गी बना दिया जाएगा। पत्र इस पर पशुओं तथा मनुष्यों के लिए कोई क्रासिंग नहीं है। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय राजमार्गो पर हर 10 किलोमीटर पर पशु क्रासिंग होते हैं। परन्तु हमारे देश में इनका कोई प्रावधान नहीं है। इस यांत्रिक तथा ट्रकों द्वारा सामान बोने के युग में पशु क्रांसिग होना जरूरी है। राजमार्गों पर पशु क्रासिंग. न होने के कारण प्रतिदिन पशु/जंगली जानवर राजमार्गो पा कुचल कर मय जाते हैं। नेवला भी जोकि मनुष्य का मिस्र है इन मार्गो पर कुचल कर मर जाता है। अत. राष्ट्रीय राजमार्गों पा पशु क्रासिंग होने चाहिएं। राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य मुख्य राजमार्गों की ओर मुख करके मकान तथा दुकान बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। इससे राजमार्गों के साथ लगती भूमि का धीरे धीरे नाजायज अतिक्रमण हो जाता है। इसके कारण वाहनों का सुचारू रूप से चलना मुश्किल –हो आता है तथा पैदल चलने वाले भी सुरक्षित नहीं चल सकते। युद्ध के समय यह रुकावटें डाल सकते हैं।

अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य–

लोक निर्माण (भवन तया सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

लोक निर्माण भवन तथा सड़कें मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): अध्यक्ष महोदय, सरकार माननीय श्रीमती चन्द्रावती, एम० एल० ए० के विचारों से सहमत है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 1 जी ० टी ० रोड को मुरथल से करनाल तक चारमार्गी बनाया जा रहा है। इसी तरह करनाल से अम्बाला और आगे हरियाणा–पजांब सीमा तक चौड़ा करने का कार्य स्वीकृत हो चुका है जिसके लिए टैण्डर भी प्राप्त हो चुके हैं और कुछ ही महीनों में इस पर कार्य शुरू होने की सम्भावना है। जी ० टी ० रोड के इन दोनों भागों में आवश्यकता अनुसार. पशुओं तथा पैदल चलने वालों के लिए इस प्रकार के क्रासिंग का प्रावधान भी स्वीकृत है। ऐसे 32 क्रासिंग बनाये जाने हैं। मुरथल से करनाल तक के भाग में जहां पथ निर्माण कार्य चल जाई ऐसे क्रासिंग का निर्माण भी साथ–साथ किया जा रहा है। जी० टी० रोड राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं ० 1 अनुसूचित सड़क अधिनियम के अन्तर्गत एक अनुसूचित मार्ग है और इसकी सीमा से 30 मीटर के अन्दर भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण निषेध है। शहरी क्षेत्र में जहां कहीं भी नगर एवं ग्रामीण आयोजन विभाग या हुडडा द्वारा नई बस्तियां विकसित की गई हैं या की जानी हैं वहाँ पत्र मकानों व दुकानों के मुंह मुख्य सड़क या राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तरफ करने की इजाजत नही है। दूसरे केसों में जहां पर शहरी क्षेत्रों में पहले ही निर्माण हो चुका है वहां पर स्थानीय यातायात की सुविधा के लिए सर्विस सड़कें बनाई जा रही हैं और राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर केवल नियन्त्रित पहुंच ही दी जाएगी। समालखा, पानीपत, घंरोंडा, करनाल, तरावड़ी,

नीलोखेड़ी, पीपली, शाहबाद, अम्बाला छावनी तथा अम्बाला शहर के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के दोनों तरफ सर्विस सड़कें बनाईं जानी हैं। अम्बाला छावनी में रेलवे ऊपर गामी पुल से रेलवे स्टेशन के क्षेत्र और बस स्टैड की तरफ तक। ऊपर गामी मार्गी बनाया लाएगा जहां से सीधा यातायात जाएगा और स्थानीय यातायात ऊपर गामा– पुल के नीचे से गुजरेगा। किंग फिशर पर्यटन स्थल जहां पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 22 निकलता है वहां पर एक ग्रेड– सेपरेटिड क्रासिंग भी बनाने का प्रस्ताव है।

यह भी कथित है कि जहां पर पहुंच सड़कें राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मिलती हैं वहां पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त ढंग से परियोजित जंक्शन बनाने का प्रस्ताव है। इस मार्ग में 184 सड़कें रार्ष्ट्रीय उच्च मार्ग से मिलती हैं। इसके अति– रिक्त आवश्यकता अनुसार ट्रकों तथा बसों को खड़ा करने के लिये ले–बाई कनाने का भी प्रस्ताव है।

इसके साथ ही साथ इस बारे में 'सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि मुरथल अस्सी किलोमीटर पर बनता है। उसमें दस क्रासिंग दिए हैं। पहला क्रासिंग 55,300 किलोमीटर पर, दूसरा 61,520 किलोमीटर पर, तीसरा 64,910 पर, चौथा 75,500 किलोमीटर दर, पांचवा 76.97 किलोमीटर पर, छठा 87.05 किलोमीटर पर, सातवां 109.05 किलोमीटर पर, आठवां 113.25 किलोमीटर पर, नौवां 114.50 किलोमीटर पर और दसवां 117.91 पर। स्पीकर साहब, इसी तरह से मूरथल से पंजाब बोर्डर तक जो

हाईवे बन रहा है, उसमें बत्तीस क्रासिंग का प्रावधान है जबकि टोटल किलोमीटर 182 बनते हैं।

श्री अध्यक्षः क्या आपने देखा है कि सड़क के बराबर कुछ लोग इंटों का एक ढांचा खड़ा कर लेते है और उस पर लाल कपड़ा डाल देते हैं और इस तरह से लोग सरकारी जमीन का ऐनक्रोचमैंट करते हैं। क्या आपने पी० डब्ल्यू० डी० अथौरटीज की डयूटी लगा रखी है कि वे सड्कों के बराबर में देखें कि कहीं ऐनक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है?

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो सड्कों के पास ऐनक्रोचमेंट है, उसको हटाने का काम पूरे जोर शोर से आलरेडी चल रहा है। जो एनक्रोचमेंट हैं, उनको हम हटवा रहे हैं। जो भी व्यवधान हैं, हरियाणा सरकार सब को हटवा देगी।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Irrigation Mlnister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to lay on the Table-

(i) The Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1991-92 as required under Section 75(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(ii) The 26th Annual Statement of Accounts of the

Haryana State Electricity Board for the Year 1992-93, as required under Section 69(5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(iii) The Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1994 as required under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

वर्ष 199 4– 95 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble members, now general discussion on the Budget for the year 1994-95 will take place.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के वित्त मल्टी श्री मांगे राम गुप्ता ने वर्ष 1994– 95 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और आज के अखबारों में बहुत बड़ी सुर्खियों में छपा है ''कर रहित बजट पेश किया गया है ''। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी कांग्रेस सरकार की एक प्रथा रही है कि बजट में तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाता लेकिन बजट से पहले इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं कि बजट में कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पिछले दिनों बिजली के रेट बढ़ाए गए। ट्रांसपोर्ट में बसों के किराए बढ़ा दिए गए। डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। खाद के भाव बढ़ा दिए गए। खाने पीने की चीजें जो जरूरियातें जिन्दगी में आती हैं उनके भाव बढ़ाए गए जैसे राशन में चीनी के रेट बढ़ा दिए गए, चावल के रेट बढा दिए गए और गेहूं के भाव बढा दिए गए। स्पीकर साहब, इसके बाद कोई विस्तार से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बजट से

पहले ही इतने टक्स लगा दिए हैं जिससे कि उपभोक्ता की कमर टूट गई है।

अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया ई उसमें कई बातें छिपा ली गई हैं। आप कैपीटल ऐक्सपैडीचर को देखिए वर्ष 1992–93 में 228.34 करोड़ रुपया, 1993–94 में 314 करोड़ और वर्ष 1994–95 में फिर 214 करोड़ हो गया है। रससे जाहिर है कि विकास के काम ठप्प हो जाएंगे और यह अनुमानित राशि पूरी न होने के क्षरण प्लान में कटौती होगी जैसे पिछले सालों में प्लान में कटौती की गई थी। यह लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो रैवेन्यू ऐक्सपैंडीचर सोशल एकोनोमिक सर्विस का 1992–93 का है, वह 1021 करोड़ रुपये है जबकि टोटल 2379 करोड़ रुपये है। 1993–94 का सोशल इकनामिक सर्विस का 1937 करोड़ रुपये है और टोटल 3533 बनता है। इस प्रकार से 1994–95 में 2785 करोड़ रुपये है और– टोटल 4818 हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रैवेन्यू ऐक्सपैडीचर के मामले में हरियाणा स्टेट सरप्लस स्टेट रही है और जहां एक तरफ विकास के कार्य हो ही नही पाएंगे और इसी प्रकार से यह जो रैवेन्यू डेफीशिट है, वह 512 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अन्देशा है। इसी तरह से ओरिजनल प्रोपोजड जो 1992–93 की मन्जूरशूदा प्लान में राशी दिखाई गई है वह है 850 करोड़ रुपये जबकि वास्तविक खर्च 752 करोड़ रुपये का दिखाय गया है 1993–94 में

भी 920 करोड़ और वास्तविक खर्च 881 करोड़ रुपये का दिखाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 1994– 95 में 1025 करोड़ के लगभग दिखाया गया है। इन्हीं के अपने बताये हुए आकड़ों के मुताबिक ही डेढ सौ, पौने दो सौ करोड़ रुपये का घाटा साफ दिखाया गया है और यह घाटा आगे बढ़ भी सकता है। ऐक्साईज रवेन्यू 1992–93 में 393 करोड़ और 1993–94 में 91 करोड़ बजट में रखा था और अपने संशोधित अनुमान में 445 करोड़ ज्यादा लगाया गया है। असल में यह 400 करोड़ रुपये तक मुश्किल से ही पहुंच पाएगा। 1993–94 के बजट में अनुमानित आय 582 करोड़ रुपये दिखाई गई है। यह आकड़े भी गुमराह करने वाले हैं। आमदनी होगी नहीं, फिर यह घाटा घटते घटते कहा तक पहुंच जाएगा और फिर यह कटौती विकास के कार्यो में ही होगी या फिर वृद्धा पैन्शन पर कट लगेगी। पिछले साल की इस कटौती का परिणाम यह निकला है कि हरियाणा प्रदेश के बूढ़े बुजुर्गो को जो सम्मानित पेशन मिलती थी, वह भी इस सर– कार ने बन्द कर दे'। आखिर जाकर यह सारी मार उन पर ही पड़ी है। मुख्य मन्त्री महोदय, ने हाऊस में यह कहा है कि पैन्शन हम हर हालत में देने जा रहे हैं, बहत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री के आश्वासन हाउस में माने जाते हैं, निभाये भी जाते हैं और उम्मीद है कि यह आश्वासन भी निभायेंगे लेकिन बजट में जो प्रावधान किया गया है, नसके मुताबिक साढ़े 92 करोड़ रुपये रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अमी

7 महीने पैन्शन के बाकी हैं और पैन्शन अगर दी जाएगी तो लगभग 50 करोड़ रुपया उसी में चला जाएगा। केवल मात साढ़े 45 करोड़ रुपये की राशि बचेगी। साढ़े आठ लाख पैमान लेने वालों की जो संख्या है, पता नहीं यह पैसा कैसे वितरित करेंगे। वित्त मनत्री महोदय इस मामले में सियाने हैं और ऐसी कम्युनिटी से जुडे हुए हैं जो हिसाब के लेखे जोखे में माहिर भी हैं, मेरी इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि 11 महीने में यह 40 करोड़ रुपया उन वृद्ध व वृद्धाओं को पैन्शन की शक में कैसे दे पाएंगे? वैसे तो हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं है कि ये किसी को सम्मानित पैन्शन दे सकेगी।

हरियाणा सरकार पैन्शन तो देगी लेकिन पैन्शन देगी चौधरी लहरी सिंह को, चौधरी पीरचन्द को, चौधरी शेरसिंह को, थी सुरेन्द्र कुमार मदान को या फिर भजन लाल को जिन्होंने डिफैक्शन करने की प्रथा कायम की हुई है। ये इन दल बदलुओं को हो पैन्शन देगें।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये दलबदलू हम को बताते हैं जबकि वे दलबदलुओं के सरदार खुद है। (शोर) जिनके पिता श्री' ने 21 दफा दल बदल कर रखा हो और वे फिर दलबदलुओं की बात करें? (हंसी) और कोई दूसरा यह बात कहे तो समझ में भी आए लेकिन ओम प्रकाश जी, आपको तो यह बात कहना यहां पर शोभा नहीं देता।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसके स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं हैं। न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि सारे देश में भजन लाल डिफैक्शन का सरदार माना गया है।

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे दल बदलू कहा है। जब मैं इनकी पार्टी छोड़ कर आया था तो मैंने एम० एल० ए० के पद से भी अस्तीफा दे दिया था। मुझे जनता ने चुन कर भेजा है, मैं चौटाला के आर्शीवाद से चुन कर नहीं आया हूं।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, चूंकि इन्होने मेरा भी नाम लिया है, इसलिये मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, ये तो ऐसी बात कह रहे हैं, जब चौधरी देवी लाल की सरकार शुरू में बन कर आई थी तो इनको 76 एम० एल० एज० प्लेट में रख कर दे दिये थे। दूसरी बार 85 एम० एल० एज० प्लेट में रख रख कर दे दिए। एक लहरी सिंह का कसूर हो सकता है, शेर सिंह का कसूर हो सकता है और चौधरी भजन लाल का कसूर हो सकता है लेकिन ये 85 एम ० एल० एज ० होते हुए अपनी सरकार तुड़वा कर घर बैठ गए थे और इनके पास केवल 17 एम० एल० एज ० रह गए थे। यह तो किसी का कसूर नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम इनके रहम पर बन कर आए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय चौटाला साहब ने इस बार भी ऐडी–चोटी का जोर लगा लिया और पिछली बार भी

जोर लगाया था। मैं तो रादौर हल्के की जनता के आर्शीवाद से तथा अपने दम पर बन कर आया हूं। इनका उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं इनको कहता हूं कि ये आगे भी जोर लगा लें, लोगों के आर्शीवाद से फिर बन कर आऊंगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि ये इस किस्म के लोगों को जरूर पैन्शन देंगे जिसकी वजह से प्रदेश के मान सम्मान पर चोट पड़ेगी। ये पैन्शन देंगे तो सरदार हरपाल सिंह कौ देगे जिनके .....

श्री अध्यक्षः ये शब्द रिकार्ड न किए जाए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, असली बात को हाउस की कार्यवाही से नहीं निकाला जाना चाहिये।

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है, ऐसी बात इनको कहनी नही चाहिए थी। इस बात में कोई सदाकत नहीं है और यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्षः वह मैंने पहले ही कह दिया है कि. यह शब्द रिकार्ड न किये जाएं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः तो अष्यक्ष महोदय, में बता रहा था कि जिन वृद्धों को चौधरी देवी लाल ने सम्मान की दृष्टि से सम्मानित पैन्शन दी थी उनको अब पैन्शन नहीं मिल रही है और न आगे मिलने की उम्मीद है। इससे ज्यादा दुखदाई बात

और क्या होगी? सरकार की तरफ से उन बूढ़ों को नोटिस इशू किए गए हैं कि जो पैन्शन आपको पहले मिली हुई है, वह आप सरकारी खजाने में वापिस दाखिल करवाएं। अब पैन्शन के लिए जो इन्होंने प्रावधान रखा है, उसके हिसाब से लोगों को पैन्शन नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से सेल्ज टैक्स के तहत 1992– 93 में इनकी 717 करोड़ रुपए की वसूली एस्टीमेटिड थी लेकिन ये 676 करोड़ रुपए वसूली कर पाए हैं। इसमें 41 करोड़ रुपए की वसूली कम हुई है जबकि अनुमानित से ज्यादा वसूली होनी चाहिए। इसी तरह से 1993–94 में 790 करोड़ रुपए का अनुमान था और संशोधित अनुमान 780 करोड़ रुपए का हैं। जनवरी, 1994 तक के रैवेन्यू ट्रेड को देखते हुए यह 725 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जा पाएगी। इसी तरह से 1994–95 में 897 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रखा हुआ है। इसमें भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुमान किया गया है। गुप्ता जी ने बड़ी होशियारी से आकड़े पेश करने की कोशिश की है। इससे प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो पाएगा। ये किस तरीके से पैसा अर्जित करेंगे और उसे कहां लगायेगे। मैं हाउस के सदस्यों को कहूंगा कि इसको गहराई से देखें। इसी तरह से पिछले साल के प्रोवीडैटं फंड के 212 करोड़ रुपए के एस्टीमेट के हिसाब से इस साल 294 करोड़ रुपऐ का ये अन्दाजा लगा कर चलते हैं। अगले साल इसका 328 करोड़ रुपए मान कर चलते हैं यानि 50 या 60 करोड़ रुपए एक्सैस मान कर चल रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं है। इनको स्माल सेविंग के लिए पिछले साल 228 करोड़ रुपए मिला, इस साल 257 करोड़ रुपए

मिले और अगले साल 337 करोड़ रुपए का इनका निशाना है। अध्यक्ष महोदय यह सरकार स्माल सेविंग का पैसा किस प्रकार से इकट्ठा करेगी। स्माल सेविंग का पैसा इक्ट्ठा करने वाले अधिकारियों ने स्टार नाइट कन् के स्टेडियम के लिये जिनसे यह पैसा वसूल करेंगे उनसे स्माल सेविंग का पैसा कैसे वसूल करेंगे। सिरसा के बारे में अखबारों में छपा है। उस बारे में तो लछमन दास अरोड़ा ज्यादा रोशनी डालेंगे इनको उस बारे में ज्यादा पता है। लेकिन जिस तरी के से यह पैसा दुकानदारों से इकट्ठा किया जाता है उसकी वजह से जहां चर्चाएं गलत चलती हैं वहां सरकारी अधिकारी अपना बहुमुल्य समय प्रशासन को ठीक चलाने में खर्च न करके बर्बाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सिरसा में स्टेडियम बने हमें कोई एतराज नहीं। वह स्टेडियम चौधरी दलबीर सिंह के नाम पर बने हमें कोई एत– राज नहीं। चौधरी दलबीर सिंह ने इस हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छे काम किए हैं। लेकिन हरियाणा के सरकारी अधिकारी उसके लिए व्यापारी से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा करने के लिए जो तरीका आखित्यार कर रहे हैं उससे आम आदमी भार महसूस करता है। इसी तरीके से आज राजनीतिक चन्दा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से वसूल किया जाता है। इस प्रकार की बातें रोज उठती हैं। कहां से किस तरीके से पैसा वसूल कर पाएंगे। कैपिटल एक्सपैडींचर के बारे में तो मैं बता चुका हूं। अब ये पैसा वसूल करने जा रहे हैं वह पैसा इनको किन किन मदों से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक तरीके से इन डायरैक्ट टैक्स के रूप में पैसा वसूल करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,

टैक्स वसूल करने में स्टेट का कोई नुक्सान नहीं होना चाहिए। इस सरकार को पथकर टैक्स के 71 करोड़ रुपए मिले थे लेकिन अब इनको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब ट्रक आप्रेटर्ज पर 1500 रुपए एक साल का पथकर टैक्स था उस समय सरकार को 71 करोड़ रुपये मिले थे लेकिन अब 1500 रुपये की बजाय 5000 रुपए एक साल का किया जाएगा इसलिये वह आमदनी घट कर 30 करोड रूपए साल की हो गई। जो आमदनी होती थी उसको इस तरह से घटाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लाटरी के बारे में अखबारों में चर्चा विस्तार से हुई हे। कुछ लोग लाटरी को बन्द करने के पक्षधर हैं और कुछ लोग इसका चलाने के पक्षधर हैं। जिस तरीके से लाटरी का सिस्टम चल रहा है। पिछले साल लाटरी में 36 करोड़ रुपए खर्च हुए और 36 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। वित्त मंत्री जी ने बजट में दिखाया है कि इस साल लाटरी पर 670 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 760 करोड़ रुपए की आमदनी होगी यानि 90 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। लाटरी से 760 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे जिसमें से 90 करोड़ रुपए सरकारी कोष में आएंगे। 800 करोड़ रुपया उन लोगों से वसूल किया जाएगा जो रिक्शा पुलर हैं, कुली हैं जो खोमचे वाले हैं अध्यक्ष महोदय, 90 करोड़ रुपए का लाभ किन लोगो को पहुंचेगा शायद वह लाभ कमिशन एजेंट को पहुंचेगा। विल मेंती जी. इस बारे में स्पष्ट करें जो जनता के हकों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं या कमीशन एजेन्टों के हकों का। लाटरी के घोटाले की चर्चाएं चली। अध्यक्ष महोदय, लाटरी की टिकटें जो

लोग प्राइवेट लाटरी वाले छपवाते हैं उनकी सस्ती छपती है लेकिन इस सरकर ने जो लाटरी की टिकटें छपवाई, वह मंहगी छपवाई। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होग कि जिस अनुपात से लाटरी छपती है, उस पर 80 हजार रुपए रोजाना फालतू लगते हैं। यानि एक दिन में 80 हजार रुपये फालतू लगते हैं। इस प्रकार एक साल के ये साढ़े तीन करोड़ रुपये हो जाते हैं। इस का फायदा केवल अपने मंजूंरेनजर लोगों को पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट लाटरी वालों कीं कम दाम पर टिकटे रखती हैं जबकि इनकी मंहगे दाम पर छपती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी लाटरी ज्यादा खूबसूरत है? मेरे कहने का मतलब यह है कि लाटरी के नोम पा ये गरीब लोगों से टैक्स वसूल का रहे हैं। क्या आपको ज्यादा लाभ होने जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं, उसको सुनकर आपको हैरानी ही नहीं बल्कि परेशानी भी होगी। ये अपना खर्चा पूरा करने के लिए लोगो से इन्डायरेक्ट रूप से पैसा वसूल कर रहे हैं। सोशल वैल्फेयर विभाग द्वारा मासूम बच्चों को, जो खाद्य सामग्री दी, जाती थीं, उसके लिए इस साल तो इन्होने 65 करोड रुपये रखे थे जो अब कम करके 53 करोड़ रुपए रख दिए हैं। यानि इस तरह से मासूम बच्चों की खुराक के भी 12 करोड़ रुपए काट लिए गए हैं। क्या इस प्रकार हे ये हरियाणा का विकास बढ़ाने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट में बताया है कि वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इस साल इनको 2 करोड़ 98 लाख रुपये की आमदनी हुई और अगले साल इस स्कीम के तहत इनको 8 करोड़ 58 लाख रुपए कीं आमदनी होगी। यानी ये लोगों से 6 करोड़ रुपये ज्यादा लेंगे। क्या यह जो 6 करोड़ रुपये ज्यादा लेंगे, यह टैक्स नहीं है? पैसा लोगों से डायरेक्ट नही लिया तो इन्डायरेक्ट रूप से टैक्स के रूप में ले रहे हैं, एक ही बात है। पीने के पानी की योजना की तरफ ध्यान देने की बजाये इनका ध्यान लोगों से पैसे वसूल करने की तरफ है। लोगों से इस तरह पैसा लेकर ये अपना प्रशासन चला रहे हैं और कह रहे हैं प्रदेश में चहुंमुखी विकास करे गे। सिंचाई के क्षेत्र में पिछले साल में इन्होंने 17 करोड़ 96 लाख रुपए अर्जित किए हैं जबकि चालू साल में 21 करोड़ 51 लाख रुपये वसूल किए हैं। अगले साल के लिए इनका 61 करोड़ 48 लाख का अन्दाजा है। सिंचाई के दाम इन्होंने एक तरह से चालू साल की अपेक्षा अगले साल के लिए तीन गुणा बढ़ा दिए। यह पैसा ये किसानों की जेब से निकलवा रहे हैं। यानि किसानों को, चालू साल की अपेक्षा अपनी जेब से सरकार को तीन गुना अधिक पैसा देना पड़ेगा। इन्होने हर मामले में तीन का पैमाना बना लिया है। किराया बढ़ाएंगे तो तीनै गुणा बढ़ाएंगे। खाद का रेट बढ़ाएंगे तो साल में तीन गुणा बढ़ाएंगे और बिजली के रेट बढ़ाएंगे तो वे भी साल में तीन बार बढ़ाएंगे। पानी का रेट बढ़ाएंगे तो वह भी तीन गुना बढ़ाएंगे। इनकी नहरों में सिंचाई के लिए तो क्या, पीने के पानी का भी प्रबन्ध नहीं है। जब बाढ़ आई

थी तो उस समय इनकी सारी नहरें बेकार हो गई। इनकी नहरों में अधिक पानी लेने की क्षमता ही नहीं है। बाढ़ के कारण लोगों का बुरा हाल हुआ और लोगों का सब कुछ बरबाद हो गया। मुख्य मन्द्री हाउस में कहते हैं कि मुसीबत जदा लोगों की पूरी मद्द की जाएगी। मद्द तो क्या करनी थी, उल्टे उनके आबियाना तक माफ नहीं किए गए। यहां तक कि बाढ़ की वजह से उनके ट्यूबवैल भी बरबाद हो गए। जब इस बारे में हम कुछ कहते हैं तो ये यहां हाउस में खड़े हो का कहते हैं कि पानी का पूरा प्रबन्ध नहीं है क्योंकि पैसे हमारे पास नहीं है। अब सिंचाई मन्द्री महोदय कोई दस्तखत करके आए हैं और कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से 800 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब पैसा मिलने की उम्मीद है तो फिर ये उसी पैसे से काम चलाएं, फिर क्यों किसानों से यह पैसा दूसरे रूप में लेते हैं? स्पीकर साहब, दें बताना चाहता हूं कि भाखड़ा नहर से 12.50 हजार क्यूसिक पानी लेने की क्षमता है लेकिन ये उस नहर से सिर्फ 7, 7.50 हजार क्यूसिकस पानी ही ले पा रहे हैं। यानी पांच हजार क्यूसिकस पानी कम ले रहे हैं। कम पानी लेने का कारण यह है कि जो इस नहर के बैक्स हैं, वे कमजोर हैं, और इस की सिल्टिग नहीं निकाली जा ग्ही यानी ये नहर को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहे हैं। एस ०वाई०एल० नहर के बारे में मुख्य मन्त्री हाउस में कहते हैं कि यह नहर तो मेरे समय में बननी शुरु हुई थी और मैं ही इसे पूरी करवाऊंगा, तुम लोगों ने कुछ नही किया। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने एस ०वाई०एल० नहर के लिए जो खर्चा मन्जूर किया है, वह केवल

11 करोड़ रुपये मन्जूर किया है। यह एस ०वाई०एल० के लिए जो 11 करोड़ रुपये मन्जूर किए गए हैं, यह तो एस ०वाई०एल० की एस्टेब्लिशमैंट पर ही खर्च हो जाएंगे। पिछले साल तो 20 करोड़ रुपये पंजाब सरकार के कर्मचारियों को इस वसे में से मिल गए थे। अब मंहगाई भी काफी बढ़ गई है और मंहगाई भत्ता भी बढ़ाना पड़ेगा जिस पर 11 करोड़ रुपये से काम नहीं चलेगा। स्पीकर साहब, एस ०वाई०एल० नहर के बारे में मन्त्री कभी कोई ध्यान दे देते हैं कभी कोई ध्यान दे देते हैं। मुख्य मन्त्री जी ने ब्यान दिया कि हम 6 महीने के अन्दर अन्दर एस० वाई०एल० का पानी ला देंगे। इनकी बात समझ में नहीं आती, इन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने इनको आश्वासन दिया है कि नहर बन जाएगी। उधर पंजाब के मुख्य मन्त्री का ब्यान आया कि मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। इनकी कौन सी बात सत्य है यह समझ में नहीं आती? स्पीकर साहब, आज प्रदेश में सिंचाई की बुरी हालत है, पूरे प्रदेश में पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। एस० वाई०एल० नहर का जो पैसा है, वह तो सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से आता है। आज केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें हैं। मुख्य मन्द्री जी ने व्यान दिया था और हाउस में कहा था कि 19 तारीख को केन्द्र के साथ बैठक होने वाली है जिसमें पानी के वारे में फैसला किया जाएगा। आज केन्द्रीय मन्त्री ने ब्यान दिया है कि 19 तारीख को कोई बैठक होने वाली नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने यह बात शायद इसलिए कह दी होगी कि यह सैशन 18 तारीख तक चलेगा

इसलिए 18 तारीख कौ तो बात टल जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे। इनकी कोई बात समझ में नहीं आती कि ये क्या सत्य कह रहे हैं? स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि एस ०वाई०एल० नहर का पानी में ही हरियाणा में लाऊंगा। हरियाणा में एस ०वाई०एल० नहर का पानी तो इन्होंने क्या लाना था, दूसरी तरफ जमुना के पानी में पंजाब के शेयर की बात और उठ खड़ी हुई और इस प्रकार से यमुना का पानी हरियाणा से पंजाब को चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है क्योंकि आपका एरिया भी जमुना के पानी से सैराब होता है। जमुना का 273 पानी का हिस्सा हरियाणा को मिलता है और 1/3 हिस्सा यू०पी ० में जाता है। इसके अलावा, किसी और स्टेट का इसमें कोई दखल नहीं था। हमारे इन मुख्य मन्त्री जी की वजह से यमुना के पानी पर 4 और दावेदार बन गए हैं। चार अन्य सरकारें इस पानी पर अपना दावा जता रही हैं। इनकी वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकार अपना हिस्सा मांग रही हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बेअन्त सिंह जी ने कहा है कि एस०वाई०एल० नहर तब तक नहीं बनेगी, जब तक जमुना का पानी पंजाब को नहीं दिया जाता है। एस ०वाई० एल० नहर का जमुना के पानी के साथ कोई मेल नहीं था परन्तु यह इनकी वजह से हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत ही पुराने मैम्बर रहे हैं और 3– 4

बार इन्होंने मुख्य मन्त्री की भी शपथ ली है, भले ही 3 महीने के लिए मुख्य मन्त्री रहे, कम से कम हाउस में इनके ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे स्टेट के हितों को कोई नुक्सान हो सकता हो। जमुना के पानी में किसी का कोई शेयर नहीं है और न ही भारत सरकार ने यमुना के पानी पर किसी स्टेट के दावे को माना है। इसमें हिमाचल प्रदेश का कोई शेयर नहीं है। पंजाब का कोई शेयर नहीं है। यू०पी० का शेयर 173 है जो सब को पता है। दिल्ली और राजस्थान का पीने के पानी का शेयर जरूर है, बाकी का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात कह कर ये स्टेट के हितों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं। इनकी बात अखबारों में जाएगी जिसकी बजत से स्टेट के हितों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला आप स्वयं करें कि हाउस को मैं गुमराह कर रहा हूं या लीडर आफ दि हाउस, हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का व्यान अखबार में छपा है जिसमें क्लीयर कट कहा गया है कि एस० वाई ०एल० नहर का काम तब तक नहीं होगा, जब तक यमुना का पानी पंजाब को न मिल जाए। अध्यक्ष, महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० नेहर कें मामले पर मारा हरियाणा इनके साथ है। इस हाउस के 90 के 90 सदस्य इनक साथ देंगे और सारे का सारा हरियाणा इस मुद्दे में इनका साथ देगा, अगर ये एस० वाई०

एल० नहर के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाएं। हरियाणा के हितों की हिफाजत के लिए ये डट कर खड़े हो जाएं तो 90 विधायकों के साथ ही सारा हरियाणा इनके साथ होगा अगर ये एक बार सकने से डट जाएं तो हरियाणा के हितों के साथ अन्याय नहीं हो सक्का। सारा हरियाणा मजबूत हो कर इनके साथ होगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनके लीडर ने माना था, आज वे संसार में नहीं हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि 28 जनवरी को चण्डी गढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, पंजाब के गवर्नर झण्डा लहराएसे 1 इसके लिए वर्दियां भी बन चुकी थीं और सारी तैयारियां हो गई थीं। चौधरी देवी लाल के सशक्त नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने एक जुट हो कर हरियाणा के हितों की रक्षा की थी। (विघ्न) स्पीकर साहब, मुझे प्रसन्नता होगी, अगर लीड, आफ दि हाउस इस प्रकार आ कोई रैजोल्य्शन पास करवाएं कि हरियाणा के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होगा, इनके इस कदम की हम प्रशंसा करेंगे।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयन्ट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात 1986 की है, जब राजीव गांधी जो ने फसला कर लिया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे देंगे। उस वक्त चौधरी भक्त लाल जी मुख्यमन्त्री थे, चौधरी देवी लाल नहीं थे। तो चौधरी भजन लाल जी मे कह दिया था कि मैं इस के विरोध में इस्तीफा देता हूं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब तो बंसी लाल जी दे देंगे क्योंकि यह इनकी पार्टी का आन्तरिक मामला था। मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता कि इस्तीफा लिया गया था या दिया गया था। मैं पार्लियामैंटरी मिनिस्टर जी को बताना चाहता हूं कि उस वक्त हमने रास्ता रोका था और उस आन्दोलन में हमारा एक आदमी भी शहीद हो गया था। उसका एक स्मारक आपके गांव में बना हुआ है। आज कल ये लोग गांवों में जाते नहीं हैं, इसलिए इनका पता नहीं है।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आर्फ आर्डर है कि जब वइ 'रास्ता रोकने की बात हुई थी तो यह बात चौधरी देवी लाल जी ने कही थी। ओम प्रकाश चौटाला तो इस 'रास्ता रोको' आन्दोलन में शामिल ही नहीं थे और ये उसके खिलाफ थे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय एक कहावत है कि किसी को मारना हो तो मारने वाले पशु के सिंग पकड़ा दें। ये ऐसा असत्य बोलते हैं उसका क्या इलाज है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में बिजली की क्या हालत है।

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। अभी चौटाला जी एस ० बाई० एल० नहर के बारे में बोल रहे थे। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब

चौधरी देवी लाल जी मुख्यमन्त्री थे और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी थे, वे कहते थे कि हम हरियाणा को पानी नही देंगे और ये कहते थे कि हम पानी लेंगे। यह तो एक पोलिटीकल मामला था। ये यह बताए कि इनके राज में दक्षिणी हरियाणा को पानी क्यों नहीं मिलता था? क्या येबताएंगे कि दक्षिणी हरियाणा के साथ क्यों भेद भाव बरता जाता था? वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। इस बारे में ये स्पष्ट कर दें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम किताब सिंह है लेकिन इन्हें कुछ किताबी ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी के मामले में पंजाब के लोग इक्कठे हैं तो हमारे हरियाणा के लोगों को इस मामले में इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किताब सिंह जी, आप बैठ जाएं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बिजली का उत्पादन फरीदाबाद थर्मल प्लांट से 163 मैगावाट, पानीपत से 330 मैगावाट जमना नगर हाईडल प्रोजैक्ट से 48 मैगावाट भाखड़ा से 554 मैगावाट डेहर से 317 मैगावाट, पौंग डैम से 6० मैगावाट, इन्द्रप्रस्त से 62.5 मैगावाट है औप एन० टी ० पी ० सी ० से हम जरुरत के मुताबिक बिजली लेते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज बिजली का उत्पादन घटा है। हमारी सरकार के वक्त

में जो उत्पादन 40 परसैंट था, वह आज घटकर 32 परसैंट रह गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आकड़ों में ये 27 परसैंट दिखाते हैं। लेकिन चालीस परसैन्ट तक ही लाईन लौसिज है जबकि हमारी पार्टी की सरकार के वक्त में यह लाईन लौसिज 21 परसैन्ट थे। अध्यन् महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में 50 हजार यूनिट बिजली एन ० टी ० पी ० सी० और एन० एच० पी० सी० से लो जा ग्ही है। यह बिजली सबसे महंगे रेट पर ली जा रही है यानी तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी पार्टी की सरकार थी दो उस बक्त हम सारी बिजली 239 लाख यूनिट लिया करते थे जबकि ये 28 लाख यूनिट बिजली ले रहे हैं। हमारे वक्त में 239 लाख यूनिट बिजली मिलने के बाद भी 24 घंटे किसानों को बिजली मिलती के, किसानों के खेत सूखे नहीं थे उद्योग–धंधे पलायन करके नही गये थे लेकिन इनके समय में ज्यादा बिजली लिये जाने के बावजूद भी लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली के बारे में जब भी कहने का मौका आता है तो ये कह देते हैं कि हमारी सरकार की वजह से बिजली का उत्पादन कम हो गया था क्योंकि हमने कोई भी थर्मल प्लांट नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस की जानकारी के लिये यह बात कहना चाहूंगा कि पानीपत थर्मल प्लांट की चौथी यूनिट जो 110 मैगावाट की है, वह हमारे समय में ही तैयार हुई थी इसके अलावा उसकी पांचवी यूनिट भी जो 210 मगावाट की है, वह भी हमारे समय में ही तैयार हुई थी और छटी यूनिट का 90 प्रतिशत पैसा उस सरकार के समय में ही मंजूर हो गया था

और बी ० ई० एल० को मशीनरी का आर्डर दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, दो साल से पानीपत रेलवे स्टेशन पर वह सारा सामान पड़ा हुआ है तथा उस पर डैमरेज लग रहा है। लेकिन सरकार उसको छुड़वा नहीं रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि इनके पास पैसा ही नही है। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि उस प्लांट की चारों यूनिट काम नही कर रही हैं। यह तो ठीक है कि परमात्मा की कृपा हो गयी और बारिश हो गयी जिसकी वजह से किसान बच गए। अध्यक्ष महोदय, अब तो गेहूं के लिये दो पानी अति– आवश्यक हैं लेकिन अगर बिजली की यही स्थिति रही तो जो गेहूं पकने को है, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जब पैडी का सोयिंग सीजन आएगा तो हमारे पास बिजली का बहुत ही अभाव हो जाएगा और इसकी वजह से सारे देश में जो हरियाणा चावल पैदा करने में पहले नम्बर पर आता है, वह नहीं आ पाएगा। हमारी ग्रो मोर पोलिसी भी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। इसलिये सरकार को इस मामले पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सब कामों को छोड्कर सरकार को इस पर ही तवज्जो देनी चाहिये। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो बिजली के अभाव की वजह से प्रदेश की खेती चौपट हो जाएगी। सारे उद्योग धंधे भी बन्द हो जाएंगे मजदूर बेकार हो जाएंगे और प्रदेश में अनाज की कमी आ जायेगी प्रदेश में अफरातफरी मच जाएगी। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, आपकी अभी से ही घंटी बजनी शुरू हो गयी। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि आप मुझे कुछ ज्यादा समय देंगे। मुझे लगता है कि यह छटी आपने किसी और वजह से बजायी होगी। शायद आपने

पानी मंगवाया होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका एक ओबेडियन्ट स्टूडैन्ट हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इन्होंने डोमैस्टिक बिजली कनैक्शन 22 लाख कौमर्शियल बिजली कन्फैक्शन दो लाख 85 हजार और इंडस्ट्रियल बिजली कनैक्शन 74 हजार दिये हैं। लार्ज स्केल पर जो फर्निस के कनैक्शन दिये, वह 400 दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ट्यूबवैल्ज कनैक्शनज का बड़ा बुलन्दबांग दावा करते हैं कि हमने 1992–93 में 14376 ट्यूबवैलज को बिजली ले कनैक्शन्ज दिए हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी, तब हमने आर० ई० सी ० से 25 हजार कनैक्शन्ज मंजूर करवाए थे और इसी वजह से ही आज यह इनका खाता बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह ज्यादा कनैक्शन्ज देने वाले होते तो 1993– 94 में इनकी कनैक्शन्ज देने की सारी संख्या 3533 ही क्यों रह जाती? आज भी कमैक्शन्ज लेने के लिये 60–70 हजार दरख्वास्तें पैंडिंग पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब तो कनैक्शन्ज लेने की भी स्थिति नहीं रही है, जैसे प्रो० सम्पत सिंह ने विस्तार से बताया लेकिन मैं इसके लिये ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि अब एक ट्यूबवैल्ज का कनैक्शन्ज लेने के लिये कम से कम 35 या 40 हजार रुपये किसान के पास होने चाहिएं। अगर किसानों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो उसको कनैक्शन नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा अंदेशा यह है कि ये बिजली किसान को पूरी देने का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं जै से हवा में चर्चाएं भी भी रही हैं कि ये पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांटस को एन०

टी ० पी० सी ० को देने जा रहे हैं। अगर ये प्लांटस एन० टी ० पी० सी० को चले जाएंगे जैसे कि इनकी आदत रही है, तो ये हरियाणा प्रदेश की सम्पत्ति को बेच रहे हैं। जैसे इन्होंने जींद की टैनरी को बेचा, मुरथल की ब्रिचरीज को भी बेचने जा रहे हैं। ये हिसार की कानकास्ट को भी बेचने की योजना बना रहे हैं। इन्होंने तो प्रदेश की सम्पत्ति को यूं ही समझ लिया है और इन्होंने सोच लिया है कि हमें जितना भी समय मिला है, उसमें प्रदेश की सम्पत्ति को लूट लिया जाए। हरियाणा प्रदेश में इनके जगह जगह किस्से छपते हैं लेकिन मैं उनके बारे में तो बाद में बताऊंगा। यहां से भी सह नहीं हुई, अश्व तो दिल्ली की संपत्ति को हथियाने के लिये हाउस के सत्रह विधायकों, वजीरों और पार्लियामैंट के मैम्बरों की एक कमेटी बनाई गई है, एक सोसायटी बनाई गई है जिसका दायरा (क्षेत्र) दिल्ली तक बढ़ा दिया है। मैं आपके द्वारा मुख्यमन्त्री से पूछना चाहूंगा श्री अध्यक्ष वह कमेटी तो आपके टाइम में बनी थी.।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, वह मेरे टाईम में नहीं बनीं, मेरे टाईम में कोई सोसायटी नहीं बनी। आपको किसी ने गुमराह किया है इसलिये आप उसकी पड़ताल करवा ले। यह जो सोसायटी का रजिस्ट्रेशन आफिस है, वह कृष्णमूर्ति हुड्डा के सरकारी आवास में है। उस वक्त कृष्ण मूर्ति हुड्डा का और चंडीगढ का क्या मेल था, यह आपको गलत बताया गया है। इस पर मैं बाद में आना चाहूंगा। मैं बिजली की चर्चा कर रहा

या। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की इतनी बुरी हालत हो गई है कि जिस तरीके से अब बिजली के रेट बढ़ाये जा रहे है, जिसकी वजह से उपभोक्ता इस बात के लिये विवश हो जाएगा कि बिजली के बिना भी गुजारा करे। आज घरेलू मीटर की सिक्यूरिटी के रेट 300 रुपये कर दिए हैं। अगर कोई आदमी कमर्शियल मीटर लगवाना चाहे तो उसके लिये 500 रुपये सिक्योरिटो है। जबकि वह खुद खरीद कर लगाए और अगर एच० एस० ई० बी ० का मीटर लेना चाहे तो उसके लिये एक हजार रुपए सिक्योरिटो देनी पड़ेगी।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर सर, मैंने गवर्नर ऐड्रसं पर भी आपसे अर्ज की थी और आज भी करुंगा कि हमारे 65 मैम्बर हैं और इनके 17 हैं। पिछली बार गवर्नर एडैरस पर हमारे 6 आदमी बोलने चाहिए है लेकिन 3 बोल सके। टोटल टाईम अलोटमैंट में 90 में से 17 प्रतिशत इनको मिलना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक घंटे से ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, फिर दूसरे बोलना चाहेंगे। जितना इनका टाईम बनता है, उससे फालतू न दिया जाए।

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, ये तो आपके हाथ की बात है। हाउस को एक हफ्ता और बढ़ा लें। मैम्बर यहां अश्वनी बात कहने के लिये ही आए हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बजट सें अलग जाकर कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हाउस का समय बर्बाद न हो। वैसे चौधरी बंसी लाल जी. का सुझाव ठीक है कि हमें तो साल में 50 दिन ही मिलते हैं, ये तो 5 साल तक ..... करते है, इसलिये हाउस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ये बड़े बलंगबांग दावे करते हैं। आज इनकी बिजली की यह स्थिति है कि जो थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, उनमें पानीपत के चारों यूनिट बेकार पड़े हैं। दावे किए जा रहे हैं कि हम हिसार में एक हजार मैगावाट का थर्मल पावर प्रोजैक्ट लगाने जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री एक तरफ तो कहते हैं कि इस प्रोसैस में 5 साल लगते हैं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह देते हैं कि वे छह महीने में तैयार कर देंगे। मुख्य मन्त्री को शायद इस बात का ध्यान नहीं होगा कि आठवी पांच साला योजना में हिसार के थर्मल पावर प्लांट का तो जिक्र है ही नहीं, थापके यमुना नगर के सुपर पावर थर्मल प्लांट का भी जिक्र नहीं है, वह भी नहीं बन पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह करते हैं, ये कैसे बना पाएंगे? कहते हैं बताएंगे, कैसे बताएंगे? मैं तथ्य पर आधारित बात करता हूं, ये कहते हैं कि हम बताकर काम चलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यह कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर बीच में बोलना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि बाकायदा वह सब जगह से

क्लीयर हो चुका है। हिसार का एम० ओ० यू० साइन हो चुका है। बिजली बनने में पांच साल लगते हैं मैंने यह कहा है आपका राज पौने चार साल जा। क्या आपने एक भी थर्मल प्लांट की आधारशिला रखकर चालू किया है? पांच साल तो मैं खुद कहता रहा हूं। बिजली पैदा होने में पांच साल लगते हैं, आपने क्या किया यह बता दें? यमुना थर्मल प्लांट कभी का बन जाता हमारे वक्त में हमने जमीन एक्वायर की थी लेकिन आपने एन० टी ० पी ० सी ० को देकर उसका सत्यानाश कर दिया।

चौधरी ओम प्रकाश चोटलाः अध्यक्ष महोदय, लोडर आफ दि हाउस पूछ रहे हैं इसलिये मैं इनको बताना चाहता हूं कि हिसार थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला हमारी सरकार के समय में रखी गई थी। यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का सारा काम हमारी सरकार के वक्त में शुरु हुआ था। भूमि पूजन भी हो गया था और उसमें सिविल वर्कस भी सारा हो गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आधारशिला हम रखते हैं और उद्घाटन का अवसर इनको मिल जाता है। ये बताएं तो सही, थर्मल पावर प्लांट की. बात तो छोड़िए किसी छोटी से छोटी डिसपैंसरी की आधार शिला भी, इन्होंने पीने तीन साल के राज में बही रखी हो, तो बताएं? फरीदाबाद का 800 मैगावाट का गैस बेस्ड प्रोजैक्ट की ईयर मार्किग भी हमारी सरकार के वक्त में हुई थे।। यह तो रिकार्ड की बात है। क्या इससे हम लोग मुनकर होने का या इससे भागने का

प्रयास कर सकते हैं? लेकिन यह तो समझते हैं कि किसी तरीके से टाईम निकाल लें और इनकी .....

12.00 बजे

श्री अध्यक्षः यह जो इन्होंने ठग्गी वाली बात कहीं है, यह रिकार्ड न की जाए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि सुपर पावर थर्मल प्लांट जो यमुना नगर का है, हमने तो उसकी कंस्ट्रक्शन करायी है लेकिन इन्होंने उसमें दरख्त लगाने का काम किया है। यह एक अच्छी बात है, कम से कम वहां पर दरख्त लगने से पर्यावरण तो ठीक होगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी दोहरी नीति है। एक हमारे हाउस के सम्मानित सदस्य हैं: श्री सुरेन्द्र कुमार मदान। उस सम्मानित सदस्य की मां के नाम से 44 एकड़ भूमि कैथल की अफगान पट्टी दी जाती है। मन्त्री महोदय खुद वन महोत्सव के लिये वहां पर दस्ख्त लगाते हैं उस महिला के नाम जमीन दी गयी जिसका पीढ़ियों से खेती करने का धन्धा हो नहीं है। यह मेरे या आपके नाम जमीन नहीं है बल्कि ऐसी महिला के नाम है जिसने कभी खेती की ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह दरख्त उखाड दिये गये। एक तरफ दरख्त लगाते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको उखाड़ देते

लोक सम्पर्क राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान): अध्यक्ष महोदय, एक बात तो चौटाला साहब ने यह कही कि 44

एकड़ जमीन है। वह 44 एकड जमीन नहीं है 44 कनाल जमीन है। मेरे पास सारा रिकार्ड है। बाकायदा दो साल के लिये 19/11 को पंचायत ने आक्शन करने के लिये रैज्योल्शन पास किया है। वह जमीन 17000 रुपये में भै रे परिवार ने ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखबारों में भी इसकी एडवर्टाईजमैंट की गयी और मुनादी भी हुई है। अखबार अग, देखना चाहें तो वह अखबार मेरे पास है, यह देख लें। मेरे पास सध कुछ हैं। यह जमीन 17 हजार रुपये में दो साल के लिये ली है। अगर इनको एतराज है तो मेंरे 17,000 मुझे वापिस दे दें और जमीन ये ले लें। दूसरी बात यह कही गयी कि मैंने बन महोत्सव के समय वहां पर दरख्त लगाये। मैं वहां पर वन महोत्सव के समय गया था और वन महोत्सव हुआ था। वन महोत्सव उस लैड पर नहीं हुआ बल्कि उस लैंड और सड़क के बीच में जो संतरे होती हैं वहां पर फौरेर्स्ट वालों ने मेरे से पौधा लगवाया था। आप उस जगह पर जा कर देखें तो पता चलेगा कि वह जमीन कम से कम सड़क से 6 फुट नीची है। जब फलड आया तो 10–20 पौधे जो लगे थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा। पंचायत की जमीन का बिल्कुल भी ताल्लुक नही है। फिर भी अगर इनको एतराज है और यह कहते हैं कि मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई घपला किया है या हेरा फेरी की है तो यह रिकार्ड देख लें अगर ये या इनका कोई आदमी यह जमीन लेना चाहे तो मेरे 17 हजार रुपये वापिस कर दें, मैं उस जमीन को रिलीज कर देता हूं। जो मैंने पैसा वहां पर

लगाया है, वह मुझे दे दें, मैं जमीन वापिस कर दूंगा। (व्यवधान व शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस मुझे कहते हैं कि गलत बात की है। मैंने जो बात कही है, वह मैंने सौ फीसदी ठीक की है। इसमें अगर एक बात भी गलत हो तो जो सजा हाउस मुझे दगा, वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। 44 कैनाल भूमि भीरावान बाई नाम से इनकी मां के नाम 8,500 रुपये में 5 साल के लिये दी गयी है, उस जगह पर स्वयं मन्द्री महोदय बन महोत्सव में पौधा लगाकर आये थे। दरख्त तो इनके वक्त के लगे हुए हैं। अब क्योंकि मां के नाम से जमीन हो गयो इसलिये अब उसमें से वह दरख्त उखाड़े गये हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू है। अध्यक्ष महोदय, ईदगाह की जमीन भी साथ लगती है। इन्होंने तो शमशान घाट ली नहीं छोड़ा। 4 कनाल शमशान नट की जमीन भीं है। सारा रिकार्ड जब आपके सामने आयेगा तो पता चलेगा। यह कौन सी जगह को छोड़ेगे। फिर भी यह बड़ी दुखदायी बात है। मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था। अश्व चूंकि दरख्त बचि में आ गये और दरख्तों का जिक्र चल रहा था इसलिये मुझे यह बात बीच में कहनी पड़ गयी। अब मैं किस–किस के किस्से छेडूं बड़े लम्बे किस्से हैं। अगर मैं शुरू करुंगा तो उसमें बहुत समये लगेगा।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, एक मिनट के लिये बैठिए।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि वह शमशान घाट की जमीन नहीं है जबकि यह कहते हैं कि वह शमशान चाट की जमीन है। उसमें 4 कैनाल जमीन अलग है। यह कहते हैं कि मैं सब तथ्यों से बात कर रहा हूं। यह भी कहते हैं कि अगर गलत हूं तो मुझे सजा दें। यह भी सजा लें और मैं भी सजा लूंगा। दोनों बराबर हैं। अगर इसमें कोई गलती नजर आये तो या तो मैं इस्तीफा दे जाऊंगा., वरना चौटाला साहब इस्तीफा दें। मैं यह कहता हूं कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाये कि उसमें शमशान घाट की जमीन है या नही है या इसमें कोई भी इररेगुलैरिटो हुई है या उसमें एक भी अनियमितता पाई जाए तो मैं एक मिनट में इस्तीफा दे का या फिर यह इस्तीफा दे दें। इसमें कोई गलत बात नही हुई है।

श्री अध्यक्षः क्या ओपन आक्शन हुई है?

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः जी हां, बिल्कुल ओपन आक्शन हुई है। डिस्ट्रिक्ट रैवैन्यू आफिसर्ज वहां मौके पर गये थे और कम से कम 70–75 आदमियों के दस्तख्त हैं। रिकार्ड यह कहता है। आप चाहें तो इसको दोबारा करवा नें। (व्यवधान व शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बता रहा था कि सारा कुछ करने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में लाईन लौसिज निरन्तर ज्यादा बढ रही हैं। हरियाणा

प्रदेश में जितने लाईन लौसिज हैं, उतने लाईन नौसिज किसी भी दूसरे प्रदेश में नही हैं यह एक रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली के रेट निरन्तर बढाते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। फ्लेट रेट पच्चीस रुपए से बढ़ाकर पचास रुपए कर दिया गया है। डौमैस्टिक बिजली पर चालीस परसैन्ट दाम बढ़ाए गए है। आठ पैसे इंधन चार्ज और बढ़ाए हैं। स्पीकर साहब, कोयले के दाम बढ़ते रहेंगे और डीजल से दाम भी बढ़ते रहेंगे तो इनका सरचार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। आखिर एक दिन यह हालत हो जाएगी कि लोग अपना मीटर कटवा देंगे क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। स्पीकर साहब, इस सरकार ने एक फरवरी से बारह परसैन्ट चार्जिज और वरा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मीटर की सिक्योरिटी की हालत यह है कि छरेलू मीटर की 85 रुपये से तीन सौ रुपये रिक्योरिटी कर दी है। कोई आदमी दुकान के लिये यानी कौमर्शियल मोटर लगाना चाहे तो पांच सो रुपया स्कियोरिटी है जबकि वह खुद खरीदकर लगाए और अगर एच० एस० ई० बी ० का मीटर लेना चाहे तो एक हजार रुपया सिक्योरिटी है। आज बिजली की स्थिति यह है कि इसकी वजह से हरियाणा का आम नागरिक अस्त व्यस्त हो गया ई। मेरा कहना गढ़ है कि इस सरकार को और कामों को छोडकर बिजली की तरफ खासतौर से तव्ज्जह देनी चाहिये जिसस प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, इस नए बजट में गरीब आदमी के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मन्त्री की तरफ से बुलन्द आवाज में यह नारा लगाया जा रहा है एक

परिवार एक रोजगार। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि एक परिवार में से एक आदमी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा लेकिन दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हर विभाग को चिट्ठी भेजो जा रही है कि कोई नई भर्ती न की जाए। स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे रोजगार देंगे। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों को रूट परमिट देंगे और उन लोगों को देंगे जो पढ़े लिखे बेकार नौजवान हैं। यह सरकार नेशनेलाइजेशन की बजाए प्राईवेटाईजेशन यानी निजीकरण करने जा पी है और इसके लिये इस सरकार ने किराए बढ़ा दिए हैं। बसों की हालत यह है कि बसों में बैठ नहीं सकते। अगर किसी तरह से बस में बैठ भी जाएं तो ठिकाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बसों में न खिड़कियां हैं और न ही ढंग की सीटें हैं ट्रांसपोर्ट कप घाटा बढ़ता जा रहा है। स्पीकर साहब, ये बेकार नौजवानों को क्या रूट परमिट देंगें, इन रूट परमिट्स के लिये खुद वजीर लड़ रहे हैं। उन नौजवानों का तो नम्बर हो नही आएगा। लाटरी सिस्टम से रूट परमिट निकाले गए लेकिन अश्व इन्होंने कैबिनिट की एक सब कमेटी बना दी है। इनको कायदे कानून का कुछ पता ही नही है जब लाटरी सिस्टम से रूट परमिट निकाले गए तो फिर वजीरों की एक सब कमेटी मुकर्रर कैसे कर दी गई। बिड होने के बाद सब कमेटी का क्या मतलब है लेकिन क्या करें वास्ता अनपढों से पढ़ गया है। हरियाणा के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस तरीके से यह सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के नाम पर लोगों को लूट रही है। पढ़े लिखे नौजवानों को

रोजगार मुहैया करने के बहाने से लोगों को लूटने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि यह सरकार प्रदेश की सम्पत्ति बेचने पर लगी हुई है। रोजगार के नाम पर प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। जहां प्रदूषण को खत्म करने व पर्यावरण के लिये पेडू लगाए जाने चाहिए थे वहां इसके उलट पेड़ो को काटा जा ग्हा है। बहुत ही बेदर्दी से पेड़ों को खत्म किया जा रहा है। स्पीकर साहब, वन मल्टी जी यहां पर बैठे हैं, इन मन्त्री जी के कोई परिचित हैं जिनका नाम शायद महिपाल है। यह तो इनको ही पता होगा कि उनके साथ इनका क्या सम्बन्ध है। उस व्यक्ति को पच्चीस सौ वृक्ष काटने का परमिट दिया और उस महानुभाव ने पच्चीस हजार पेड खैर के काट लिए। इस बारे में इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद यह पाया गया कि वह व्यक्ति दोषी है आगे की कार्यवारी के बारे में तो मन्दी जी ही बताएंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

वन मन्त्री (राव इन्द्रजीत सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर स्पीकर साहब, इंक्वायरी इस बारे में हुई और वह दोषी पाया गया। जितने पेड ऐक्सैस में काटे गए थे उसके हिसाब से दंड भरने के लिये उसे कहा गया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है।

राय इन्द्र जीत सिंह: नहीं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, जो आदमी पच्चीस हजार दरख्त काट ले जबकि उसको केवल पच्चीस सौ पेड़ काटने की इजाजत मिली हो और चि भी उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज न हो इससे खराब बात और क्या हो सकती है? सैन्ट्रल गवर्नमैंट की इंस्ट्रक्शंज है कि कोई आदमी अपने धर का पेडू भी नहीं काट सकता। इस आदमी ने इतने पेडू काट लिये और फिर भी कोई केस उसके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया, यह बड़े ताज्जुब की बात है? इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं हो सकता।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्कीका साहब, इनको समझने में कुछ दिक्कत हुई है। ये जिन पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये फौरेस्ट के दरख्त नहीं हैं। पंचायत या सोसायटी की जमीन पर ये दरख्त थे। सोसायटी ने ये सारे के सारे दरख्त एक व्यक्ति को बेच दिए जिसका नाम मिलाप सिंह है। अध्यक्ष महोदय, उस आदमी ने जो दरख्त काटे थे उनको देखने के लिये मैं खुद वहां पत्र गया था और मैंने वह मौका देखा भी था। हम तो फौरस्ट की तरफ से सिर्फ यह रेगुलेट कर सकते हैं कि यह दरख्त काटने लायक हैं या नहीं हैं। दरख्त काटने की इजाजत हेम नहीं देते। दरख्त काटने की इजाजत तो सोसायटी ने दी है, हमने नही दी। उस समय सैक्शन चार और पांच लागू नहीं थी इसलिये हम तो इस मामले में दखल नहीं दे सकते।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अष्यक्ष महोदय, उस आदमी को 2512 दरख्त काटने का परमिट दिया गया था लेकिन

उसके बदले में उसने दरख्त काटे 25 हजार। खैर हो या शीशम हो, कहीं पर भी दरख्त नहीं काटे जा सकते। इससे बड़ा क्राईम और क्या हो सकता है कि 2512 दरख्त काटने के बदले में 25 हजार दरख्त काटे गये। यह सबै सरकार की मिली भगत. के कारण हुआ। मैंने इनसे पूछा कि जिन लोगों ने यह क्राईम किया है नके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, यह देखना तो सरकार का काम है।

अध्यक्ष महोदय, जून 1993 में नम्बर एच० आर० 4—1148 का ट्रक खैर की लकड़ी ले जाता हुआ बतूर गांव में पकड़ा गया था। इसी तरह से एच० वाई० सी ०6875 नम्बर का इक लकड़ी से भरा हुआ पिंजौर पंचायत समिति के चेयरमैन का पकड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार से दरख्तों को काट कर चोरी हो रही है। जिन लोगों के ऊपर दरख्तो को काटने के गम्भीर आरोप थे, उनके खिलाफ मुकरमें दर्ज करवाये गये थे लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने कालका से अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिये सभी केसिज को विदड्रा कर लिया। आज सरकारी सम्पत्ति को इस प्रकार से बेदर्दी से लुटाया जा रहा है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है औम प्रकाश यहां पर बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलैस बातें कह रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने कह दी कि 2500 दरख्त काटने की बनाये 25 हजार दरख्त काट लिये गये। मैं

इनका यह बतलाना चाहता हूं कि पेडू सरकारी नहीं होते। पेडू प्राईवेट लोगों के होते हैं। सरकार अगा इजाजत देती है तो यह देखकर इजाजत देती है कि आया वे पेडू काटने के लायक हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है उस आदमी ने इजाजत से ज्यादा काट लिये हों। ज्योंही द्रमें इस तरह की शिकायत मिली बाकायदा हमने इसकी जांच करके उस आदमी को जुर्म किया। जो कायदे कानून के मुताबिक. हो सकता था, वह कार्यवाही की गयी है। दूसरी बात इन्होंने यह कह दी कि मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने बेटे को कालका से चुनाव जिताने के लिये जो केस दर्ज हुए थे, वे वापिस ले लिये। अध्यक्ष महोदय, हमने बाकायदा 31 दफा लोगों को पकड़ा है। उनके खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं। जो कायदे कानून के अनुसार कार्यवाही हो सकती थी, वह की गयी। यह सरकार गल्त काम करने वाले आदमी की मदद नहीं करती। यह काम तो ओम प्रकाश जी आपकी सरकार का था, हमारी सरकार का नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गन्ने के भाव की भी यहां पर बहुत चर्चा की गयी थी और मुख्य मस्ती ने हाउस में कहा था कि हम 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसानों को गन्ने का उचित भाव मिलना ही चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह ग्हा हूं कि आपके क्षेत्र में भी गन्ना पैदा होता है। हमारी सरकार के वक्त में गन्ने का भाव 24 रुपये से 49 रुपये हो गया

था। उस समय राशन की दुकानों पर चीनी 5 रुपये 85 पैसे के हिसाब से मिलती थी और आज हालत यह है कि चीनी 9.05 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन की दुकानों पर मिल रही हे। यू० पी० सरकार ने भी भाव में दो रुपये की वृद्धि की थी। हरियाणा की सदा ही एक प्रथा रही है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को गन्ने का भाव दूसरे प्रदेशों की तुलना में हमेशा ही ज्यादा मिला है। अब पहला अवसर आया है कि हरियाणा के लोगों को गन्ने का भाव कम मिला है। भाव 65 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है लेकिन आज चीनी के अनुपात से अगर आप देखेगें कि जब तक किसानों को कम से कम 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव नहीं मिलेगा तो लाभप्रद खेती नहीं हो पाएगी। इसी भाव के कारण किसानों ने अपना गन्ना पाट दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में जो मिलें मई तक चला करती थीं वह अब जनवरी में ही बन्द हो गई। अब हालात यह हो गये हैं कि इस सरकार ने हरियाणा के किसानों को गन्ने का उचित भाव नहीं दिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात कर रहे हैं? इनके वक्त में किसानों ने गन्ने का उचित भाव न मिलने के कारण गन्ना खड़ा ही जला दिया था। ये किस वक्त की बात का रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः उस समय में आप भी थे दल बदल तो आपने बाद में किया था 35 मेम्बरों को लेकर आप

बाद में दल बदल कर गये थे। (शोर) यह उस वक्त की सरकार का दुर्भाग्य था। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी बिल्कुल बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। 49 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव अगर किया है तो आज की सरकार ने किया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः यह तो रिकार्ड फी चीज है इस के लिये कोई किसी को कैसे गुमराह कर सकता है। हमारी सरकार के वक्त में गन्ने का भाव 24 रुपये से बढ़ कर 49 रुपये हुआ था आज ये गन्ने के भाव की 65 रुपये की बात कर रहे हैं जबकि चीनी के भाव को देरवते हुए गन्ने का भाव तय किया जाना चाहिए। हरियाणा के गन्ने का भाव कम दिया जाता है जबकि यू ० पी० का गन्ना महंगे दाम पर खरीदा गया है।

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, आज सारे देश में किसी ची स्टेट में 65 रुपए का भाव गन्ने का नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः आज तो आप 60 रुपए ही दे रहे हैं, आप हाउस को गुमराह क्यों कर रहे हैं? 65 रुपए का भाव अग ले साल के लिए है जिसके लिए मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी। ये तो वैसे भी घोषणा मन्त्री हैं, पता नहीं यह बात सिरे चढ़ेगी भी या नहीं। हरपाल सिंह जी आप तो भुगतभोगी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज खाद और कीड़े मार दवाइयां

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आपने काफी टाइम ले लिया है। गवर्नर एड्रैस और सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पर ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से 223 मिनट बोला गया और अपोजीशन की तरफ से 222 मिनट बोला गया। इसलिए आप अपना भाषण जल्द खत्म करें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज कोआप्रेटिव विभाग की बुरी हालत है, आप तो इससे जुड़े रहे हैं। आज हालत यह है कि हरकोफैड ने अपने मुलाजिमों को तनखाह देने के लिए हरको बैक से दस लाख रुपए लोग लिया है। हरको बैक से आज तक तनखाह देने के लिए कमी कर्जा नहीं लिया गया था और न ही तनखाह देने के लिए हरको बैंक से कर्जा लिया जा सकता है। यह केवल मात्र कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है और उसको निरन्तर चलाया जा रहा है। यही हालत कनफैड की है। उसकी कुल पूंजी पांच करोड़ रुपए की है और खर्चा दस करोड़ रुपए है। यह केवल के ०आर० पुनिया की कुर्मी को बरकरार रखने के लिए है। उसकी कुर्सी बचाने के लिए स्टेट को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। इसी तरह से इनफैड की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है जीन्द की जूतों की फैक्टरी को इन्होंने बेच दिया। उसके साथ जुड़ी हुई और टैनरीज हैं उनको भी ये बेचने के प्रयास में हैं। इसी तरह से एक लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फैडरेशन है। वहां पर इन्होंने अपनी मन्जूरे नजर का अफसर लगाया है। हमारी सरकार के वक्त में उसके खिलाफ

मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन यह सरकार आने के बाद उसके खिलाफ मुक्दमा वापिस लिया गया और उसी को वहां पर फिर बिठा दिया गया। क्या सरकार की कोई मजबूरी है कि जो प्रदेश की सम्पति को लूटता है उसी को बार बार कुर्सी पर बैठाया जाए। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं आधे घंटे के अन्दर अन्दर खत्म कर दूंगा?

श्री अध्यक्षः आपको पांच मिनट और दिए जाते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, आप तो इतने सेहतमन्द हैं, आप मिनटों में तो बात न करें बल्कि घंटों में करें। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आपने हरको बैंक का किस्सा देखलिया। हमारी सरकार के वक्त में ग्रामीण लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एफ० जी ० ओ ० की पोस्ट होती थी और उसके साथ 15 लड़के और लगाए थे। मौजूदा सरकार ने उस पोस्ट को खत्म कर दिया और नई पोस्ट प्रोजैक्ट अफसर की बना दी तथा और लड़के भर्ती कर दिए। असिसटैट ब्रांच मैनेजर की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन और आयु में रिलैक्सेशन कर दी गई. ..

श्री मनी राम केहरवालाः हरको बैंक में या कोआप्रेटिव बैंक में असिसटैंट बांच मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम यह तो जरूर ख्याल रखें कि बिला वजह हाउस का समय

खराब न हो। आप माननीय सदस्य को बताएं कि किस बात पर और कहां पर प्वायंट आफ आर्डर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वह रिलैक्सेशन इसलिए दी गई क्योंकि एक मती की बीवी को अकोमोडेट करना था एक विधायक के लड़के को अकोमोडेट करना था। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हालांकि हरको बैक के एम० डी० की दो लड़कियां अंडर मैट्रीक हैं उनको भी बैक में नौकरी दी गई है। इस बारे में इन्कवायरी हुई औप उस अधिकारी ने यह तसलीम किया कि उसने यह बेकायदगी की है। इस बारे में समय आने पर मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि इनका उनके साथ क्या विशेष रिश्ता है। उस अधिकारी को यह छूट कैसे दी गई? वह अफसर इन्कवायरी में यह तसलीम करते हैं कि उसने यह बेकायदगी की है, उसके बावजूद भी वह अधिकारी उसी पोस्ट पर है। अध्यक्ष महोदय, हरको बैंक में एक बात इससे भी ज्यादा चोट की देखी कि हरको बैक के डायरैक्टर को बैंक द्वारा कार का लोग दिया गया। उस डायरैक्टर को दो लाख से तीन लाख रुपए कार का लोन दिया गया जबकि वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी कोआप्रेटिव बैंक से, किसी भी डायरैक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता। हाउस के सम्मानित सदस्य तो कार के लिए दो लाख रुपए ले सकते हैं लेकिन बैक के डायरैक्टर ने ती न लाख रुपए कार का लोन लिया है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय हरको बैंक का चेयरमैन जगह जगह जा जा कर डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की घोषणाएं करता है और बैंक की तरफ से चौक काट काट कर भेजे जाने हैं।

श्री मनी राम केहरवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, हरको बैक के बारे में बात आई है। मैं उसका चेयरमैन हूं इसलिए सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरको बैक को जो प्रोफिट होता है, उसमें से दो परसैट चेयरमैन का डिस्किशनरी कोटा होता है। जो डिस्ट्रिक्ट का कोआप्रेटिव बैक है, उसके चेयमैरन का बैक के प्रोफिट में से एक परसैटं डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। चेयरमैन वह पैसा अपनी मर्जी से जिसको चाहे दे सकता है। एक बात माननीय सदस्य ने यह कही कि बैंक के डायरैक्टर को कार लोग दे दिया गया। इस बारे में मैं कमको बताना चाहूंगा कि हरको बैक के डायरैक्टर भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में वाइस चेयरमैन और दूसरे आफिसर्ज आते हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज वे ले सकते हैं, उसी तरह की फैसिलिटीज डायरैक्टर ले सकता है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, दो परसैंट डिस्क्रिशनरी कोटा कैसे हुआ, यह सब्जैक्ट इनका नहीं है। इस बारे में तो मुख्य मत्री जी या वित्त मन्त्री जी बताएंगे। जो बात मेरे नोटिस में आई, वह मैंने आपके समक्ष रख दी। आया यह कानून कायदे के विरुद्ध बेकायदगी की गई है या नहीं? इसी तरह से हैफेड का महकमा है जिसने पिछले साल डी ०ए ०पी ० खाद स्वयं खरीदी थी। उस खाद को खरीदने में दिल्ली की फर्म ने मुख्य मतो से मिल कर बड़े पैमाने पर सौदा किया था लेकिन हैफेड के अधिकारियों ने वह सौदा नहीं माना, तो मुख्य मन्त्री जी ने उस

अधिकारी का तबादला रातो रात कर दिया जिसने वह सौदा नहीं माना था। हैफेड के खाद खरीदने के अधिकार खत्म करके, खरीदो–फरोफ्त एक हाई पावर्ड परचेज कमेटी के सुपुर्द कर दी जिसके चेयरमैन स्वयं मुख्य मंत्री हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनको अपना जमाना याद आता है। आपको अपने स्वप्न याद आते हैं। सभी विभागों में अधिकारियों की बाकायदा हा ई पावर्ड परचेज कमेटीज बनी हुई हैं। उन कमेटीज में खरीदो फरोख्त के फैसले होते हैं। उस अधिकारी की तबादले की बात किसी और कारण से हो सकती है। जिस तरह के काम आप लोग करते थे, वैसा ही आप दूसरों को समझते हो। जैसी आप लोगों की विचारधारा होती थी, वैसी ही विचारधारा आप दूसरों के बारे में रखते हो।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप कितना समय और लेंगे?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप सभी माननीय सदस्यों से पूछेंगे तो आपको यही मालूम होगा कि सारे विधायक इस बात के समर्थक होंगे कि सभी सदस्यों का समय मुझे बोलने के लिए दिया जाए क्योंकि इनको मेरी बात दुहा रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आबकारी' तथा कराधान विभाग के बारे में जिकर करना चाहता हूं। कर–राजस्व में पिछले साल के संशोधित अनुमानों की तुलना में, वर्ष 1994– 95 के बजट

अनुमानों में, 11 परसैंट की वृद्धि हुई है। जबकि यह वृद्धि 25 से 30 परसेन्ट होनी चाहिए। इस प्रकार कहा से ये काम चलायेंगे। इन्होंने वसूली का लक्ष्य 1350 करोड़ रुपए रखा जबकि वसूली 1200 से 1250 करोड़ रुपए होने जा रही है। यानी 150 से 170 करोड़ रुपए कम वसूल होंगे। जो आपका एक्साईज विभाग पैसा अर्जित करने वाला है, अगर उसकी वसूली कम होगी तो फिर यह सरकार कैसे चल पाएगी? इस तरह से इस सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश में करों की बकायदा चोरी हो रही है। चोरी बहुत बडैं पैमाने पर सरकारी संरक्षण प्राप्त लोग कर रहे हैं। हिसार में स्वयं मुख्य मंत्री के सन–इन–ला की जो एसोशिरटिड डिस्टिलरी है, उसमें से रोजाना 8– 10 ट्रक बिना एक्साईज डयूटी अदा किए बाहर जा रहे हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक पैसे की भी शराब वहां से बगैर डयूटी दिए बाहर जा रही है तो मैं आज हो इस्तीफा दे दूगा। जब इनका राज था तो इन्होंने बाकायदा पूरी जांच पड़ताल की और उसमें एक बाल माड की भी ये कमी नहीं निकाल पाए। आप हा उस में बैठे हैं, इसलिए कम से कम हाउस में तो सही बात करनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि जब किसी को शीरा एलाट होता है तो बाकायदा उसका हिसाब रखा जाता है कि कितना शीरा अलाट हुआ और उस शीरे से कितनी शराब बनेगी। ये खुद तो बेईमान थे इसलिए दूसरों के भी बेईमान समझते हैं।

आप अपने समय में, कुछ भी उस फैक्टरी में कोई कमी नहीं निकाल पाए थे। कम से कम आप कोई बात करने से पहले अपने गिरेवान में मुंह डाल कर बात करें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की जो को–आप्रेटिब शूगर मिल है, उस में 5 लाख क्विंटल कम लीग पाया गया है। उस पर 30 लाख रुपया जुर्माना विभाग ने दिया। जहां तक आप के इस्तीफा देने की बात है, उस बारे में तो मेरे से ज्यादा चौधरी बंसी लाल जी ही बताएंगे कि आप इस्तीफा देंगे या सुसाइड करेंगे। क्योंकि आप दोनों के अपने कोई रिश्ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां पर आम काउंटर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है क्योंकि उनकी 100 गुना एक्साईज डयूटी कम है। आज कल जितने भी बड़े बड़े फैसले शराब के संबंध में होते हैं, वे सारे के सारे मुख्य मंत्री की कोठी पर होते हैं। यानी बड़े बड़े ठेकेदार मुख्य मंत्री की कोठी पर बैठकर ठेकों की बिड का फैसला करते हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में बाकायदा ठेके एलाट किए हुए थे और अपने समय में करोड़ों रुपये की गड़बड़ की थी। अगर कोई यह साबित कर दें कि आज तक मैंने किसी भी अधिकारी को, खैर, अब तो मैं सी० एम ० हूं जब मंत्री भी था कभी यह कहा हो कि फलां ठेकेदार को मदद हो

जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह बात ओन ओथ कहता हूं। ... .

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी हो रही है और उस चोरी को सरकार करवा रही है। जो अधिकारी चोरी को पकड़ता है उसको फौरन बदल दिया जाता है और जो कर्मचारी चोरी करवाता है, उसे एच० सी० एस० बनाया जाता है।

Mr. Speaker : Om Parkash Chautala Ji, your time is over.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो अधिकारी चोरी को रोकते हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। उसको यह सरकार सम्मानित करने की बजाए खुड्डे लाईन लगा देती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की चीरी अम्बाला और पंचकूला में भी हो रही है और वहां पर केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा हो मुख्य मन्त्री जी ऐसे अधिकारियों को खुड्डे लाईन की बजाए चोरी करने वालों की इन्क्रवायरी करवाएं।

Mr. Speaker : Please take your seat.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी' तो मैंने केवल 3– 4 इशू ही टच किए हैं। जो इन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं, उनको उखाड़ने का अवसर मझे मिलना चाहिए।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि आप पार्टी के मैम्बर्ज की रेशों के हिसाब से टाइम एलोट करने की मेहरबानी करें। यदि आपने 10 घण्टे का टाईम डिबेट के लिए फिक्स किया है तो 90 में से हमारे 65 सदस्यों के अनुसार हमें टाईम ऐलोट किया जाए और इनकी पार्टी के 17 मैम्बर्ज हैं इसलिए इनकी पार्टी के सदस्यों को 17 सदस्यों की रेशों के हिसाब से टाईम ऐलोट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद बोलने के लिए इतना टाईम ले लिया है, क्या इनकी पार्टी के बाकी के मैम्बर्ज टाईम नही लेंगे? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इनकी पार्टी को जितना ज्यादा टाईम एलोट होगा और जितना ज्यादा टाईम ये लेंगे वह इनकी पार्टी से टाईम में से कट जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से कानून बनाया गया था कि शीरे को प्राईवेट सैक्टर में बेचा जाए लेकिने हमारी सरकार ने आधा शीरा खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया और आधा शीरा कण्ट्रोल पर बेचने का फैसला किया। खुले बाजार में शीरा 200/– रुपए और 250/– रुपए क्विंटल पर बिक रहा है और कण्ट्रोल का शीरा सरकार द्वारा 13–14 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जा रहा है। यह सारा शीरा ऐसोशियेटिड डिस्टिलरी, हिसार को जा रहा है। हरियाणा का रिकार्ड है कि 42 से 47 प्रतिशत शीरे में एल्कोहल हाता है।

200/– रुपए क्विंटल के हिसाब से शीरा खरीद कर जो शराब बनाई जाती है, उसकी एक बोतल शराब करीब 5–6 रुपए में पड़ती है और 13– 14 रुपए क्विंटल के भाव पर जो शीरा बेचा जाता है, उससे जो शराब बनती है, वह 35–38 पैसे बोतल पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी हरियाणा की सरकारी सम्पत्ति को इस प्रकार से बांटने में लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार से अपने सन–इन–ला को शराब का किंग बनाया जा सके। इसके लिए हरियाणा की सम्पत्ति को कौड़ियों के भाव बेचा जा ग्हा है, नीलाम किया जा रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। आज इन लोगों ने प्रदेश की ऐसी हालत कर दी है जिसका कोई अन्त नहीं है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है, उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने फैसला किया है कि शीरे को डी– कण्ट्रोल कर दो। जब ठेके नीलाम होते हैं तो उनका भाव तय होता है। अगर शीरे का भाव मंहगा हो जाता है तो स्टेट कप राजस्व छट जाता है इसलिए हमने उस वक्त कहा था कि आधा शीरा तो खुला बेचा जा सकता है और आधे शीरे पर कण्ट्रोल रहना चाहिए। डी–कण्ट्रोल का जो शीरा है, वह बाजार में बिक रहा है और जे'। कण्ट्रोल का शीरा है, उसका भाव तय किया जाता है तथा फैक्टरी की कैपेसिटी के मुताबिक शीरा अलाट किया जाता है। यह किसी के घर की बात नहीं है या किसी के घर की दुकान नहीं है। किसी

के साथ ज्यादती न हो, इसके लिए भी हमने पूरा प्रबन्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, इनको तो '' के अलावा कुछ नजर नहीं आता, इनके अपने वक्त के जो मैं के कारनामे थे, वे इनको याद आते हैं। हमने चीफ मिनिस्टर के नाते किसी भी आदमी को नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया। इसलिए आगे हमने यह भी तय किया कि जो शीरा डी–कण्ट्रोल है उसका भी भाव तय होना चाहिए। जो प्राईवेट शीरा 200–250 रुपए क्विंटल बिक रहा था, हमने उसका रेट 180/– रुपए क्विंटल तय करवाया है। हमारे पड़ोस में यू०पी० का 70 प्रतिशत शीरा कण्ट्रोल पर बिकता है, फिर हम तो 50 प्रतिशत ही कण्ट्रोल पर ले रहे हैं। जो कण्ट्रोल पर ले रहे हैं, उसका भी भाव तय किया है और शराब के ठेकों पर दिया जाता है। जो शीरा शराब के लिए बेचा जा सकता है, उसका भी हमने भाव तय किया है ताकि इससे कोई गलत फायदा न उठाए। अध्यक्ष महोदय, इनको सरकार के हर काम में गड़बड़ नजर आती है। अध्यक्ष महोदय, इन्हें सिवाय गड़बड़ के कुछ नजर नहीं आता। सिवाय ..... के इन्हें और कोई बात दिखाई नहीं देती, ...। स्पीकर साहब, ... उसको बताने में घण्टे डेढ़ घण्टे का वक्त मुझे लग जाएगा। वक्त आने पर मैं इन की सारी बातें यहां पर बताऊंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसीलाल जी, क्या आप बोलना चाहते हैं। (विघ्न) औम प्रकाश जी, आपका टाईम खत्म हो गया, इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कुछ और बातें कहनी हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और ऐलोट करने की कृपा करें। (विष्य)

श्री अध्यक्ष: सवा घण्टे से ज्यादा समय आपको बोलते हुए हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पत्र बैठें। (विष्य)

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए भी अपना नाम दिया था और अब बजट पर बोलने के लिए भी आपसे समय मांगा है।

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी ने आपका नाम भेजा हुआ है, अभी आप अपनी सीट पर बैठें। औम प्रकाश जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा काम बेईमानों को सजा दिलवाने का भी रहा है, इसलिए ये भी ध्यान में रखें, समय आने पर मैं यह भी करूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, शीरे के मामले में एक व्यक्तिं विशेष को ही ज्यादा फायदा पचहुचाया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में ला– एंड–आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आज हरियाणा प्रदेश में सारा ला–एंड–आर्डर पूरी तरह से महरूम हो गया है। आए दिन अखबारों में किस्से छपते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मत। ने अपने ही क्षेत्र के बीसियों लोगों के खिलाफ टाडा के मुकदमें दर्ज ही नही करवाए बल्कि उनके परिवारों के लोगों को भी परेशान

किया। उन लोगों की फसलें बर्बाद हो नई थी। अगर मैं स्वयं वहां जाकर उनकी फसल न बंटवाता तो वे उजड़ जाते। अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट किसी की बापौती नही है। अध्यक्ष महोदय, नारनौल में जो फायरिंग हुई, उसका आप को पता है। नासिंग में जो फायरिंग हुई, उसका भी आपको पता है। नीसिंग मे तो दो किसान अपनी बात मनवाने के लित मुख्य मन्त्री के पास जा ग्हे थे। वे किसान मांगने बिजली गए थे लेकिन मुख्य मंत्री– जी ने स्वयं अपनों सभा में आदेश देकर के उनको गोलियों से मरवाया था। मुख्य मंडी जी ने बाद में यह कहा था कि वे तो शराब पी कर आपस में लड़कर मर गए थे। नरवाना चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने हाऊस में उन दोनों किसानों को दो–दो लाख रुपए कम्पनसेशन देने का फैसला किया। अगर वे दोनों बदमाश थे और आपस में लड़कर मरे तो सरकार ने उनको दो–दो लाख रुपए किस बात के दिए थे त् अध्यक्ष महोदय, कलावड के केस की चर्चा आपके सामने है। अबूब शहर मे एक ताजा ही. केस हुआ शै। वहां पर एक शादी थी उस शादी में मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार थे। वह शादी हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड के सैक्रेटरी मिस्टर जय सिंह बिश्नोई के भतीजे की' थी। उसके घर में मुख्यमंत्री का चूल्हे तक आना जाना है। मुख्यमत्री जी उसको अच्छी तरह से जानते है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या सभी बिश्नोई आपस में रिश्तेदार होते हैं, क्या सभी जाट आपस में रिश्तेदार हैं? मेरे नोटिस में जब वह बात

आई तो हमने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। वे चार मुलजिम थे। उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी दो अभी पकड़े नही गए हैं, वे भी पकड़ लिए जाएंगे। भजन लाल के राज मे अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, उसको सजा मिलेगी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक जगता नाम का आदमी नांदड़ी गांव का है। उसका नांदडी गांव की सड़क पर होटल है। उस होटल का उद्घाटन खुद मुख्य मंत्री जी करके आए। यह रिकार्ड की बात है। ये इससे कैसे भागेगे? जगते की बहन की दोहती जो है, वह भजन लाल के साले के लड़के को ब्याही हुई है। अगा ये उसको भी रिश्तेदारी नही मानेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं। वह भी उस केस में शामिल है। सवाल इस बात का नहीं है कि मुलजिम क्या है, सवाल तो इस बात का है कि जुर्म किस किस्म का है। देखने वाली तो यह बात है। किसी की ब्याह शादी में खुशियां मनाने के लिए नाचने गाने वाली बुलाई गई। उसका किडनेप किया गया, उसके साथ रेप किया गया। उस बारे में सात दिन तक केस दर्ज नही किया गया। बाद में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करवाया। इस प्रकार से आज वे लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो आज कानून के सरबरा बने बैठे हैं और फिर ये गलत बोलते हैं कि वे उनके रिश्तेदार नहीं हैं?

श्री अध्यक्षः चौटाला जी अब आप बैठ जाएं। आपका ट। ईम खत्म हो गया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं हरियाणा प्रदेश के ला–एंड–आर्डर की हालत के बारे में चार लाइनें पढ़कर बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैस ला है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ–जस्टिस ने लिखा है

"The way Mr. Bhajan Lal is functioning as Chief Minister is too bad forward. In a recent case concerning the Haryana Police, no less a person than the Chief Justice of India, was reported to have angrily observed, I do not know what is happening in this part of the country, it is a jungle law, I just cannot think that no child is safe, where no person is safe here, addressing the counsel of Haryana Government. the Chief Justice has further stated that tell your Chief Minister, tell your Chief Secretary that if this is the situation in the State of Haryana, then the Supreme Court will be forced to say that the constitutional machinery has broken down here."

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। इन परिस्थितियों में इस सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आपका टाईस हो गया है अब आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने जिस व्यक्ति का लिखा हुआ पर्चा पढा है, उस बारे में मैं बाद में कहूंगा। अगर ये न पढ़ते तो अच्छा ही होता अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो नोट पढ़कर सुनाया है, वह चौधरी हरद्वारी लाल का लिखा हुआ है। (शोर) जो आपने अभी पढ़ा है, वह हरद्वारी लाल का ही लिखा हुआ नोट है हरद्वारी लाल ने आप लोगों के बारे में जो कहा है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। मैरे पास भी हरद्वारी लाल का लिखा हुआ एक नोट है, उस ने चौधरी देवी लाल और चौधरी बंसी लाल के बारे में जो–जो लिखा है, वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इस में वैसी लाल की हथकड़ी लगीं हुई फोटो भी है। उसने देवी लाल के बारे में जो कहा है, उसका हैडिग है ''देवी लाल का असली रूप''। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने के लिए टाईम दें।

श्री अध्यक्षः आप बाद में बोल लेना।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे वारे में कहा इसलिए मुझे इनके बारे में कहना ही पडेगा। ठीक है बंसी लाल जी, मैं आपके बारे मैं नहीं कहूंगा। मैं चौधरी देवी लाल के बारे में बता देता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस किताब के अन्दर चौधरी देवी लाल जी के बारे में इस किस्म की बातें उन्होंने कही हैं कि कुछ कहा नहीं का सकता। इसमें कहा है कि देवी लाल का

असली रूप, चौटाला से चंडीगढ़ और यहां तक कह दिया कि देवी लाल से गिरा हुआ आदमी. इस देश में कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह हरद्वारी लाल की किताब में लिखा हुआ है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, हरद्वारी लाल भजनलाल जी के लिए भी एक कार्टून बना रहे हैं। (दिव्य)

चौधरी भजन लालः आप वह कार्टून दिखा देना। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने देवी ताल जी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें कहे।. हैं कि अगर मैं ज्यादा उनको कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता। (शोर. एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी देवी लाल जी इस प्रदेश के मुख्य मली और देश के उप प्रधान मंत्री तक भी रहे हैं, इसलिए इनको चौधरी देवीलाल जीं के सम्मान के खिलाफ एक शब्द भी नही कहना चाहिए और न ही कमको पार्लियामैंट्री परम्पराओं का उल्लंघन करना चाहिए। स्पीकर साहब, ये इनका उल्लंधन केवल बहुमत के बल पर कर रहे हैं जो इनके। नहीं करना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा बल्कि यह तो हरद्वारी लाल ने कह रखा है। मैं तो केवल वहीं बता रहा हूं जो उन्होंने कहा है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जो भी ओम प्रकाश जी के बारे में कह रखा है उसको तो इनको बता देना चाहिए क्योंकि वे इस सदन के मैम्बर हैं लेकिन चौधरी देवीलाल जी और हरद्वारी लाल के बारे में कमको कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वे अब इस सदन के मैंम्बर्ज नही हैं। ये उनके बारे में कह कर बेकार ही हाऊस का समय जाया कर रहे हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं कहा। चौधरी बंसी लाल जी, आप तो बहुत समझदार हैं। हरद्वारी लाल को आपने क्या क्या कहा था, वह तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अध्यक्ष महोदय, उस आदमी का नाम लेने से भी कलंक लगता है लेकिन वह लोगों के बारे में छाप दे, कुछ कहे तो क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, उसका इतिहास आपके सामने है। प्रताप सिंह कैरो तो इसे बनाने वाला था, उसको भी नहीं बख्शा। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बात से इनका क्या ताल्लुक है? आप भी यह किताब पढ लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन के करैक्टर और इतिहास के

बारे में कहने का कोई फायदा नहीं है। ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी अब आप बैठिए। अब चौधरी बंसी लाल जी बोलेंगे।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरुरी नहर का पानी है और हमारे यहां नहर के पानी. के दो सिस्टम हैं। एक भाखड़ा का और दूसरा वैस्टर्न जमुना कैनाल का। आज यमुना नदी के इलाके के जो डब्लू० जे ० सी ० के इलाके हैं, उनमें पानी बड़ी मुश्किल से आता है, 45 दिन में से कभी हफ्ता भर आए तो आए और न आए तो न आए। कई जगह 1 –2 दिन से ज्यादा पानी नहीं चलता और बहुत सी जगहों पर तो पानी पहुंचता ही नही है इसके लिए इस बजट में 14 करोड़ 82 लाख का प्रोविजन इन्होंने किया है। देखते हैं ये कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। आज तक तो डीसिल्टिंग कही नहीं हुई, आगे हो जाएगा तो देखेगे। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों करनाल में कहा कि बंसी लाल आगमैटेशनं कैनाल गलत बनाकर भिवानी ले तथा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमत्री जी को बताना चाहता हूं कि आगमैटेशन कैनाल का पानी अकेले भिवानी नहीं जाता करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, रिवाडी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों वगैरह में जाता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अकेले भिवानी ले गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि

आगमैंटेशन कैनाल तो यमुनानगर से निकलका मूनक तक आती है, उससे आगे नही जाती।

श्री अध्यक्षः करनाल, कौन से जलसे में कहा और किस जगह पर कहा?

श्री बंसी लालः करनाल में, 18 जनवरी का ट्रिब्यून है, इसमें लिखा है—

"Mr. Bhajan Lal further blamed Mr. Bansi Lal for the irrigation water crises in the northern districts of Haryana. He alleged that Mr. Bansi Lal had wrongfully constructed the augmentation canal to take water to the parched land of Bhiwani district."

अध्यक्ष महोदय, औगमैंटेशन कैनाल जिस समय बनाई गई थी, उस समय उस इलाके की कई लाख एकड़ जमीनै कल्लर हो गई थी, सेम से भर गई थी। सारी जमीन पर पटेरा ही पटेरा खड़ा था, उस जमीन को बचाया, उसमें जिप्सम वगैरह डालकर रिक्लेम किया और वह पानी आगे के जिलों को दिया। जब लीन पीरियड होता है तो मेन डब्लू० जे० सी ० बंद हो जाती है, केवल इस आगमैंटेशन कैनाल में पानी चलता है। अध्यक्ष महोदय, आगमैंटेशन कैनाल बनाने से कम से कम 700—800 क्यूसिकस पानी की बचत हुई। जिस वक्त 1976 में इंदिरा जों ने फैसला किया, उस समय मैं भी सैन्ट्रल कैबिनेट में था। मैंने इंदिरा जी से फैसला करवाया था कि हरियाणा को तो पानी मिलेगा 3.5

मिलियन एकड़ फूट और पंजाब को मिलेगा from the remaining water not exceeding 3.5 MAF. चौधरी' भजन लाल जी ने 31 दिसम्बर, 1981 को राजस्थान और पं जाब के मुख्य मंत्रियों के साथ समझौता किया जिसमें इन्होंने पजांब का 4.22 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा मान लया और हरियाणा का वही 3. 5 एम ० ए एफ० रहा। राजस्थान का 8 एम० ए० एफ० था, उसका इन्होंने 8.60 मान लिया। अद्वय क्ष महोदय, जब ईराडी ट्रीब्यूनल आया तो ईराडी ट्रिब्यूनल से हमने कहा कि सैन्ट्रल कैबिनेट में तो यह फैसला हुआ था। उन्होंने कहा कि "Mr. Bansi Lal, what can I do ? Your predecessor has already accepted in principle that Punjab will get 4.22 MAF water and you will get 3.5 MAF water. I am the judge of the Supreme Court and I have to go by the facts and the law".

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहैं रहा हूं कि भजन लाल जी ने इराडी कमीशन की जो रिपोर्ट आई, ट्रिव्यूनल की जो रिपोर्ट है वह तो बाद में आई, इन्होने उससे पहले ही यह एग्रींमैंट किया कि पंजाब का 4.22 एम ० ए० एफ० हरियाणा का 3. 5 एम० ए० एफ० माना और राजस्थान का 8 एम० ए० एफ० की बजाय 8.60 एम० ए० एफ० माना। उस एग्रीमैंट से हरियाणा को जितना नुकसान हुआ उतना किसी चीज से नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, पानी की हकीकत यह है कि पंजाब यमुना नदी में से भी पानी मांगता है, औंर भी मांगता है। इराडी ट्रिब्यूनल ने यह बात मानी है कि पंजाब में सरफेस वाटर 13.589 एम० ए० एफ० है और

ग्राउन्ड वाटर 12.3 मिलियन एकड़ फीट है। यानी पंजाब के पास कुल पानी 25.889 मिलियन एकड़ फीट है जबकि पजाब की इरीगेशन के लिए टोटल रिक्वायरमैंट 19.25 मिलियन एकड़ फीट है। कहने का मतलब यह है कि पंजाब के पास 8 मिलियन एकड़ फीट फालतू पानी है। वह बिना बात के हमारे साच धक्का कर रहा है और कोई बात नहीं है। हरियाणा में जो पानी है, सरफेस वाटर. 8.858 मिलियन एकड़ फीट है और ग्राउन्ड वाटर 4.12 मिलियन एकड़ फीट है। यानी हरियाणा का कुल अवेलेबल पानी 12.97 मिल्यिन एकड फीट बनता है जबकि इरीगेशन के लिये 16.92 मिलियन एकड़ फीट पानी की जरूरत है। हमे तो 4 मिलियन एकड़ फीट पानी की और जरूरत है और पंजाब के पास 6 मिलियन एकड़ फीट पानी सरप्लस है। इसके अलावा यमुना नदी के पानी के बारे में पंजाब वाले अब कहते हैं कि उसमें भी हमारा हिस्सा है। 10 मार्च, 1992 को पंजाब के सी ० एम० ने प्रधान मंत्री को एक लैटर लिखा है जिसमें उन्होंने रीआर्गेनाईजेशन आफ पंजाब एक्ट का हवाला दिया है और यह कहा है कि इसमें हरियाणा का इतना हिस्सा नही बनता। उन्होंने उस एक्ट को ठीक तरी के से इन्टरप्रट नही किया। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पंजाब के मुख्य मत्री रीआर्गेनाईजेशन आफ पंजाब एक्ट का हवाला तो देते हैं लेकिन वहं इसके साथ साथ यह बात भूल गये कि री प्रार्गेनाईजेशनं आफ पंजाब एक्ट की धारा 79 के तहत रोपड, हरिके और फिरोजपर के जो हैड वर्क्स है, वह हरियाणा को मिलने चाहिये। आपको पता है जब रोपड़ से पानी पाता है तो

वहां पर हमेशा गड़बड़ होती है। हमारा जो पानी है, वह पूरा नही आता। हमारा कहना यह है कि इन हैड–वर्क्स का चार्ज बी० बी० एम० बी० के पास होगा चाहिये। 1975 में जब मैं यहां पर मुख्य मंत्री था और ज्ञानी जी पंजाब के मुख्य मंत्री होते थे तब वहां से पानी रोक लियो गया था। मैंने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से शिकायत की। उन्होंने ज्ञानी जी से कहा कि इनको पानी दो तब कहीं जाकर 16,000 क्यूसिक्स की बजाये केवन 12,000 क्यूसिक्स पानी रबीं–सोईन्ग के लिये हमें मिला था। बाकी का पानी हमें नही मिला। कहने का मतलब यह कि हरियाणा सरकार को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिये कि रीआगेंनाईजेशन आफ पंजाब एक्ट को पूरी तरह से इम्पलीमैंट करायें और रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैड–वर्क्स का कन्ट्रोल बी ० बी ० एम० बी ० को दिलाये। री– आर्गेनाईजेशन आफ पंजाब एक्ट की बार–बार यह बात करते हैं। रीआर्गेनाईजेशन आफ पंजाब एक्ट के तहत तो आपने काम ही नही किया। जब बाउन्ड्री कमीशन इस एक्ट के तहत बना तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें थे। उसने यह लिखा था कि Kharar tehsil including the capital project will go to Haryana. क्या पंजाब वाले उसे बात को मानते है? पंजाब वाले तो हरियाणा के साथ धक्का कर रहे हैं। हरियाणा का हक मारना चाहते हैं। हक मारना हो नहीं चाहते, उन्होंने हक. मार रखा है। आप सदन में इस किस्म का एक रैजोल्यूशन लाक... सब पार्टीज से बात करके, 'उसे पास करें। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव पास किया जायेगा तो इससे हरियाणा सरकार के हाथ भी मजबूत

होंगे और दिल्ली की सरकार के भी हाथ मजबूत होंगे। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव की बात तो करते हैं। 1986 में इसी सदन में, जब भजन लाल मुख्य मंत्री था, तो ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था और हम आलरैडी यह पास कर चुके है। इस मामले पर उस दिन यह वाक–आउट कर गये थे। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि बाकायदा इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि एस० वाई० एल० कैनाल जल्दी बनाई जाये। इसलिये अब इसको दोबारा पेश करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः यह प्रस्ताव 20 फरवरी, 1986 को पास हुआ था।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस समय जब भजन लाल ही चीफ मिनिस्टर था और उस समय यह प्रस्ताव हम पास करके बाकायदा भेज चुके हैं।

श्री अध्यक्षः यह जोल्यूशन इस तरह से है–

"This House recommends to the State Government to approach the Central Government to immediately take over the construction of the S.Y.L. Canal in the Punjab Territory in their own hands so that the same is completed without any further delay. The delay in the construction of the said canal

has already greatly affected the economy of the State and increasing the cost of construction thereof tremendously."

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1986 में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया होगा। मैं इस बात को एडमिट करता हूं। लेकिन इसके बाद गंगा में पानी बहुत बह गया। इस बात को आठ साल हो चुके हैं। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि उस समय अपोजीशन यहां नहीं थी। हम लोग जो अपोजीशन में थे राजीव लौगोवाल समझौते पर एजए प्रोटैस्ट सारी अपोजीशन ने रिजाइन किया था और उस समय हम इत्र हाउस में पार्टीसिपेट नहीं कर ते थे। आज हम यही हैं और हम भी चाह हैं कि रेजोल्यूशन पास हो (विध्न)इन दि हैण्डज आफ सैन्टर्ल गवर्नमैंट नहीं सर। वी ० आर० ओ० से इस काम को कंगने के बारे में सैन्टर के जो आर्डर हो चुके हैं उसको ऐग्जाक्यूट करवाए। आज उस रेजोल्यूशन को पास कराने में क्या दिक्कत है। स्पींकर साहब, 1994 में क्या दिक्कत है जब आप 1984 का जिक्र करते हैं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी के पानी के बारे में समझौता 1954 में हुआ था जिसमें यह था कि दो तिहाई पानी हरियाणा का और एक तिहाई उत्तर प्रदेश को मिलेगा और यह समझौता 2004 में रिओपन होना था। चौधरी भजन लाल ने यह समझौता जज से डेढ़ साल या दो साल पहले खोलना मन्जूर कर लिया और ये हरियाणा की पानी घटवा रहे थे। लेकिन उस

वक्त राजस्थान में डा ० चन्ना रेड्डी, जो वहां के गवर्नर थे, उन्होंने दस्तखत करैंने से इन्कार कर दिया, वरना इन्होंने तो कैबिनिट का भी और दूसरों का भी हवाला दे दिया था कि हरियाणा के लिए यह हिस्टोरींकल समझौता है। पिछले सैशन में यह बात आई थी।

चौधरी भजन लालः यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई। दुबारा खुलने का कोई सवाल नहीं है। हरियाणा का दो तिहाई हिस्सा है। एक बूंद न तो कम करने की बात है और न कम होगी।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जे ० एल० एन ० कैनाल के फीडर के साथ साथ रोहतक जिले और सोनीपत जिले के गांवों में सेम आई हुई है और खास तौर से करीब पचास बावन गांव ऐसे हैं जिनमें सेम ने बहुत नुक्सान कर रखा है और खासतौर से अछेद और पहाड़ीपुर दो गांव मैंने देखे हैं, उनके घरों में दहलीज तक पानी पहुंचा हुआ है। इसके लिए डिंच ड्रेन सरकार बनाए। कलोई खास, बहौर, मालोट, गड़ी माजरा, सुनारिया, बालन्द, रिटोली, कबूलपुर और दुब्बल धन इत्यादि ऐसे बहुत से गांव हैं जिनकी हालत खराब है, मगर अछेद और पहाडीपुर की हालत खासतौर से खराब है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोहाना के इलाके के गांव हैं घनाना, बुटाना और बडौदा के बीच परमानैन्ट पानी खड़ा रहता है। बारिश के दो तीन मही ने के बाद तक भी यह पानी इन गांवों के बीच में खडा रहता है। वहां मुर्दा सड़क के किनारे जलाते हैं। वहां पर से पानी निकालने

का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए ताकि वे लोग हमेशा इस बात से नुक्सान में न रहे। अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी कह देते हे कि एस ० वाई० एल० का 95 प्रतिशत मैंने बनाया है। अध्यक्ष महोदय पिछले साल मैंने कम्पट्रोलर एण्ड औडीटर जनरल, पंजाब की' रि पोर्ट पढ़कर सुनाई थी। इनके वक्त में दो परसैन्ट लाइनिंग हुई थी। दो परसैन्ट का अगर दो सौ परसैन्ट बन जाए तो मुझे नहीं मालूम। अध्यक्ष महोदय, ये कह देते हैं कि राजीव गांधी ने यह कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ने यह बात कभी नही कही कि हरियाणा को फाजिल्का और अबोहर का इलाका मिले बगैर, इनकी कैपीटल कमने और एस ० वाई० एल० नहर कमने से पहले चंडीगढ़ पंजाब को देंगे। ऐसी बात राजीव गांधी ने कम से कम मेरे से कभी नहीं कही। अगर चौधरी भजन लाल जी को कहा हो तो मुझे पता मेही है। राजीव गांधी ने हमेशा यही कहा कि पहले हरियाणा का हक मिलेगा और उसके बाद पंजाब को चण्डीगढ़ मिलेगा।

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहरों के बारे में कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी डीसिलटिग करवा देगे उतनी जल्दी टेल पर पानी पहुंचेगा और टेल को फायदा होगा। यमुना के फ्लड का जो पानी है उसका भीं इस्तेमाल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली की हालत यह है कि 35 से 40 परसैन्ट लाइन लौसिज हैं और ये कह देते हैं कि केवल 25 परसैन्ट लाईन लासिज है। वह

दरअसल बिजली की चोरी है और नाम लगा देते हैं ऐग्रीक्लचर सैक्टर का। अध्यक्ष महोदय, हर फीडर के ऊपर रखवाली करें, हरेक फीडर के ऊपर मीटर लगाए। यह लाईन लौसिज इतने होते क्यों हैं? ये लाईन लौसिज नही हैं असल में तो यी बिजली. चोरी होती है। बिजली की चोरी जो होता है, वह ईंडस्ट्रीज में ज्यादा होती है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत के अन्दर 110—110 मे० वाट के जो थर्मल प्लांट्स हैं, वे 30 से 40 परसैन्ट के बीच में प्लांट लोड फैक्टर पर चलते हैं, उससे ज्यादा नही चलते। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार का एक थर्मल प्रोजैक्ट था पहले उससे केवल 30—31 परसैन्ट पावर पैदा होती थे। लेकिन उन्होंने एन० टी ० पी ० सी ० को वह प्रोजैक्ट सौंप दिया और गच वह 70 परसैन्ट से ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को यह सुझाव दूंगा कि पानीपत के जो थर्मल प्लांट्स हैं, उनके मेनटीनैन्स व पावर जनरेशन के लिये एन ० टी ० पी ० सी ० को दे दें ताकि 70 परसैन्ट प्लांट लोड फैक्टर पर जब हमारे प्रोजैक्ट चलेंगे तो उससे हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन धट जाएगी। आज बदरपुर का जो थर्मल प्लांट है, आज जो उसके रेट्स हैं, वह सारे हिन्दुस्तान में माने जाते हैं। वहां 1 रुपये 25 पैसे परे यूनिट बिजली का प्रोड्यूस करने पर खर्चा पड़ता है जबकि हरियाणा के अन्दर यह रेट 1.50 पैसे है। अध्यक्ष महोदय, 300 इंजीनियर्ज जो वहां बैठा रखे हैं, उनको चर बैठे ही तनख्वाहें दे दो। वे जितने ज्यादा बैठे हैं, उतना ज्यादा वे नुक्सान कर रहे है। सरकार उनको कही दूसरी जगह पर इस्तेमाल करे।

कुछ इंजीनियर्ज को वहां भेजो, जहां से कोयला आता है। वे वहां पर कोल हैड पर कोयले की इंस्पैक्शन कर लेंगे कि कोयला ठीक आता है या नही आता है। बाकी जो इंजीनियर्ज हैं उनको इस काम के लिये लगा दो कि वे देखें कि बिजली की चोरी कहां कहां और कैसे होती' है। ऐसे लोगों को पकड़े जो बिजली की चोरी कर ते हैं। मैं सरकार को एक सुझाव यह भीं दूंगा कि जितनी बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं, उनके लिये एक मीटर सड़क के किनारे लगा दो और एक मीटर उस फैक्टरी के भीतर लगा दो ताकि जो सिटीजन चाहे, वह चौक कर सके कि कौन चोरी करता है, कौन नही करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो लाइन लासिज हैं, उनका एक कारण यह भीं है कि गल्त माल खरीदा जाता है। सब–स्टैण्डर्ड चीजें खरीदी जाती थी। करन्ट ईयर में बीस हजार से ज्यादा ट्रांसफारमर जल चुके हैं। क्या कारण है कि 20 हजार ट्रांसफार्मर्ज केवल एक साल में ही जल जाएं? कोई तो वजह इसकी जरूर होगी। अगर एक साल के अन्दर 20 हजार ट्रासफार्मर्ज जल जाते है तो कितने किसानों का नुकसान होतीं है, कितनी फैक्टरियों का नुकसान होता है, कितने डोमैस्टिक कजंम्पशन वाले लोगों का नुकसान होता है? इसलिये सरकार को इस सारी खरीदारी के ऊपर चौकसी लगानी चाहिये जिससे आगे के लिये सामान ठीक खरीदा जा सके, ठीक ढंग की चीजें आए। 15 परसैन्ट से ज्यादा लाईन लासिज नही होने चाहिये। अपार 15 परसैन्ट से ज्यादा

लाईन लासिज हैं तो इससे ऐसा प्रतीत होता मैं कि सारी बिजली चोरी होती है।

श्री अध्यक्षः इस चोरी की एक वजह यह भी हो सकती है कि मीटर तो दिखा रखी है कम पावर की, मौर लगाई हुई है ज्यादा पावर की। इसी ओवर लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्ज भी ज्यादा जलते होंगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि ऐग्रीक्लचर सैक्टर में चोरी नहीं होती। वहां नारमल होती है लेकिन इडंस्ट्रीज में ज्यादा बिजली की चोरी होती है और वह जरूरत से ज्यादा होती है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि भला हुआ ट्रांसफार्मर, बिना पैसे लिये नहीं बदला जाता चाहे कितने ही दिन लग जाए, जब तक पैसा नहीं दिया जाता, काम नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार को कहूंगा कि बिजली की चोरी को रोकने के लिये अफसरों की जिम्मेवारी फिकस की जाए। जिस अफसर से इलाके में बिजली की चौरी हो, उसी की जिम्मेवारी उस इलाके के लिये फिक्स की जाए। जब वह तनख्याह लेता हैं तो उस अफसर की जिम्मेवारी भी फिकस होनी चाहिये। मैं बताता हूं कि यह जो चोरी होतीं है, यह सारी अफसरों की मिली भगत से होती है। अध्यक्ष महोदय, आगे आगे बिजली की खपत बढ़ती ही जाएगी। एक तो मैं आपके जरिये सरकार को सुझाव दूंगा कि एन० टी ० पी ० सी ० से सस्ती बिजली कहीं और नहीं मिल सकती और उनसे 500 मेगावाट का

एग्रीमैंट भी सरकार कर ले ताकि आगे बिजली की कोई दिक्कत न हो। हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, उसमें हाईडल प्रोजैक्ट्स का बड़ा ही स्कोप है, बड़ा ही पोटेंशियल है। इसलिये सरकार हिमाचल प्रदेश से बात करके वहां के प्रोजैक्ट्स आईडैन्टीफाई करके उनके साथ ऐग्रीमैंट करे ताकि भविष्य में 5,10,15 सौलों तक बिजली' में कमी न अमने पाए। मुख्य मन्त्री जी कह देते हैं कि किसान को बिजली देने में दो ऊचाई सौ करोड़ रुपए साल का नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा, गेर और पौंग से हमें एक तिहाई बिजली मिलती है यानी लगभग आठ या साढ़े आठ सौ मैगावाट बिजली मिलती है। भाखड़ा की बिजली हमें 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है और डेहर तथा पौंग से 19/20 पै से प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं मिलता। अगर हम किसान को बिजली न दें और किसान फसल पैदा न करे तो हरियाणा का नाम ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए किसान को ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें, उसको चोर बनाने की कोशिश न करें। उसके दम पर ही हरियाणा चल रहा है। अष्यक्ष महोदय, सरकार बिजली का कोई कम चार्ज नहीं कर रही है। हमारी एक तिहाई बिजली 15–20 पैसे यूनिट के बीच में आती है। आगे 1.25 रुपए में बदरपुर में पैदा होती है। अभार पानीपत में डेढ़ रुपए यूनिट भी बनती हो तो इंडस्ट्रीज से आप 2.31 रुपए पर यूनिट लेते थे और अब तो और भी रेट बढ़ा दिए हैं। फिर यह नुकसान क्यों है और कहा है, सरकार इस बात को बताए। एक चीज मैं मुख्य मन्त्री जी को कहूंगा कि वे चौक कर लें कि भाखड़ा में डेहर और पौंगका

पानी आने से पहले, रावी व्यास का पानी आने से पहले हमारा पानी 52 परसैंट था और बिजली एडहौक पर हमें 39 परसैंट दी गई थी क्योंकि उससे ज्यादा बिजली हम खर्च नहीं कर रहे थे। जितनी हम खर्च कर रहे थे, उतनी हमें अलाट हो गई। अगम अब वह कम हो गई हो तो उसकी पूर्ति दिल्ली की सरकार से करवाएं। एक तरफ हिमाचल के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि उन्होंने 1000–1100 करोड़ रुपए पंजाब और हरियाणा से लेने हैं। तों हरियाणा में तो ज्यादा बिजली आई नहीं बल्कि उसको तो अपना हिस्सा भी पूरा नही मिला। इसलिए उन्होंने अगर पैसे लेने होंगे तो पंजाब से लेने होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद कम्प लैक्स में चुनाव करवाने के लिए मुख्य मन्द्री जी ने कहा था कि जल्द करवाए जाएगे। दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं और वहां असैम्बली भी कांस्टीच्यूट हो चुकी है लेकिन फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव अभी नहीं हुए हैं।

चौधरी भजन लालः उस बारे में हम बिल ला जे है।

श्री बंसी लालः अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, गुड़गांव और फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की जमीन नीलाम हुई है या बेची गई है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की कमेटी बनाई जाए जो यह देखे कि पिछले 10– 15 सालों में गुड़गांव, फरीदाबाद तथा बाकी हरियाणा में जो पंचायतों की जमीन बेची गई है, वह किस परपज के लिए बेची गई है। कितना उसमें काम हुआ और कितना नहीं हुदा, क्या

क्या चीजें उसमें हुई हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सड्कों के बागे में कहना चाहता हूं। वैसे तो पूरी स्टेट में ही सड़कें खराब हैं लेकिन मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि यमुना नगर, कैथल, सोनिपत जिलो और विशेष रूप से खरखौदा से मडोरा के इलाके में सड़कें ज्यादा खराब हैं। इसी तरह से रिवाड़ी, रोहतक, पानीपत, जीन्द और करनाल जिलों की सडके भी खराब हैं। करनाल से आगे एक पुल पार करना पड़ता है। उस पुल पर पहुचने से पहले किसी की मोटा पूरी नहीं रहती। वह कहा पर टूट का ही पहुंचती है। एक सड़क है रिवाड़ी और रोहतक जिले में। वह कंवाली कोसली और साल्हावास तक का 29–30 किलोमीटर का टुकड़ा है। उस पर साइकिल, रिक्शा या पैदल भी आदमी नहीं चल सकता। वहां पर कच्चे में चलना पड़ता है। एक कलायत हल्के में बालू से कसान और जीन्द रोड तक दो किलोमीटर सड़क का टुकड़ा है जो बहुत खराब है। इसी तरह से रिवाड़ी मन्डी की भी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। क्षज्जर के चारों तरफ भी सड़कें टूटी पड़ी है। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरसों की फसल इस बार हमारे यहां बहुत अच्छी हुई है। हमारी स्टेट में तीन रुपए के हिसाब से इस पर मार्किट फीस ली जाती है। दो रुपए तो फीस है और एक रुपया किसी और चीज का है। तो एक बोरी पर तीस रुपए मार्किट फीस पड़ती है। दिल्ली में इस पर कोई मार्किट फेस नहीं है। इस वजह से हरियाणा के ज्यादातर किसान अपनी सरसों दिल्ली में ले जाएगे। मैं सरकार को सुझाव दूंगा जिससे राजस्थान

की सरसों भी हरियाणा प्रदेश कीं मंडियों में आएगी। अध्यक्ष महोदय, नार्थ इंडिया में तेल की सबसे बड़ी मडी हिसार की है लेकिन हिसार में तेल की फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। सरकार को उन फैक्ट्रीज की सहायता करनी चाहिए, अगर टैक्स कम करने से काम चलता हो तो टैक्स कम करें। उन फैक्ट्रीज को चलाने का प्रबन्ध किया जाए। हमारी स्टेट का अनाज, सरसों दिल्ली की मंडियों में न जाए। दिल्ली. के आस पास के किसान दिल्ली मंडी में चले जाते हैं। राजस्थान के आस पास के लोग राजस्थान की मडियों में चले जाते हैं। पंजाब के आसपास के लोग अपना अनाज ले कर पंजाब की मंडियों में चले जाते हैं क्योंकि हमारी मार्किट फीस ज्यादा है और उनकी कम है। यदि हमारे यहां मार्किट फीस उनके बराबर ही कर दी जाए तो वे लोग भी हरियाणा प्रदेश की मंडियों में अपना अनाज लाएंगे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी गुड़गांव के लिए बिल्डर्ज को बड़े लाईसैसं दे रहे हैं। वैसे तो गुडगांव सहर अढाई लाख की आबादी के लिए बना था लेकिन अथ उसकी आबादी बढ़ती जा रही है। आपने एग्रीमैंट में एक क्हाज ऐसी रख दी जिसके तहत 15 परसैंट मुनाफा हरियाणा सरकार को मिलना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में यह बताए कि बिल्डर्ज ने हरियाणा सरकार को कितना मुनाफा दिया है?

अब मैं एक बात खास करके ला एंड आर्डर के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे तो हरियाणा स्टेट में ला एंड आर्डर है ही नहीं, उसके बारे में क्या कहूंगा। हिसार में एक खास घटना खटी। 2 अक्तूबर, 1993 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके स्टैच्यू पर हार पहनाने के लिए जब लोग शहर के बीच में पहुंचे तो उनको लाठियों से मारा गया। यह ज्यादती की बात है। हिसार मुख्य मंदी जी का अपना शहर है। ये उस बारे में इन्कवायरी कर लें और जो जवाब ठीक हो वह दे दें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अब मैं लाटरीज के बारे में जिकर करना चाहूंगा। यह सरकार लम्बी अवधि की लाटरी चलाएं, हमें उसका कोई एतराज नहीं है लेकिन डेली लाटरी बूंद होनी चाहिए। वित्त मती ने कहा कि लाटरीज से साल का 19–20/– करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे गरीब आदमी लुटता है। इसमें

हर गरीब आदमी यह समझता है कि लाटरी निकल आएगी। पिछले दिनों मैं शाहबाद गया था तो उस समय शाहबाद के लोगों ने मुझे बताया कि शाहबाद में डेली लाटरी की टिकटें तीन लाख रुपए रोज की बिकती हैं और कुरूक्षेत्र में 15 लाख रुपए रोज की बिकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार डेलो लाटरी बंद कर दें और लम्बी अवधि कीं लाटरी चलाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

इस के अलावा, अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव और फरीदाबाद में माईन्ज हैं जिनमें से सलिका या पत्थर निकलता है, उनका ठेका प्राइवेट लोगों को दिया गया है। जिन लोगों को ठेका दिया गया है, उनमें से बहुत से लोग हिसार जिले के हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वे लोग हिसार के हैं या कहीं के भी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आप उन माइन्ज को नैशनेलाइज कर दें, उससे सरकार को आमदनी होगी, पूरा टैक्स आएगा। ऐसा करने से कुछ न कुछ फायदा ही' होगा, कोई नुक्सान नही होगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की बहुत सी. जगहों पर, बहुत सी जगहों तो क्या, पूरे हरियाणा प्रदेश में उसको मारूती भी कहते है, उसको जुगाडू भी कहते हैं, उसको स्काइलैब भी कहते हैं और उसके अलावा जीप, टेंकर, टैम्पो और मै टाडोर कई तरह की व्हीकल्ज नाजायज तौर पर चल रही हैं। उनको कोई बंद नही कर सकता। मैं इस बारे में सरकार को सुझाव दूंगा कि उनके बारे में कोई कानून बना कर उनको रैगुलेराइज कर दें।

श्री अध्यक्षः जिन लोगों को प्राइवेट बसिज के रूट परमिट मिलेंगे, वे इनको बंद कर देंगे।

श्री बंधी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार को सुझाव दूंगा कि आप इन सब को कानून बना कर रैगुलराइज कर दें औरे दउसे टैक्स लें सरकार को बाटा क्यों हो। जु गाड़ के ब्रेक ठीक करके उनकी बाडी ठीक करके कानून के तहत उनको रैगुलराइज कर दें। यह ठीक बात है कि आज के हालात में

जुगाडू को बंद नहीं कर सकते। यह मैं मानता हूं लेकिन उनको ठीक करके रैगुलराइज कर दें ताकि सरकार को कोई घाटा न पड़े। इसके अलावा, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमैंट की व्हीकल्ज हैं, उनका मिस्यूज बहुत होता है। उनका मिसयूज इस हद तक होता है कि जब चीफ मिनिस्टर जाए तो कई मिनिस्टर और औफिसर्ज इकट्ठे चल पड़ते हैं। चाहे मुख्य मंत्री के साहबजादे जाए' तो उनके पीछे कई सरकारी गाड़ियां चल देती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे मुख्य मती जाए, चाहे मंत्री जाए और चाहे मुख्य मंत्री का लड़का जाए, जो भी गाड़ी जाए, उसका पूल कर लो, खाली गाड़ी कोई न जाए। जिस गाड़ी में पूरी सवारी हो, वह गाड़ी जाए ताकि सरकारी गाड़ी का तेल बच जाए। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कल परसों शूगरकेन के बारे में बात हो रही थी। इन्होंने शूगरकेन की काश्त की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की कि उसकी काश्त कम क्यों हो रही है। इनके वक्त में किसानों को पर्ची नहीं मिलती है। तोलने में गडबडी होता है और फिर पेमैंट में भी गड़बड़ होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश से गन्ना लाना पडता है। करनाल में जब शूगर मिल लगा तो उस वक्त 25–30 हजार एकड़ में गन्ने की काश्त होती थी जो अश्व घट कर सिर्फ 5–10 हजार एकड ही रह गयी है। अगर आप किसानों को सहूलियत देंगे तो किसान गन्ना जरूर अधिक पैदा करेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने टूरिज्म के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मगर यह 3 करोड़ 20 लाख रुपये बहुत कम हैं, इसको बढ़ाया जानो चाहिए। हमारे कई जिले दिल्ली के नजदीक हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के आसपास टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाए जाने चाहिए। राई में जो टूरिज्म कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है यह दिल्ली के पास है। इसी प्रकार से रोहतक लेक का जो इन्फासट्रैक्चर बना हुआ है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां पर और. ज्यादा टूरिस्ट आ सकें। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म के जो कम्पलैक्स हैं, उनकी मेन्टींनैंस बहुत कमजोर है आप बेशक 10 रुपए किराया बढ़ा दें लेकिन जो पैसेंजर वहां पर आकर ठहरते हैं, उनको पूरी सहूलियत रात के। मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से अम्बाला का जो टूरिस्ट कम्पलैक्स है, उसको भीं बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि पंजाब से आने वाले यात्री रात को वहां पर आकर ठहरते हैं और. सुबह पंजाब की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इसको बढ़ाये जाने की तरफ सरकार को कदम अवश्य उठाने चाहिएं। इसी प्रकार से जो इन कम्पलैक्सों में बैड शीट्स हैं या तकिये है, वे 15—20 साल पुराने हैं, इसलिए लोग इनको लगाना पसन्द नहीं करते। ये बहुत पुराने हो गए हैं इसलिए उन सबको बदल दें। इसी प्रकार से जो तकिए और बैड शी टस है, नए खरीद कर उनको सब कम्पलैक्सिज में बराबर बराकर कैपेसिटी के हिसाव से बांट दें क्योंकि पुराने तकियों को कोई लगाना पसन्द नहीं करता। मैं सरकार का ध्यान दिलाना

चाहता हूं कि रिवाड़ी का जो रैस्ट हाउस था, उसमें डी ० सी ० का और जो कैनाल रैस्ट हाउस था, उसमें एस ० पी० का रैजिडैसं हो गया है। दूसरे जो वहां पर टूरिज्म कम्पलैक्स हैं, उसमें गर्म और ठण्डे पानी को एक साथ मिलाने का कोई प्रबन्ध नही है। वहां पर जो पानी मिलेगा वह या तो गर्म ही मिलेगा या ठण्डा ही मिलेगा। इसलिए उस कम्पलैक्स में ठण्डे और गर्म पानी को एक साथ मिलाने का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। इस बारे में मेर सरकार को सुझाव है कि स्कूल अपग्रेड करने के बारे में सरकार कोई प्रिंसिपल तय कर ले दि? इतनी' आबादी. होमी और इतने छात्र होंगे तो वहां पर प्राईमरी, मिडल या हाई स्कूल या दस जमा दो का स्कूल अपग्रेड किया जायेगा। यह बन्दर बांट खत्म कर दें और आबादी के हिसाब से तथा छात्रों की सख्या के आधार पर स्कूल अपग्रेड करने के प्रिंसिपल सरकार तय कर दे ताकि यह समस्या ही दूर हो जाये। हां, जो पिछडे इलाके हैं, जैसे शिवालिक का एरिया है, सढोरा का इलाका है या छछरोली व मुलाना जी का हल्का है वहां पर कुछ सिद्धांत तोड़ कर भी स्कूल अपग्रेड किए जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है बाकी सारे हरियाणा के लिए इस सिद्धांत के तहत ही स्कूल अपग्रेड किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अस्पतालों की खस्ता हालत की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज अस्पतालों में लोगों

के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं है। दवाईयों के लिए जो बजट में पैसा रखा राया है, वह बहुत कम है। दवाईयों कीं कीमत पहले की अपेक्षा कई गुणा बढ़ चुकी है। गरीब आदमियों को तो दवाईया मिलती ही नही जबकि इनके दाम पहले की' अपेक्षा दो तीन गुणा बढ गए हैं। इतना ही नहीं, दवाइयां मिलनी तो दूर की बात, अस्पतालों में डाक्टर ही नहीं हैं। नारनौल के हस्पताल में मैंने सूअरों को घूमते हुए देखा है। जिस समय नारनौल का अस्पताल बना, उस समय यह सबसे अच्छा बना था। अब हालत यह है कि वहां पर जो कपड़े धोने की मशीन थी, वह भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में प्राईवेट क्लीनिकों की भरमार है। अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा होगा तो प्राईवेट क्लीनिकों में कोई नहीं जाएगा। जब लोगों को सरकारी अस्पतालो में सही इलाज नहीं मिलता तो उनके पास प्राईवेट अस्पतालों में जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मजबूर हो कर वे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार को होस्पीटलों में भी सुधार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने बजट में जिक्र किया कि हमने कर्मचारियों को यह दे दिया वह दे दिया, लेकिन कर्मचारियों को क्या दिया है, यह कहीं नहीं लिखा है। इसलिए मै अनुरोध करुंगा कि जब वित्त मत्री जी जवाब दें तो इसका भी खुलासा दे दें कि कर्मचारियों को क्या दिया है और उनको क्या मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यहं कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी भी हाउस में बैठे हैं, एक सरकारी कोड ऑफ कण्डक्ट बना हुआ है। यह नियम है कि इतने

रुपयों की कीमत तक गिफ्ट, मंत्री या मुख्य मन्त्री ऊपने पास रख सकतें हैं और अगर गिफट उससे ज्यादा का हो तो वह गिफ्ट तोशाखाना में जमा करवाना होता है। अभी मैंने पिछले दिनों अखबार. में पढ़ा था कि करनाल में मुख्य मन्त्री जी को 70 हजार रुपये का शॉल भेंट किया गया है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं कि वह शॉल 70,000 रुपये का था, मैंने तो वह शॉल ओढ भी लिया है और वह पुराना भी हो गया है। इससे यह क्या करना चाहते हैं? अगर आपको चाहिये तो मैं आपको भेज देता हूं

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह शॉल तोशाखाना में जाना चाहिए था।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह तथ्य चौधरी बंसी लाल जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि करनाल में माननीय मुख्य मन्त्री जी को कोई 70,000 रुपय मूल्य का लॉल भेंट में न हीं दिया गया करनाल में ऐसी कोई बीत नहीं हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सोने का ताज, चांदी की छड़ी और चांदी. की कुर्सी आदि का तो आपने कभी जिक्र नहीं किया, आप उनका जिक्र भी तो कीजिए।

श्री बंसी लालः मैंने यह खबर अंग्रेजी के ''दि ट्रिब्यून'' अखबार में पढी थी। यह अखबार 21– 10– 1993 का था जिसके पेज–3 कॉलम–2 में यह लिखा हुआ था, आप चाहे तो इसको वहां से पढ़ सकते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 120 साल की एक वृद्धा, जिसका नाम राखी, पत्नी तुलसी राम है रायपुर रानी में मुझे मिली थी और उसने बताया कि उसको पैंशन नहीं मिल रही है,' इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि कम से कम उस वृद्धा को पैंशन तो दिलवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एन ० आर ० आई० के बारे में मुख्य मंत्री जी नें व्यान दिया कि हम उनको इनवाईट करते हैं, मगर उनको इनचाईट करने के साथ ही फेसिलिटी ज तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं फाईनैशियल इस्टीच्यूशन्ज का जिक्र करना चाहूंगा। बिल मन्त्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि ' फाईनैशियल इन्हीच्यूशन्ज का काम बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक सीनियर डैजिग्नेशन का फाईनैशियल कमिशनर जो कम से कम फाईनैशियल कमिशनर रैक का हो, को इण्डिपैडैटली इस काम पर लगा दिया जाए। जब एन ० आर ० आई० आएगा तो काम बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का जहां तक सवाल है, पिछले सैशन में भी मैंने इस सदन में कहा था कि वाटर वर्क्स में कई जगह मिट्टी बदलने वाली है, उस मिट्टी को बदला जाए, बैडस पुराने हो गए हैं और मिट्टी पुरानी पड़ गई है, उसमें कैमिकल और गन्दगी बढ़ गई है इसलिए भिवानी बैडस कें बदला जाए, नहीं तो उसका बहुत नुकसान होगा। अध्यक्ष

महोदय, भिवानी जिले में पीलिया के 1000 से अधिक केसिज डिफैक्टिव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की वजह से हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने एक्साइज एंड टैक्सेशन से एक्चुअली आमदनी 1992–93 में 676.40 करोड़ रुपये दिखाई है और फिर आपने 93–94 के बजट एस्टीमेट में प्रावधान 790 करोड़ रुपए तक किया है। अब आपने रिवाईज एस्टीमेट में 700 करोड़ रुपए दिखाए हैं। पिछले साल के मुकाबले में सेल टैक्स से आमदनी 4– 5 परसैंट बढ़ी है जबकि यह कम से कम 16– 17 परसैंट बढ़नी चाहिए थी। इस साल में 1994–95 का बजट एस्टीमेट 897 करोड़ रुपये का रखा है। अध्यक्ष महोदय पिछले साल से 4– 5 परसैंट से ज्यादा बढ़ौतरी नहीं हुई है जबकि इन्फलेशन रेट 8 परसैंट है, यह उससे भी मैच नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, अंतर' ताज ये 897 करोड़ रुपये का प्रोविजन करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि 26 परसैंट इन्क्रीज हो जाएगी। इसको आप पूरा कैसे करेंगे? आपके बजट में कोई तो मैनुप्लेशन है या आपके हिसाब में सारी ही गडबड है? मैं इनसे यह पूछता हूं कि आप ये पूरा कहां से करेगे?

अब मैं आपको गवर्नमैंट मशीनरी के मिल–यूज करने के बारे में बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के संगेरिया मण्डी में एक एफ० आई० आर० दर्ज हुई, जिसमें सी ० आई० डी ० के दो ए० एस ० आई० हैं, और भी आदमी हो सकते हैं 1 पुलिस वाले हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। इस बारे में तो हमें पता नही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक अखखबार निकलती है। उसका

नाम ''राजस्थान पत्रिका'' है। इसमें लिखा है ''हरियाणा के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और हरियाणा के कई मंत्री स्तर के कई नेता राजस्थान में जातियों के अनुरूप कार्य करने में लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी' नियमित दौरे कर रहे हैं। हथियारों की आवत–जावत बराबर बनी हुई है। '' आगे चलकर लिखा है–''अकेले कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस के हुक्मराम बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग अढाई हजार लोग हरियाणा से आ चुके हैं। उनके चुनाव की बागडोर भी इन्हीं लोगों के हाथ में है और हरियाणा के अधिकारी तोल ठोक कर कहते हैं कि यह सीट तो हमारी है। '' इससे आगे कहते हैं– ''यही हाल भानू का है। प्रति दिन दर्जनों की संख्या में हरियाणा और दिल्ली से वाहन आ रहे हैं। कई वाहनों पर नम्बर प्लेटें न होने को शिकायतें भी की जा रही हैं और कई वाहनों पर गलत नम्बर प्लेटों की शिकायत पुलिस महा निदेशक को ज्ञापन, के रूप में भी मिली हैं।'' अध्यक्ष महोदय, दोबारा इससे आगे है––''इस क्षेत्र की चुनाव सभाओं में चौधरी भजन लाल प्रमुख नेता से क्य में कमान सम्भाले हुए हैं। खैर, यह तो इनकी पार्टी का काम है, कोई बात नहीं। उनकी भाषा न केवल भड़कीली है बल्कि मर्यादाओं से भी परे दिखाई पड़ती है। उनकी चेतावनी भीं रहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीते तो इस इलाके को नहर का पानी बन्द का देगे। एक भाषण में वह यह भी कह चुके हैं कि मेरे से बड़ा गुण्डा और कौन हो सकता है? '' मुख्यमंत्री जी आप सारे काम करें,

उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर सरकारी मशीनरी का मिसयूज न करें क्योंकि ऐसा करना बहुत ही गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं पुलिस ऐसोसियेशन के बारे में कहूंगा। इस बारे में आज सवेरे भी जिक्र चल रहा था। हिन्दुस्तान में 14 स्टेटों में पुलिस ऐसोसिएशन हूँ। पुलिस की एसोसिएशन बनाने से उनमें कोई राजनीति नहीं आएगी। अगर पुलिस एसोसिएशन बनाने की आप इजाजत दे देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। उससे तो एक ही बात होगी और वह यह है कि पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं, वे अपने हकों की लडाई लड़ सकेंगे और उच्च–अधिकारी उनके खिलाफ ज्यादती नहीं कर सकेगे। अगर कोई पुलिस कर्मचारी, पुलिस कप्तान, डी ० आई० जी ० और आई० जी ० के कहने से कोई गलत काम न करे तो वे उसकी ए० सी ० आर० खराब कर देते हैं। साल में 6–6 दफा तबादले कर देते हैं। तो मेरा आपके द्वारा सरकार को सुझाव है कि पुलिस एसोसिएशन बनने की मन्जूरी दे दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री जी कों एक सुझाव और देना चाहूंगा कि बुढ़ापा पैन्शन का कानून भी पास कर दें कि हर आदमी को महीने की फलां तारीख को पैन्शन मिल जाया करेगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अमीर चन्द मक्कडः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomarrow, the 9th March, 1994. .Sh. Amir Chand Makkar will continue.

***13.30**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 9th March, 1994.)